BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

Wish You all a Very Happy New Year

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तद् लक्ष्यम्

Admission Open
For The Academic Session 2024-25
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao,
Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

मई 2024

उत्तरांचल दीप

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

पत्रिका

₹:40

तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी

मोदी के कंधे पर चुनाव कब तक?

लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने वालों को खुद से पूछना चाहिए कि वह दो या तीन बार जीत चुके हैं, लेकिन जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाए? आत्मचिंतन करने से शायद जवाब मिल जाएगा, जिस मोदी के नाम पर वो जीतते हैं वो मोदी मेहनत करता है, जिसका फल कुछ निकम्मों को भी मिलता है।

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वोकल फॉर लोकल नीति से प्रेरित
उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में
उभरता नाम

नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य
उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास
जूट से बने फेंसी आइटम, होम डेकोरेशन की फेंसी सामग्री, गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन लाइन उपलब्ध

VOCAL FOR लोकल

SHAKTI PURAM GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:
05946 220841, +91 9410334041
Paytm +91 9760590897

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

मासिक
उत्तरांचल दीप पत्रिका

वर्ष:7, अंक 1, मई 2024

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

10

यूपी में वोट जिहाद की इंट्री

यूपी लोकसभा चुनाव में दो नये नारे सुनाई दिए हैं, एक 'वोट जिहाद' और दूसरा 'संघी सरकार', वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद में सपा की चुनावी सभा में मुसलमानों से कहा कि इकट्ठे नहीं हुए तो 'संघी सरकार' आने वाली नस्लों को खत्म कर देगी, इसलिए अब वोट जिहाद का वक्त आ गया है।

12

विश्लेषण

भाजपा की हैट्रिक लगेगी उत्तराखंड में ?

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड में सिर्फ अपनी हाजिरी लगाई है, सिर्फ चुनाव लड़ा ...

14

चुनाव

मन से हार चुका विपक्ष ?

लोकतंत्र और संविधान बचाने की बातें वो कांग्रेसी नेता कर रहे हैं जिनसे पार्टी तक नहीं बचाई जा रही ...

16

उत्तराखंड

उत्तराखंड का हलक सूखने लगा

उत्तराखंड देश की एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन ये पहाड़ी राज्य खुद भीषण ...

उत्तराखंड

18

उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाएं

उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टीनेशन युवाओं को खींच रहे हैं, सरकार इसे बढ़ावा देती है तो न केवल सरकार को टैक्स ...

साकेत अग्रवाल

2024 में बिखर जाएंगी कांग्रेस ?

लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून को आ जाएंगे। इसके बाद क्या कांग्रेस दो गुटों में बंट जाएगी? क्या गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और जीजा रॉबर्ट वाड्रा के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर रखे हैं? प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्या राहुल गांधी से बगावत कर सकते हैं? क्या भाई - बहन और बहनोई के बीच कांग्रेस पर वर्चस्व के लिए शीतयुद्ध चल रहा है? क्या राहुल गांधी एंड कंपनी प्रियंका गांधी वाड्रा को पॉलिटिकल पावर नहीं देना चाहती? ऐसे तमाम सवालों को लेकर राजनीति के जानकारों के बीच बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गांधी परिवार को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर दो धड़ों में बंट जाएगी। गांधी परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं उन्हें कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। इसके पीछे आचार्य प्रमोद कृष्णम के तर्क हैं कि राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी घर में चूल्हा संभालें और मां सोनिया गांधी की सेवा करें। शायद इसलिए चाहते हुए भी प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाईं, जबकि वो लोकसभा चुनाव लड़कर संसद में कांग्रेस के पक्ष को मजबूत तरीके से रखना चाहती हैं। इसलिए ही अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने में संस्पेंस बनाया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी कि वो अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ें, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा तो अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, पोस्टर तक लगवा दिए थे, लेकिन उन्हें अमेठी से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ कांग्रेस में साजिश हो रही है? क्योंकि प्रियंका, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के खिलाफ थी। उन्होंने कांग्रेस के भीतर आवाज उठाई थी कि निमंत्रण ठुकराने से पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। प्रियंका फरवरी में यूपी के संभल में हुए कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम में भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीएम नरेंद्र मोदी थे। प्रियंका गांधी, भाई के सामने कम बोलती है, जब बोलती हैं तो मुखर होकर बोलती है, इसलिए राहुल के सलाहकारों को प्रियंका पसंद नहीं हैं।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलासा किया कि प्रियंका के जो करीब रहा उसे या तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी या उसे हासिये पर धकेल दिया गया। इनमें सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद आदि ऐसे नाम हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं या अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, इनमें बहुत से कांग्रेसी प्रियंका गांधी के समर्थक है, लेकिन राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तो राहुल गांधी भी भागे-भागे फिर रहे हैं। वो अमेठी छोड़ पहले वायनाड और अब रायबरेली भागे हैं। सवाल ये है कि रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से राहुल जीते तो फिर एक सीट छोड़ कर भागेंगे। इसलिए सवाल ये भी है कि जब अमेठी हारे थे तब वायनाड ने इज्जत बचाई थी। लिहाजा वायनाड छोड़ते हैं तो यह वहां के मतदाताओं के साथ धोखा होगा और यदि रायबरेली छोड़ेंगे तो यहां के मतदाता खुद को ठगा महसूस करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं। वो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, उनका निष्कासन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो कांग्रेस में रहते हुए अयोध्या में श्रीराम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। वो कांग्रेस के उन नेताओं को नसीहत देते रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगते हैं। कई मौकों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मन से प्रशंसा भी की थी। निष्कासन से ठीक पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम यूपी के संभल जिले में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने गए थे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर कायर तो नहीं कहा पर, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले को डर से जरूर जोड़ा। यानी जो राहुल गांधी कहा करते थे कि डरो मत, आज वही राहुल गांधी डरे-डरे से हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह लगता था कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं, लेकिन अब इससे यह मैसेज गया है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर भाग गए। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब गांधी परिवार के किसी सदस्य ने अपनी कर्मभूमि से पलायन किया है। क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी ही नहीं हारे बल्कि गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली हार के बाद भी नहीं छोड़ी। संजय गांधी भी चुनाव हारे, लेकिन सीट नहीं छोड़ी, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारीं, लेकिन सीट नहीं छोड़ी। यह पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने सीट छोड़ दी है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या राहुल का रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला आत्मघाती सिद्ध होगा? क्योंकि जब राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे, तो कहते थे डरो मत, लड़ो, पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे, कि डरो मत, मीडिया से कहते थे कि डरो मत, जो व्यक्ति दूसरों से कहता था कि डरो मत, वो खुद क्यों डरा-डरा सा है। राहुल गांधी खुद को पीएम का दावेदार मानते हैं फिर भी भाजपा की स्मृति ईरानी से डर गए? अब जब अमेठी से नहीं लड़ना था, तो देश की सबसे हाटॉ सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ लेते क्योंकि वो बात-बात पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते रहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं, मेरी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। खैर राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे कोई रणनीति नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक साजिश है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा को पॉलिटिकल पावर से वंचित रखना। ●

बदलेगी पीएचडी की सूरत-सीरत

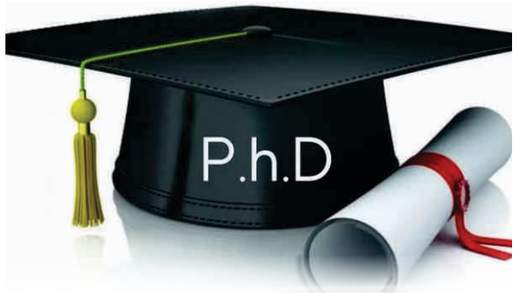

2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अब केवल एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-नेट देनी होगी, यह नई शिक्षा नीति-2020 का अहम हिस्सा है, उच्च शिक्षा के शीर्ष संस्थान के इस कदम से देश भर में कई प्रवेश परीक्षाओं की अब जरूरत नहीं रहेगी।

प्रो.श्याम सुंदर भाटिया
टीएमयू

भारत में पीएचडी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन-यूजीसी से बड़ी जानकारी आ रही है या यूं कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए, पीएचडी करके भविष्य में अपने नाम के आगे डॉक्टर जैसे सम्मानित शब्द की चाहत रखने वालों के लिए यूजीसी ने अब नई संजीवनी से लबरेज नायाब तोहफा दिया है। 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अब केवल एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-नेट देनी होगी। यह नई शिक्षा नीति-2020 का अहम हिस्सा है। उच्च शिक्षा के शीर्ष संस्थान के इस कदम से देश भर में कई प्रवेश परीक्षाओं की अब जरूरत नहीं रहेगी। नेट परीक्षा प्रावधानों की समीक्षा के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यूजीसी की हाल ही में हुई 578वीं बैठक के दौरान इस बड़े बदलाव को हरी झंडी दे दी गई है। यूजीसी ने इसे जून 2024 से ही क्रियान्वित करने का ऐलान भी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एनईपी-2020 को लागू करने की सिफारिशों के संग केंद्र सरकार ने गैर जरूरी बताते हुए एमफिल की विदाई कर दी थी। यूजीसी के इस फैसले के बाद देशभर में अब किसी भी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमफिल की डिग्री नहीं दी और ली जा रही है। नेट परीक्षा अब तक मुख्य रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप-जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्तियों की पात्रता तय करने के लिए होती रही है। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट परीक्षा ही पात्रता होगी। पीएचडी में एडमिशन के लिए रिजल्ट उम्मीदवार के प्राप्त अंकों के साथ परसेंटाइल में जारी किया जाएगा। बताते चलें कि अभी तक पीएचडी रेग्यूलेशन एक्ट-2022 के तहत जेआरएफ पास स्टुडेंट्स को ही इंटरव्यू बेस पर पीएचडी में एडमिशन मिलता रहा है। लेकिन अब नए बदलाव के साथ यूजीसी की ओर से नए परिवर्तन की गाइडलाइन्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

क्या हैं नए नियम?

नए नियमों के मुताबिक जून-2024 से यूजीसी नेट योग्य उम्मीदवारों की पात्रता तीन श्रेणियों में होगी। एक- जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के संग-संग पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। दो-जो आवेदक जेआरएफ के बिना पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन सहायक प्रोफेसर नियुक्ति चाहते हैं। तीन-वे पूरी तरह से पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के हकदार होंगे। नेट के माध्यम से पीएचडी प्रवेश के लिए दो और तीन श्रेणी में नेट स्कोर का वेटेज 70 प्रतिशत होगा, जबकि 30 प्रतिशत वेटेज इंटरव्यू के जरिए दिया जाएगा। यह इंटरव्यू आवेदक उम्मीदवार की चयनित यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। यदि आवेदक ने इस समयावधि में प्रवेश नहीं लिया तो इसके लिए वह अयोग्य हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी को पुनः नेट परीक्षा देनी होगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान का जुड़ाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोध के प्रति समर्पण दर्शाता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वैश्विक रैंकिंग को लेकर कितनी संजीदा है। 2021-22 में पांच साल के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन-एनआरएफ का बजट 50 हजार करोड़ आवंटित हो चुका है। उम्मीद है कि शोध के क्षेत्र में तरक्की की नई राहें निकलेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि छात्रों को रिसर्च और इन्नोवेशन को जीने का तरीका बनाना होगा।

बदलाव से देश में शैक्षणिक माहौल बनेगा

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में शिरकत कर रहे छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि समाज में नवाचार को अब अधिक स्वीकृति मिल रही है। जय अनुसंधान का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा था कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागी इसके ध्वजवाहक हैं। जाने-माने शिक्षाविद प्रो.यशपाल का मानना रहा है, जिन शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो न तो शिक्षा का भला कर पाती हैं और न ही समाज का। इसलिए आत्मविश्वास से लबरेज यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार कहते हैं कि यह बदलाव निःसंदेह देश में शैक्षणिक खोज और विद्वतापूर्ण उन्नति के लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में अनमोल योगदान देगा। प्रो. कुमार कहते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए अगले सप्ताह से मूर्त रूप देने जा रही है। इससे न केवल छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की ओर से आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी से राहत मिलेगी, बल्कि इससे परीक्षा संसाधन और खर्चों का बोझ भी कम होगा। शिक्षाविद मानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा से न केवल आपके अंकों के आधार पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के द्वार खुलेंगे, बल्कि आपको आकर्षक छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता भी सुगम हो जाएगा। अब आईआईटी, आईआईएम या दीगर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए अगल से इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देश में अब वन पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम फार्मूला लागू हो गया है।

भारत भी अनुसंधान देशों में

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अनुसंधान देशों में से एक है। क्यूएस रिसर्च वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारत के अनुसंधान उत्पादन में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वैश्विक औसत के दो गुना से भी अधिक है, जबकि वैश्विक औसत 22 प्रतिशत है। इसमें भारत के 66 विश्वविद्यालयों को शुमार किया गया था। चीन, अमेरिका और यूके के बाद दुनिया में भारत का रिसर्च चौथे पायदान पर है। क्यूएस के मुताबिक भारत ने 2017 से 2022 के बीच 1.3 मिलियन अकादमिक पेपर्स तैयार किए हैं। इस अवधि में करीब 15 प्रतिशत रिसर्च पेपर शीर्ष जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। यह खुलासा क्यूएस ने अपनी रैंकिंग में किया है। अकादमिक पेपर्स में यूनाइटेड किंगडम का आंकडा 1.4 मिलियन है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, भारत निकट भविष्य में यूके को पीछे छोड़ देगा। यह बात दीगर है, साइटेशंस में 8.9 मिलियन उद्धरणों के साथ भारत की नौवीं रैंक है। क्यूएस रिसर्च वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने यह रैंकिंग निर्धारित करने के लिए भारत समेत दुनिया के 93 देशों के 1300 से अधिक विश्वविद्यालयों के डेटा का विश्लेषण किया है। रैंकिंग निर्धारण में अनुसंधान आउटपुट, शिक्षण गुणवत्ता और नियोक्ता प्रतिष्ठा जैसे कारक शामिल थे। भारत में अनुसंधान का सबसे प्रचुर क्षेत्र इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है। इसके बाद प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा का स्थान आता है। भारत दो या अधिक मुल्कों के साथ अपने अनुसंधान उत्पादन का 19 प्रतिशत उत्पादन करता है। यह वैश्विक औसत पर 21 प्रतिशत है। इसमें कोई शक नहीं है, भारत दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाला रिसर्च हब बन चुका है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

सुर्खियां

कांग्रेस डूबता जहाज

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि 2024 के बाद कांग्रेस डायनासोर की तरह धरती से गायब हो जाएगी। गुजरात के भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बच्चे अब से दस साल बाद कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए राजनाथ सिंह ने राजाओं और महाराजाओं पर कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि राजघरानों ने लोगों की जमीन नहीं हड़पी, बल्कि अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय की पेशकश की। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे राजा हुआ करते थे जो लोगों की जमीन हड़प लेते थे। जहां तक हमारे देश के राजाओं का सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री की एक अपील पर सभी ने अपनी रियासतों का विलय भारत में किया था। देश में जो माहौल है उससे मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के काम के कारण अब जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है। मैं जब अन्य देशों का दौरा करता हूं, तो मुझे भारत के बारे में लोगों के व्यवहार और उनके दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में यह धारणा बन गई है कि भारत कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो वह देश से गरीबी हटा देंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह भी यही कहते थे, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं हटाई, बल्कि गरीब हटा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है उसे दुनिया की कोई ताकत डूबने से बचा नहीं सकती। उन्होंने गांधीजी का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में उनकी बात नहीं मानी। किंतु अब जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस का सफाया होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है और वह खुद को 'दीमक' की तरह चट कर रही है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। कांग्रेस ने कई सीटों पर या तो अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जहां उतारे वहां से कई प्रत्याशी चुनावी मुकाबला छोड़ गए हैं। ग्वालियर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस से अपना 18 साल पुराना नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ●

आग बुझाने की कोशिश तो करो

उत्तराखंड सरकार के द्वारा चीड़ की सूखी पत्तियों को 50 रुपये किलो में खरीदने का निर्णय स्वागत योग्य है। अधिक आय के लिए ग्रामीण इसे इकट्ठा करेंगे तो यह जंगल की आग को नियंत्रित करने में भी सहायक होगा। पर्वतीय क्षेत्र में पिछले करीब एक महीने से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। यहां आग लगने के पीछे कारण आदमी ही होते हैं। कुछ अनजाने में आग लगाते हैं तो कुछ जानबूझकर। एक बार आग लग जाए तो पिरूल यानी चीड़ की सूखी पत्तियां इसे तेजी से फैलाने का काम करती है। क्योंकि इनमें काफी मात्रा में ज्वलनशील तेल होता है जिसके कारण आग बहुत जल्दी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। सरकार ने आग पर काबू पाने और उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी तय करने के लिए पहले पिरूल की कीमत 3 रुपये प्रतिकिलो निर्धारित की थी, लिहाजा लोग इसे इकट्ठा करने में रुचि नहीं लेते थे। अब 50 रुपये किलो खरीद मूल्य होने पर उम्मीद है इसका अधिक उठान होगा तो प्रत्यक्ष रूप से आग पर नियंत्रण होने की संभावना बढ़ेगी। आग लगाने वालों के विरुद्ध भी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है यह अच्छी पहल है। पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष पंत का मानना है कि वनों में आग लगाने वालों पर हत्या जैसी संगीन धारा के तक अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पेड़-पौधों और वन्य जीवों में भी जीवन होता है। जंगल की आग में हजारों छोटे बड़े वन्य जीव और पक्षी व उनके बच्चे जलकर मर जाते हैं। इन सबकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि औरों के लिए भी मिसाल बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरूल के दाम बढ़ाने का एतिहासिक निर्णय लेकर एक तरह से जीवों की रक्षा करने का काम किया है। लेकिन इस योजना की उन्हें खुद मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी हो वरना लालफीताशाही के कारण पिरूल की फाइल सचिवालय में ही घूमती रह जाएगी और फायर सीजन बीत जाएगा। डॉ. आशुतोष पंत पब्लिक से अपील की है कि वो जहां भी जंगलों में आग लगी देखें उसे बुझाने का प्रयास करें। यह ना समझें कि यह वन विभाग का ही काम है। उनकी तो ड्यूटी है ही पर उनके पास स्टाफ सीमित है। इसलिए सब जगह उनका पहुंच पाना संभव नहीं है। जब तक उन्हें सूचना मिलेगी तब देर भी हो सकती है। ●

जिंदगी क्या है?

नीरू जग्गी
दरियागंज दिल्ली

एक कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पांच अंधों और एक हाथी की। अंधे बेचारे हाथी को छू-छूकर अलग-अलग तरीके से उसके आकार का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कान छूनकर लगता है ये पंखे जैसा है। पैर छूकर लगता है जैसे खंबा है। पूंछ छूकर अहसास होता है कि ये कोई रस्सी है। इसी तरह जिंदगी भी है। अपने अपने अनुभव के आधार पर कोई उसे खुशहाल अथवा सुखी बताता है तो कोई उसे दुखो भरी बताता है। परंतु यह लेख पढ़ने के बाद आप कभी भी अपनी जिंदगी से दुखी नहीं होंगे। मनुष्य की एक समस्या यह है कि वह बहुत शीघ्र ही दूसरों की बातों में आकर हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और नकारात्मक सोच के कारण गमगीन हो जाता है। वह इसी सोच का शिकार हो जाता है कि बाकी लोग तो मजे में जिंदगी जी रहे हैं जबकि वह स्वयं दुखों से ग्रसित है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। आज हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नकली चेहरा लगाकर घूम रहा है। जी हां... बिलकुल सही पढ़ा आपने। आज की एक घटना बताती हूं कि एक जेठानी जो बहुत अच्छे सरकारी पद पर कार्यरत है और भारी भरकम तनख्वाह पा रही है। वो अपनी देवरानी का हाल-चाल पूछने उसके घर आई है। जबकि हाल-चाल पूछना तो सिर्फ एक बहाना है। असलियत में वह अपनी देवरानी को अपनी श्रेष्ठता एवं विलासिता वाली जिंदगी की तस्वीर दिखाने आई है। चाय पीते-पीते वह देवरानी को बड़े घमंड से बताती है कि आत्मनिर्भरत होने के कारण वह जो चाहे खरीदती है, पहनती है, खाती-पीती है और रोज सज-धज कर अपनी निजी कार से दफ्तर जाती है। घर में भी मेरी ही चलती है। शुक्र है कि मुझे घर में रहकर चौका-चूल्हा संभाल कर अपनी जिंदगी नहीं बितानी पड़ती है। जो भी मन करता है आनलाइन आर्डर करके मंगा लेती हूं ऐसी है मेरी मजे की जिंदगी।

उधर देवरानी भी जेठानी के विलासिता और घमंडी लाइफस्टाइल के बारे में डींगे सुनकर फीकी और दिखावटी हंसी हंस कर अपना भी दूसरा चेहरा दिखाती है और कहती है कि नहीं ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेले ही सब काम करती हूं। ये यानी मेरे पति सुबह आफिस जाने से पहले और शाम को घर आने के बाद में मेरा हाथ भी बंटाते हैं। इतना ही नहीं रात को खाने के बाद बंटी की पढ़ाई भी देखते हैं। रोज शाम को घर आते हुए कभी समोसे तो कभी मिठाई कुछ न कुछ हमारी पसंद का जरूर लेकर आते हैं। कुछ समझ आया...? क्या हुआ होगा इसके बाद? जेठानी रास्ते भर सोचती जा रही हैं कि देवर कितना अच्छा है? मेरे पति को तो रोज ही घर आने में देर हो जाती है और खाना भी अकसर बाहर ही खाकर आते हैं। एक अरसे से हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। हमारी बेटी सुमेधा की पीएमटी में जाने की तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली इन्हें। बेटी को पढ़ाना तो दूर की बात है। मेरी देवरानी कितनी सुखी है जिसे इतना ध्यान रखने वाला और प्यार करने वाला पति मिला है। एक मैं हूं जो नीरस वैवाहिक जीवन जी रही हूं। उधर देवरानी का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। पति के आने तक ना खाना बनाया और न ही बंटी का स्कूल का बस्ता ही खोला। जो भी सोच-सोचकर दिमाग में भर रखा था पति के आते ही सब गुस्से में चिल्ला-चिल्ला कर निकाल दिया। मुझ पढ़ी लिखी को घर में बांध कर बैठा दिया है। हमेशा नौकरी को मनाकर दिया। घर की नौकरानी बना दिया है। बस घर के काम करो। बंटी को पढ़ाओ। आप भी जहां हो बस वहीं रहना। तरक्की तो होनी नहीं है आपकी। कार में तो अगले जन्म में बैठना ही नसीब होगा। देखा आपने जेठानी और देवरानी एक-दूसरे को बेहतरीन जिंदगी दिखाने के चक्कर में झूठा दिखावा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल औरतें ही ऐसा दिखावा करती हैं। पति लोग भी पीछे नहीं हैं। इनसे एक साथी बताता है कि मेरी पत्नी तो मेरी हर बात मानती है, मजाल है कि मायके भी मेरी मर्जी के बिना चली जाए। दूसरा भी डींगे हांकते हुए कहता है कि मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है। सुबह-सुबह गर्मा गरम नाश्ता, आफिस साथ ले जाने के लिए स्वादिष्ट खाना, सलाद के साथ और शाम को तो पूछो नहीं पकोड़े या चिप्स अथवा मैगी चाय के साथ पेश करती ही है। लेकिन ये हकीकत नहीं है बल्कि सच ये है कि पति देव को नाश्ता तो क्या मिलता, चाय भी उन्हें अपनी और पत्नी की खुद ही बनानी पड़ती है। अगर पत्नी को चाय नहीं मिले तो वो बिस्तर से भी नहीं उठेगी और जो एक सब्जी रोटी बनाती है वो भी भुनभुनाते हुए। मुझे आफिस जाते वक्त एक सब्जी रोटी भी बना कर नहीं देती है। शाम को खाली हाथ घर लौटने के बारे में तो ये बेचारा पति सोच भी नहीं सकता, वरना...। अब बताइए इन्होंने अपने साथियों को अपनी पत्नियों की ऐसी तस्वीर दिखाई कि वो बेचारे दुखी होकर सोचने लगे कि काश मेरी जिंदगी में ऐसी सुघड़ पत्नी होती, तो मेरी जिंदगी भी फूलों से खिल जाती। वह तो सोचकर और दुखी हो गया कि मैं तो पत्नी की मिन्नत और मनुहार ही करता रह जाता हूं कि हफ्ते में बस दो ही दिन मायके चली जाया करो। वैसे मुझे और बच्चों को तुम्हारे बिना परेशानी हो जाती है। दोनों बेचारे पति सोच रहे हैं कि वह कितना भाग्यशाली है जो सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा है। मेरी तरह नहीं जिसे लोगों के सामने खुश रहने का नाटक करना पड़ता है। जिंदगी सिर्फ पति-पत्नी की नहीं है। युवा पीढ़ी तो अपनी सुख सुविधाओं में सबसे आगे है। युवा पीढ़ी भोग विलासिता की सामग्री का उपयोग भले ही कम करें, लेकिन प्रदर्शन करने में सबसे आगे है। एक से एक बड़े और नामी रेस्टोरेंट में जाकर दोस्तों को खाना खिलाना, ब्रांडेड कपड़ों की नकल खरीदकर पहनना, पब और बार में पार्टियां देना और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोल्डकाफी स्टार्टबक्स में पीते हुए फोटो पोस्ट करना और दोस्तों को रिझाना आदि से अपनी धाक जमाने की कोशिश करना। किंतु दुर्भाग्य से कोई उनके असली चेहरे को नहीं देख पाता है कि पैसा और जेब खर्च को लेकर वे अपने माता पिता से कितना झगड़ा करते हैं। माता-पिता को ताना मारते हैं कि हमे अपने ऊपर आपकी तरह मध्यम वर्ग का ठप्पा नहीं लगाना है। मुझे समाज में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर माता-पिता पैसा देने में असमर्थता दिखाए तो क्रेडिट कार्ड उनकी मदद के लिए मौजूद रहता है। अब इन्हें कौन समझाए कि आमदनी अठ्ठनी और खर्चा रुपया है तो कल क्या होगा? इसलिए बेहतर है कि संभल जाएं और अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को समेट लें। कहीं जीवन में हर किसी से आगे निकल जाने की दौड़ में हमारी कीमती जिंदगी ही दांव न हार जाए। हर पल हर क्षण में कुछ न कुछ सकारात्मक ढूंढ कर संतोषी रहना सीखें। झूठी और बनावटी शान वाली जिंदगी से प्रभावित होने से बचें। आप अपने परिवार अपने प्रियजनों के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण हैं। एक बात और बताऊं कि खुशी वास्तविकता में ही है। मैकअप करके कोई भी स्त्री सुंदर दिख सकती है, लेकिन यह सुंदरता अस्थाई होती है। वास्तविक सुंदरता उसकी सादगी में ही झलकती है। ●

मोदी के कंधे पर चुनाव कब तक?

लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने वालों को खुद से पूछना चाहिए कि वह दो या तीन बार जीत चुके हैं, लेकिन जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाए? आत्मचिंतन करने से शायद जवाब मिल जाएगा, जिस मोदी के नाम पर वो जीतते हैं वो मोदी मेहनत करता है, जिसका फल कुछ निकम्मों को भी मिलता है।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

शह ही नहीं दुनिया देख रही है कि एक अकेला नरेंद्र मोदी कैसे सब पर भारी पड़ रहा है? इंडिया गठबंधन हो या बाकी विपक्षी दल सभी लोकसभा प्रत्याशी से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए कहा जाता है कि देश और दुनिया को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। मोदी से अपेक्षाएं हैं, मोदी से उम्मीद रहती है। लेकिन एक सच ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात पसीना न बहाएं तो भाजपा के 80 फीसदी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो सकती है। जिन सांसदों को दूसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया उनमें से 75 फीसदी प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके संसदीय क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है। बहुत से संसदीय क्षेत्र के मतदाता अपने प्रत्याशी या सांसद का नाम तक नहीं जानते। न ही कभी सांसद को अथवा लोकसभा प्रत्याशी को देखा है, लेकिन एक जनून सब के सिर चढ़ कर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही बनाना है, इसलिए 80 फीसदी सांसद सिर्फ मोदी के नाम पर और काम पर जीत कर संसद पहुंचेंगे। मोदी के नाम पर संसद पहुंचने वालों में एक गलत फहमी कॉमन होगी, वो ये कि वह तो अपने दम पर जीतकर आएं हैं। ऐसे ही माननीय अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। चुनाव जीतने के बाद न तो क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हैं और न ही सांसद विकास निधि का पैसा खर्च कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सांसद क्षेत्र में ही नहीं जाएंगे तो क्षेत्र की समस्या का उन्हें क्या पता होगा? जब समस्या ही नहीं पता तो फिर सांसद विकास निधि कैसे खर्च होगी? सांसद विकास निधि का सही और समय पर उपयोग किया जाए तो एक सांसद अपने क्षेत्र के बहुत से गांवों की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, आदर्श गांव बना सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ज्यादातर सांसदों के भीतर राजा जैसी फीलिंग जन्म ले लेती है और वो जनता से दूरी बन लेते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसीना बहाना पड़ता है। यदि सांसद खुद जमीन और जनता से जुड़े रहें तो उनकी ही लोकप्रियता बढ़ेगी, चुनाव के दिनों में उन्हें पोस्टर तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही मई-जून की गर्मी में झुलसना पड़ेगा।

बात उत्तराखंड की

उत्तराखंड की बात करें तो यहां की पांचों सीटें भाजपा की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। इनमें टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ से अजय टम्टा, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट से अजय भट्ट, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी हैं। इन सभी प्रत्याशियों की जीत होती है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। क्योंकि टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह शाही परिवार से आती है, इसलिए वो जनता के संपर्क में कम ही रहती हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी किस्मत अजमा रहे हैं। अजय बलूनी की पकड़ दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त है, इसलिए तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अजय बलूनी को भाजपा ने टिकट दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में देखा जाए तो अजय बलूनी का जनाधार इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठ कर राजनीति करते हैं। हरिद्वार से सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वो मोदी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, इसलिए पहले उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और अब जब चुनाव का मौका आया तो उनकी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। अजय भट्ट की बात की जाए तो उनकी छवि भी पब्लिक में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उनका पूरा चुनाव प्रचार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर था। चर्चा तो यहां तक है कि जहां मतदाता नाराज थे वहां अजय भट्ट ने स्वीकारा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की भावुक अपील कर अपनी जीत का रास्ता साफ कर लिया।

जिन सांसदों को दूसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया उनमें से 75 फीसदी प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है, क्योंकि उन्होंने कभी सांसद को देखा ही नहीं, वो अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते फिर भी एक जनून सबके सिर चढ़कर बोलता है कि पीएम तो नरेंद्र मोदी को ही बनाना है।

भाजपा की जीत का श्रेय

बात अल्मोड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा की जाए तो वो अपने संसदीय कार्यकाल में एक टैंकर से डिजायर व फॉर्चयूनर गाड़ी वाले हो गए हैं। 15 साल में उनकी चल-अचल संपत्ति आंधी-तूफान की गति से बढ़ी है। अजय टम्टा ने अल्मोड़ा संसदीय सीट से पहला चुनाव 2009 में लड़ा था। तब उनके पास चल संपत्ति तीन लाख रुपये थी। उस समय वाहन के नाम पर सिर्फ एक टैंकर था। हालांकि वो 2009 का चुनाव हार गए थे। इसके बाद मोदी लहर में 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। लिहाजा उनके यहां कुबेर की वर्षा होने लगी। नामांकन पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2019 में उनके पास 6,49,744 की चल संपत्ति और 37,31,375 रुपये की अचल संपत्ति थी। पत्नी सोनल टम्टा के नाम 11,59,669 की संपत्ति आ गई थी। अजय टम्टा का जनाधार होता तो 2009 का चुनाव ही नहीं हारते। इसलिए टम्टा भी मोदी के ही कंधों पर चुनाव में उतरते आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब उनकी सीएम की कुर्सी गई तब वो कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बने तो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते उनका संगठन से बेहतर रिश्ता नहीं रहा, शायद इसलिए उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को और फिर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया। अब संगठन ने ही उन्हें संसद तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ऐसे प्रत्याशियों का सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति इरानी, योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के वजनदार और दमदार स्टार प्रचारक नहीं आते तो शायद पांचों सीटों पर नतीजे चौकाने वाले होते। इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के पांचों उम्मीदवार यदि जीत दर्ज करते हैं तो इसका श्रेय उनके जनाधार को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी शीर्ष नेताओं को मिलना चाहिए। उत्तराखंड की पांचों सीट भाजपा जीतती है तो इसका श्रेय कांग्रेस को भी दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, चुनाव जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए था वो शायद नहीं लड़ा।

निम्न कोटि पर खुद को न तौले

इसमें कोई दो राय नहीं ही कि भारत को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में मौजूदा केंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है। इसलिए इस सरकार को लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में बने रहना जरूरी है। इसलिए यह नारा आम है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जनप्रतिनिधि अगर यह सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वह चुनाव जीत जाएंगे तो वह अपने आप को निम्न कोटि पर रखकर तौल रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार बनता है तो वह अपने आप से पूछे कि वह दो बार या इससे अधिक बार जीत चुका है, लेकिन अभी तक जनता के दिल में अपने लिए जगह क्यों नहीं बना पाया? शायद उसे आत्मचिंतन करने से जवाब मिल जाएगा। जिस मोदी के नाम पर वो जीत का सेहरा बांधते हैं वो मोदी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जिसका फल कुछ निकम्मों को भी मिल जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनप्रतिनिधियो के प्रति अंदरखाने काफी आक्रोश रहा, क्योंकि उसने अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को सीधा लाभ हुआ हो। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन यह लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे अहम होते हैं, ठीक है राष्ट्रीय मुद्दे होने भी चाहिए, लेकिन स्थानीय मुद्दों को कैसे छोड़ा जा सकता है, जबकि सांसदों को सांसद क्षेत्र विकास निधि मिलती है। जिससे सांसद अपने क्षेत्र का विकास सीधे करा सकता है। इसलिए स्थानीय मुद्दों पर भी प्रत्याशियों की जवाबदेही होनी चाहिए। उत्तराखंड में ठोस भू-कानून, 1950 से मूल निवास प्रमाण पत्र, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए अलग से इंसेंटिव की व्यवस्था, ऑर्गेनिक खेती और उन्नत उत्पादन को बढ़ावा देने, विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए वित्त पोषित योजनाएं होनी चाहिए। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम, मानकों में सहूलियत, नौकरियों की टर्म कंडीशन में रियायत बरती जानी चाहिए। सरकार जब कोई नीति बनाती है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसका फायदा सभी को हो। उसमें तमाम अभिलेखों या प्रमाण पत्रों को अनिवार्य करने से जनता को ही दिक्कत होती है। पहाड़ से पलायन रोकने के लिए जरूरी है कि अधिकारी भी पहाड़ में ही रहें। राजकीय कार्यालय सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में न हों, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी हों। इसके अलावा गैरसैंण में भी सरकारों को रहना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में नेताओं को हवाई यात्रा के बजाए सड़क मार्ग से जाना चाहिए, ताकि वो जमीनी हकीकत को जान सकें। उत्तराखंड राज्य को प्रकृति ने कई अनमोल तोहफों से नवाजा है, जिसको संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सच्चे मन से करना पड़ेगा, यह काम अगले 5 साल को सोचकर नहीं, बल्कि अगले कई दशकों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर दूर की दृष्टि रखनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार और राजनेताओं को मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी होगी।

- **अगर ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जनप्रतिनिधि अगर यह सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वह चुनाव जीत जाएंगे तो वह अपने आप को निम्न कोटि पर रखकर तौल रहे हैं।**
- **उत्तराखंड के पांचों उम्मीदवार जीत दर्ज कराते हैं तो इसका श्रेय उनके जनाधार को नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी और शीर्ष नेताओं को मिलना चाहिए, इसका श्रेय कांग्रेस को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, चुनाव लड़ी ही नहीं।**

उत्तराखंड में युवा जागृति

स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो उत्तराखंड में धधकते जंगल बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में हर तरफ जंगलों में आग लगी हुई है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक चारधाम के दर्शन के साथ ही खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में धुंध होने से पहाड़ नहीं दिख रहे। ऐसे में पहाड़ की जनता को चुनाव के दौरान प्रत्याशियों से स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल करने चाहिए थे। प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे पहला मुद्दा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का है। कुछ लोगों ने मजबूरी में अपनी जमीन को बेचा है तो कुछ सरकार ने बेची, कुछ ठेकेदारों ने बेची। लेकिन अब प्रदेश का युवा जाग रहा है। उसे पहाड़ के जल, जंगल और जमीन कीमत का अहसास हो रहा है। युवा कह रहा है कि विकास हो, लेकिन इसका एक दायरा भी होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए अलग और ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग मानक तय होने चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का एक मानक भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। प्रदेश का युवा यह जान चुका है कि सख्त भू कानून की आवश्यकता है। साथ ही मूल निवास का मुद्दा भी अहम है। पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। महिलाओं को आगे लाकर स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम प्रधानों को इतना जागरूक होना चाहिए कि योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाएं। अगर सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लड़ें, ताकि उनके गांव की महिलाओं के साथ प्रदेश की सभी महिलाओं का भला हो सके। पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम महिलाएं स्वयं सहायता समूह के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही महिलाएं बिना शिकायत के पारिवारिक जिम्मेदार भी निभा रही हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए छोटे-छोटे क्लीनिक भी बनाए जाने चाहिए, ताकि वो बिना किसी के सहारे के अपना इलाज कराने जा सकें।

गांवों में बसता है भारत

यह भी सच है कि भारत का 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवेश है। यही परिवेश मिलकर देवभूमि उत्तखंड बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि गांव हैं तो हम हैं, गांव हैं तो हमारी संस्कृति है। लिहाजा जब तक गांव सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। इस समय पहाड़ के गांव से पलायन की मुख्य वजह स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में पानी के प्राकृतिक स्रोत, शुद्ध हवा, जंगल और जमीन थे, जहां आप बिना रोक टोक घूम सकते थे, लेकिन समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा खत्म होने की कगार पर है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों का युवा जल, जंगल और जमीन छोड़कर शहर की तरफ भाग रहा है। उत्तराखंड में नशा भी गंभीर समस्या है। शहर में बच्चों के स्कूल बैग तक नशा पहुंच गया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में नशा कैसे पहुंच रहा है? जो आने वाले समय में गंभीर समस्या बनकर प्रदेश के युवाओं का तबाह और बर्बाद ही करेगा। युवाओं में बढ़ती नशे की तल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। युवाओं का भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नशे की गिरफ्त से बाहर लाना होगा। जनता वो ताकत है जो चाहे तो वो वोट की चोट से बड़े-बड़ों का तख्त पलट सकती है। विधायक और सांसद के पास काम करने के लिए पांच साल का समय बहुत होता है।

यूपी में वोट जिहाद की इंट्री

यूपी लोकसभा चुनाव में दो नये नारे सुनाई दिए हैं, एक 'वोट जिहाद' और दूसरा 'संघी सरकार', तरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद में सपा की चुनावी सभा में मुसलमानों से कहा कि इकट्ठे नहीं हुए तो 'संघी सरकार' आने वाली नस्लों को खत्म कर देगी, इसलिए अब वोट जिहाद का वक्त आ गया है।

पारस अमरोही
लखनऊ

पिछले चुनावों में लव जिहाद, लैंड जिहाद खूब सुनने को मिला था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से वोट जिहाद का नारा लगाया गया है, वो भी किसी मदरसा छाप ने नहीं बल्कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की भतीजी तथा समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने लगया है। मारिया आलम खान उच्चशिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। यह भाजपा विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा नहीं तो और क्या है? दलअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दो नये नारे सुनाई दिए हैं। एक 'वोट जिहाद' और दूसरा 'संघी सरकार'। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा में मुसलमानों से कहा कि अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो 'संघी सरकार' आने वाली नस्लों को खत्म कर देगी, इसलिए अब वोट जिहाद का वक्त आ गया है। सलमान खुर्शीद के सामने उनकी भतीजी ने लोगों से कहा कि जो मुसलमान भाजपा के नेताओं की सभाओं में जाते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उन सभी का हुक्का-पानी बंद होना चाहिए। इस बयान के बाद मारिया आलम खान सुर्खियों में आ गई। जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिनकी राजनीति में अपनी कोई पहचान नहीं थी उन्हें गूगल पर सर्च किया जाने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि महत्वाकांक्षी मारिया आलम खान ने क्या ये बयान सुर्खियां बटोरने के लिए दिया है? क्या अपनी पहचान बनाने के लिए दिया है? खैर कुछ भी हो वोट जिहाद पर नई बहस शुरू हो गई है। बहस इस पर भी हो रही है कि जो मुस्लिम नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं भाजपा का समर्थन सोशल मीडिया पर खुलकर कर रहे हैं उससे विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के होश उड़ गए हैं? क्योंकि अभी तक ज्यादातर विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते रहे हैं। जबकि फर्रुखाबाद में मुस्लिम समाज का एक तबका भाजपा प्रत्याशी का खुलेआम समर्थन कर रहा है।

भाजपा समर्थक मुस्लिम गद्दार

खैर अभी तक लव जिहाद और लैंड जिहाद शब्द ही सुनने और पढ़ने को मिलता था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की भी इंट्री हो गई है। ये इंट्री किसी और ने नहीं बल्कि सीनियर कांग्रेस लीडर व पूर्व केंद्रिय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने कराई है। मारिया आलम खान समाजवादी पार्टी की नेता और अच्छी खासी पढ़ी-लिखी हैं। मारिया आलम खान फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद दो बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के लिए प्रचार करने मारिया आलम खान कायमगंज पहुंची थीं। इस इलाके में मुसलमानों की संख्या काफी हैं। मारिया आलम खान ने पहले तो भाजपा उम्मीदवार मुकेश राजपूत के पक्ष में प्रचार करने वाले मुसलमानों को कौम का गद्दार बताया, उनका हुक्का पानी बंद करने की अपील की, फिर कहा कि आज मुस्लिम समुदाय पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकना है तो मुसलमानों को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। मारिया आलम खान ने सीएए-एनआरसी का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर जुल्म और ज्यादती रोकनी है, तो वोट जिहाद करना ही होगा, वोट जेहाद ही जुल्म से आजादी दिलाने का एक मात्र रास्ता है।

सलमान की भतीजी ने लोगों से कहा कि जो मुसलमान भाजपा नेताओं की सभाओं में जाते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उन सभी का हुक्का-पानी बंद होना चाहिए, इस बयान के बाद मारिया आलम खान सुर्खियों में छा गई।

क्या चाहती है मारिया आलम?

मारिया ने जो कहा, वो इस तरह है 'अगर आज की बात की जाए, तो आज ये कुर्बानी जरूरी है... हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां न हम अकेले जीत सकते हैं और न हम हार सकते हैं...अगर अब भी हम एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहां से हमारा नाम-ओ-नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे। उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होकर, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहां पर बैठ कर मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आज कितने लोग सीएए-एनआरसी के कारण जेलों में बंद हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने मुकदमे अदालत में सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी ताकत आप हो और आप अगर ऐसे मायूस होकर बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। सौ बार लड़ेंगे...सौ बार हारेंगे, लेकिन फिर उठकर चलेंगे। दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी मौका मिलता है। आज जो भी चुनावी मीटिंग होती है उसमें कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पर मैं कहती हूं कि न संविधान खतरे में है और न लोकतंत्र खतरे में है बल्कि आज तो इंसानियत खतरे में है। इंसानियत पर हमले हो रहे हैं। तो इस बार बहुत जोश के साथ नहीं बल्कि होश से वोट दो। किसी की बातों में किसी के बहकावे में मत आओ।

कौन है मारिया आलम

मारिया आलम खान दिवंगत इजहार आलम खान की बेटी हैं। इजहार आलम खान फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पितोरा तहसील कायमगंज के रहने वाले थे। वो कायमगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। मारिया आलम खान फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं। मारिया आलम खान के पति सरोश उमर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। मारिया आलम की शिक्षा-दीक्षा दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई है। वह ह्यूमन साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। राजनीतिज्ञ के अलावा मारिया आलम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कई आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। वह अधिकांश समय दिल्ली के जामियानगर में रहती हैं। मरिया ने जेल में बंदियों के रोजगार के लिए भी काम किया है। मारिया आलम खान के चाचा सलमान खुर्शीद हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद यूपीएस सरकार में विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय का काम देख चुके हैं। मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने के मामले में सलमान खुर्शीद पर भी केस दर्ज किया गया है।

मुस्लिम भरोसे लायक नहीं ?

फर्रुखाबाद पुलिस ने सपा नेता मारिया आलम खान और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ मजहब के नाम पर वोट मांग कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम और यादव वोट बैंक के भरोसे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लगता है कि अगर यूपी में उनके उम्मीदवारों को एकमुश्त मुस्लिम वोट मिलता है तो कई सीटों पर भाजपा को फाइट दी जा सकती है। मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं, किसे वोट देते हैं, ये जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि अब उन्हें दो वक्त का राशन मिलता है, शौचालय मिले हैं, बिना भेदभाव के बिजली और पानी के कनेक्शन मिले हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6000 रुपये सालाना मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर है, दिन हो या रात बहू-बेटियां बिना डर और खौफ के कहीं भी आ जा सकती हैं। पुलिस बेवजह किसी को परेशान नहीं करती, गुंडे लूट-खसोट नहीं करते, बिना भेदभाव के घर मिले हैं, सड़कें बनी हैं, सुकून की जिंदगी है, इस सब के बावजूद जब बात वोट की आती है तो बहुत कम मुस्लिम मतदाता ही कमल को वोट देने की बात करते हैं, बाकी ज्यादातर मुस्लिम मतदाता साइकिल का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक बदलाव आजकल दिखाई देता है। कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इतना सब मिलने के बाद उन्हें भी बदलना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेताओं को ये डर लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट टूट ना जाए। इसलिए मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट जिहाद जैसे लफ्जों का टेप सुनाया जा रहा है। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि अगर भाजपा की सरकार तीसरी बार आई तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा की कोशिश है कि अगर विपक्ष मुस्लिम वोटों पर दांव लगा रहा है, तो उसे हिंदू वोट पर फोकस करना चाहिए और ये काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी कर भी रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बंगाल में एक जनसभा में आरोप लगाया कि ममता सरकार पश्चिमी बंगाल में बंग्लादेशियों और रोहिंग्या को गैरकानूनी तरीके से बसा कर हिंदुओं को राज्य में अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रच रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त किया जाएगा।

- **अगर हम एक नहीं हुए तो समझ लेना कि हमारा नाम-ओ-नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसे तुम कामयाब करने का काम करोगे, इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होकर, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो।**
- **मारिया आलम खान फर्रुखाबाद में सपा की जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके पति सरोश उमर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं, मारिया आलम की शिक्षा-दीक्षा दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई है, वह ह्यूमन साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं।**

मारिया के बचाव में अखिलेश

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मारिया आलम खान का बचाव किया है। वोट जिहाद के मुद्दे पर मारिया का बचाव करते हुए सपा मुखिया ने कहा मारिया का इरादा लोगों को बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कहना था, भड़काना नहीं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि कभी-कभी लोगों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए उत्साहित करने में शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल हो ही जाता है। मारिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। सपा मुखिया ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भरोसे लायक नहीं है। इस सरकार ने अपने फैसलों से देश की जनता को संकट में डाल रखा है। सरकार के नोट बंदी, जीएसटी, इलैक्टोरल बांड लाने जैसे फैसलों से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में कई बार अनजाने में कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द पब्लिक को भड़काने वाले होते हैं।

भाजपा की हैट्रिक लगेगी उत्तराखंड में ?

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड में सिर्फ अपनी हाजिरी लगाई है, सिर्फ चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने पीए नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं को मैदान में उतार कर विपक्ष के हौंसले पस्त कर दिए।

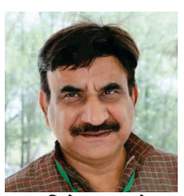

दिनेश मानसेरा
स्वतंत्र पत्रकार

कसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो गया है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवार मतदान से पहले ही सरेंडर करने की मुद्रा में आ गए हों। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस खेमे में सन्नाटे की सी हालत देखकर कार्यकर्ताओं में जोश या उत्साह भी ठंडा पड़ गया। केंद्रीय नेतृत्व ने भी उत्तराखंड से हाथ खींच लिए थे, पूरे चुनाव कैंपियन में सिर्फ कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए आई। इससे लग रहा था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं की चुनाव में कोई रुचि नहीं है। इसलिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार में करंट ही दिखाई नहीं दिया। यानी ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ अपनी हाजिरी लगाई है, जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे नहीं लड़ा है। इसके विपरीत भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अनुराग ठाकुर जैसे फायरब्रांड नेताओं को उत्तराखंड के चुनाव मैदान में उतार कर विपक्षी उम्मीदवारों के हौंसले पस्त कर दिए। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खूब पसीना बहाया जिससे उनके भीतर उभरती युवा सनातनी नेता की छवि दिखाई दी। मतदाताओं के बीच मोदी ने भी धामी के मैजिक को प्रभावी बनाया है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं तो चल ही रही है साथ ही मोदी सरकार ने यहां एक लाख 25 हजार करोड़ की बड़ी योजनाएं चुनाव से पहले ही दे दी थी। जिनमें चार धाम के स्थल विकास, ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट, मानसखंड प्रोजेक्ट आदि शामिल है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद पर प्रभावी कारवाई करने, सख्त धर्मांतरण कानून बनाने, दंगा विरोधी कानून लाने, गौ हत्या, गौ तस्करी के खिलाफ गैंगस्टर लगाने जैसे सनातनी कार्य किए है।

नैनीताल	हरिद्वार	अल्मोड़ा	पौड़ी गढ़वाल	टिहरी
भाजपा 7,72,195	भाजपा 6,65,674	भाजपा 4,44,651	भाजपा 5,06,980	भाजपा 5,65,333
कांग्रेस 4,33,159	कांग्रेस 4,06,945	कांग्रेस 2,11,665	कांग्रेस 2,04,311	कांग्रेस 2,64,747

सीएम धामी के सख्त तेवर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद पर प्रभावी कारवाई करने, सख्त धर्मांतरण कानून बनाने, दंगा विरोधी कानून लाने, गौ हत्या, गौ तस्करी के खिलाफ गैंगस्टर लगाने जैसे सनातनी कार्य किए। हल्द्वानी में लैंड जिहाद पर बुल्डोजर चलाने के विरोध में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव हुआ तो धामी ने सख्त तेवर दिखाए और सरकारी तथा निजी संपत्ति की भरपाई आरोपियों से करने के सीधे निर्देश दिए। पुलिस पर अटैक करने वालों से जिस सख्ती से निपटा गया उससे पुष्कर सिंह धामी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परछाई नजर आ रही है। जिसकी वजह से उनकी छवि जनता में एक सख्त हिंदू प्रशासक के रूप में बनकर उभर रही है। भाजपा को इस छवि का लाभ लोकसभा चुनाव में मिलना निश्चित है। युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून लाकर नौकरियों में पारदर्शिता लाने से भी भाजपा को फायदा मिल रहा है। जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और क्षेत्रीय नेता एकजुट होकर भी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर नहीं कर पाए है। हालत ये थी कि इंडिया गठबंधन का कोई साझा घोषणा पत्र तक नहीं था, हर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र अपने हिसाब से बनाया, इससे ही विपक्षी एकता की कलई खुल गई।

नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट

उत्तराखंड की नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। 2019 में अजय भट्ट ने नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सीट पर कमल खिलाया था। कैबिनेट से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हुई तो अजय भट्ट को रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री बनाया गया। अजय भट्ट दूसरी बार नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला दो बार विधानसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस के प्रकाश जोशी से है। जबकि 2019 में अजय भट्ट ने इसी सीट से उत्तराखंड में कद्दावर कांग्रेस नेता हरीश रावत को बड़े अंतर से हराया था। इससे समझ सकते हैं कि प्रकाश जोशी कहां टिक पाएंगे? इस सीट को वीवीआईपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्व में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र कृष्ण चंद्र पंत, नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे बड़े नेताओं की कर्मभूमि रही है। इस सीट पर 2024 के चुनाव में कुल दस प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार अजय भट्ट ने कांग्रेस के दिग्गज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 3,39,096 वोटों से मात दी थी। हरीश रावत को 433159 वोट मिले थे। भाजपा के अजय भट्ट को 772195 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस ने ठाकुर की बजाय ब्राह्मण उम्मीदवार पर दाव लगाया है। कांग्रेस की हालत ये है कि कई नेता पार्टी छोड़ कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। बसपा ने इस वीवीआईपी सीट से अख्तर अली को प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विशाल जनसभा कर गए है, जनसभा में पीएम मोदी के प्रति जनसमर्थन और दीवानगी देखकर तो यही लगता है इस बार भी भाजपा यहां उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।

हरिद्वार लोकसभा सीट

भाजपा ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, उनका मुकाबला पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत से है। वीरेंद्र रावत की उम्मीदवारी घोषित होते ही पारिवारिक अंतर्कलह सामने आ गई थी। हरीश रावत की दूसरी पत्नी से विधायक पुत्री अनुपमा रावत नाराज है। हरिद्वार लोकसभा सीट से खानपुर के विधायक उमेश कुमार निर्दलीय प्रत्याशी है जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां मौलाना जमील अहमद को टिकट दिया है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहां 4,06,945 और बीएसपी को 1,73,528 वोट मिले थे। यहां मुस्लिम वोटों की संख्या भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकती है यदि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में अच्छा मतदान हुआ तो भाजपा को एक बार फिर यहां से विजयश्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हरिद्वार से 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खूब पसीना बहाया जिससे उनके भीतर उभरती युवा सनातनी नेता की छवि दिखाई दी, मतदाताओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के मैजिक को प्रभावी बनाया है।

अल्मोड़ा (सुरक्षित)

अल्मोड़ा सुरक्षित संसदीय सीट से एक बार फिर से भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और कांग्रेस के पूर्व राज्य सभा सदस्य प्रदीप टम्टा के बीच चुनावी टक्कर है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बार यहां सात उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा सीट से भाजपा के अजय टम्टा को 4,44,651 और कांग्रेस प्रदीप टम्टा को 2,11,665 वोट हासिल हुए थे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली इस लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव घोषित होने से पहले ही चार बड़ी जनसभाएं करके भाजपा की राह आसान कर दी थी। चुनाव से कुछ माह पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ की व्यास घाटी, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम में शिव आराधना कर रैली को संबोधित किया था। जिसके बाद से स्थानीय लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता सौंपने का जुनून सवार नजर आता है। क्योंकि मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री होने के साथ कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।

पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र

पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काट कर, अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के गणेश गोदियाल से है। अनिल बलूनी नया युवा चेहरा है और दिल्ली की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते है। पिछली बार यानी 2019 में यहां भाजपा के तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 और कांग्रेस के मनीष खंडूरी को 2,04,311 वोट मिले थे। मनीष खंडूरी अब भाजपा के साथ है। उनके अलावा बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी और तीन पूर्व विधायक भी भाजपा का दामन थाम चुके है। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से 13 प्रत्याशियों ने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दल यहां स्टार प्रचारकों की रैलियां करा चुके हैं। अब चार जून को किसके सिर ताज होगा इसके लिए इंजतार कीजिए।

टिहरी लोकसभा क्षेत्र

टिहरी संसदीय सीट पर पहले से ही राज परिवार का कब्जा रहा है। भाजपा ने इस बार भी महारानी माला राज लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिहरी राज परिवार ने यहां से 12 बार लोकसभा चुनाव जीता है। पिछली बार 2019 में टिहरी से महारानी को 5,65,333 वोट मिले थे जबकि कांग्रेस के प्रीतम सिंह को 2,64,747 वोट मिले थे। इस बार भी टिहरी संसदीय सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक धमक सुनाई दी है। कांग्रेस ने यहां जोत सिंह को टिकट दिया है जो पिछली बार के प्रत्याशी प्रीतम सिंह से कमजोर और उम्रदराज प्रत्याशी माने जा रहे है। टिहरी राजघराने की महारानी माला राज लक्ष्मी के लिए यहां की जनता में एक आदर भाव रहता है। उनके राजमहल से ही भगवान बद्री विशाल के द्वार खुलने और बंद होने की तिथि घोषित होने की परंपरा रही है। जिसकी वजह से इस परिवार को क्षेत्र की जनता बेहद सम्मान से देखती आई है। इस संसदीय सीट पर 11 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब चार जून का इंतजार करें।

मन से हार चुका विपक्ष ?

लोकतंत्र और संविधान बचाने की बातें वो कांग्रेसी नेता कर रहे हैं जिनसे पार्टी तक नहीं बचाई जा रही। यूपी की दो अदद लोकसभा सीटों रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी घोषित करने में पसीने छूट गए। राहुल गांधी अमेठी छोड़ कर वायनाड के बाद अब रायबरेली पहुंच गए।

केके चौहान

लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, तक सभी पार्टियों के नेता रोड शो और रैलियों में गजर और बरस रहे हैं। पर सच ये है कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन मानसिक रूप और मन से हार स्वीकार कर चुका है। उसे भी पता है कि आएंगे तो मोदी ही। इसलिए जिसके मन में जो आ रहा है बोल दे रहा है। कोई संविधान को खतरा बता रहा है तो कोई लोकतंत्र को। कोई आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रहा है तो कोई पीएम मोदी को बददुआएं दे रहा है। कोई राम और शिव का झगड़ा करा रहा है, कोई मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि इन सबकी परवाह किए बिना देश के हर कोने में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में जम कर मेहनत की है। पश्चिम बंगाल और बिहार में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ करने के लिए भाजपा पसीना बहा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों में विरोधी दलों के आरोपों का ऐसा जवाब देते हैं कि विरोधी बैकफुट पर आ जाते हैं। विरोधी दलों के नेता चीख-चीख कर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि अगर मोदी फिर जीते तो वह संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के सभी बयानवीरों को गंभीरता से सुनते हैं और फिर चुन-चुन कर सबको जवाब देते हैं। संविधान बदलने के विपक्षी झूठ पर पीएम मोदी का दो टूक कहना है कि भाजपा तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो अब खुद बाबा साहब आंबेडकर भी नहीं बदल सकते। संविधान तो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों का रक्षा कवच है, संविधान देश की प्रगति को दिशा देने वाली ताकत है, संविधान के साथ खिलवाड़ तो 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर किया था। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा कर संविधान को निलंबित कर दिया था। कांग्रेस ने जिन समाजवादियों को जेल में ठूंसा था वही कथित समाजवादी आज कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है तब उसे संविधान और लोकतंत्र की याद आती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब खुद राहुल गांधी ने 2013 में संविधान में किए गए संसोधन को फाड़ कर फेंक दिया था। जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता भी कुछ दिन के लिए चली गई थी। अब हार की हताशा में डूबे विपक्षी दलों के नेता देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। मोदी को अगर 400 से ज्यादा का बहुमत मिल गया तो मोदी संविधान को बदल देंगे। जरा सोचिए मोदी को ये काम करने होते तो 10 साल में निपटा दिए होते।

संविधान बदलने के विपक्षी झूठ पर पीएम मोदी का दो टूक कहना है कि भाजपा तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो अब खुद बाबा साहब आंबेडकर भी नहीं बदल सकते, संविधान तो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों का रक्षा कवच है।

ऐसे में विपक्ष पर सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी दस साल से प्रधानमंत्री हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन क्या संविधान में कोई बदलाव हुआ या कोई छेड़छाड़ हुई? क्या 1975 वाले दिन देखने को मिले? क्या किसी को आरक्षण से वंचित किया गया? जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला गया। उनका हक छीन कर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। तेलंगाना की 26 जातियों लम्बे समय से ओबीसी का दर्जा मांग रही हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये तुष्टीकरण की प्रयोगशाला नहीं तो और क्या है? तेलंगाना और कर्नाटक में क्या भारत के संविधान को खतरा पैदा नहीं किया गया? संविधान में तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था कहीं है ही नहीं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात संविधान में कहां लिखी है। ये वो कांग्रेस है जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60 वर्षों तक जमकर लूटा है। अब उसकी नीयत आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। इसलिए कांग्रेस ने विरासत टैक्स की चिंगारी लगा दी है। ताकि नॉर्थ ईस्ट, असम व देश के अन्य भागों में घुसपैठ बना चुके करोड़ों घुसपैठियों व रोहिंग्या को सहूलियत दी जा सकें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कांग्रेस विरासत टैक्स लादकर आम जनता को तबाह करने का षडयंत्र रच रही है। देश के मेहनतकश लोगों की संपत्तियों को जबरन कब्जा कर कांग्रेस घुसपैठियों को देना चाहती है। जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरू सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के प्रयास की उसी मंशा को उजागर किया है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी इस टैक्स को लागू कर चुकी होती। सैम पित्रोदा की वही कह रहे हैं, जो पी.चिदंबरम कह चुके हैं और कांग्रेस कर चुकी है। क्या ये सब संविधान का हिस्सा है?

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी से लेकर असद्दुदीन ओवैसी तक सारे नेता अपनी रैलियों में यही झूठ फैलाते रहे हैं भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान बदल सकती है। ओवैसी कहते हैं कि मोदी बार-बार चार जातियों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान को बदलकर वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि अगर-मगर की कोई बात ही नहीं हैं, भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो मोदी संविधान बदलेंगे। भाजपा के कई बड़े नेता इसके लिए माहौल बना रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दो, तो संविधान बदल देंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, वो लोकतंत्र खत्म होने का संकेत है। भाजपा गरीबों को मुफ्त राशन इसलिए बांट रही है ताकि वो सरकार से सवाल न पूछ सकें, वो संविधान बदलें, आरक्षण खत्म करें, लेकिन लोग इस डर से कि कहीं राशन बंद न हो जाए, चुप रहें। इसलिए मुफ्त राशन की लत लोगों में डाली जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करने की फिराक में हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस बार संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

लोकतंत्र और संविधान बचाने की बातें वो कांग्रेसी नेता कर रहे हैं जिनसे पार्टी तक नहीं बचाई जा रही। यूपी की दो अदद लोकसभा सीटों रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी घोषित करने में पसीने छूट गए। राहुल गांधी अमेठी छोड़ कर वायनाड के बाद अब रायबरेली पहुंच गए। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामाकंन रद्द कराकर सूरत की सीट भाजपा को सौंप दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने खेला ही कर दिया। नामाकंन वापस लेने के आखिरी दिन इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे और अपना नामाकंन वापस ले लिया। अक्षय क्रांति यहीं नहीं रुके, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भी शामिल हो गए। इससे एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। इन सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लम्बी है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेसी कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में या डराने धमकाने से उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। खैर मुद्दे पर लौटते हैं और बताते हैं कि मोदी सरकार ने संविधान को सर्वोपरि रखा है, इस साल संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया है कि जैसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वैसे ही संविधान महोत्सव मनाया जाएगा। देश में पिछले 30 साल से भाजपा

- **विरोधी दलों के नेता चीख-चीख कर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि अगर मोदी फिर जीते तो वह संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं।**
- **भाजपा के रणनीतिकार हमेशा टारगेट तय करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, इसलिए हर चुनाव में चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का भाजपा टारगेट लेकर चलती है, टारगेट हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जाती है।**

राज्यों से लेकर केंद्र तक में सत्ता में रही, किंतु भाजपा ने संविधान पर कभी आंच नहीं आने दी। फिर भी विपक्ष संविधान को राजनीति हथकंडा बना रहा है। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि उनके लिए संविधान विकसित भारत बनाने का मार्गदर्शक है।

संविधान बदलने का आइडिया विपक्षी दलों को कहां से आया? इसका सीधा सा जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंतिम सत्र में भाजपा को 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता फील्ड में उतरे तो अबकी बार 400 पार का नारा देना शुरू कर दिया। भाजपा के रणनीतिकार हमेशा टारगेट तय करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। इसलिए हर चुनाव में चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का भाजपा हमेशा टारगेट लेकर चलती है। टारगेट हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। रणनीति के दायरे में रहकर काम किया जाता है। चुनाव में परीक्षा होती है तो परिणाम भी बेहतर आते हैं, लेकिन कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों का अपना कोई टारगेट नहीं है। सिर्फ दावा कर रहे हैं कि भाजपा 150 पार भी नहीं करेगी। एसी रूम में बैठकर सोशल मीडिया अथवा मीडिया में बयान जारी करने से भाजपा 150 पर नहीं रुक जाएगी। विपक्षी दल ये नहीं बता रहे कि वो कितनी सीट जीत रहे हैं, यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 सीटें हार रही है, लेकिन कौन हरा रहा है? सपा कितनी सीट जीत रही है? ये नहीं बता रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ऐसे ही हवा-हवाई दावे कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जनता ने मन बना लिया है भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का, लेकिन नतीजा सबने देखा और योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा सीएम बनने का रिकार्ड बनाया। मोदी के 400 पार वाले नारे से विपक्ष बोखलाया हुआ है, उसे पता है कि 400 पार नहीं तो 400 के आसपास तो भाजपा रहेगी ही। इसलिए चिल्लाना शुरू किया नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा।

मानसिक रूप से हार चुका विपक्ष

लोकसभा चुनाव से पहले ही में कांग्रेस की समझ में आ गया था कि वो अपने बूते पर भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की हालत में नहीं है। इसलिए उसने क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा किया। इसे एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने त्याग का घूट पीकर गठबंधन किया है। कांग्रेस ने जो त्याग किया वो राजनीति के इतिहास में कांग्रेस को सबसे कमजोर बताने के लिए काफी है। यानी 10 साल में कांग्रेस का ढांचा चरमरा गया है। कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं रही इसलिए 2014 के लोकसभी चुनाव में वो सबसे कम 310 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 529 सीटों पर 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। 1951 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उस समय कांग्रेस ने 440 सीटों पर चुनाव लड़ा और 209 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 464 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे जिसमें से 44 ही जीत पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जिसमें से केवल 52 को ही जीत मिली थी। इसमें दो सांसद गांधी परिवार से थे। 2019 में ही राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी हार गए थे।

उत्तराखंड का हलक सूखने लगा

उत्तराखंड देश की एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन ये पहाड़ी राज्य खुद भीषण जल संकट से गुजर रहा है, वैसे ये माना जाता है कि जिस राज्य में गंगा नदी बहती हो वहां भला जल की क्या कमी? पर आंकड़े जो सच बयां कर रहे हैं, वो डराने वाले तो हैं।

हि

रतन सिंह किरमोलिया
गरुड़, बागेश्वर

मालयी ग्लेशियर में जो बर्फ जमा है, वो पिघल कर नदियों के रूप में करीब 90 करोड़ आबादी के लिए वरदान है। क्योंकि यही पानी नदियों से होते हुए इंसानी बस्तियों तक पहुंचता है। इसलिए हिमालय को एशिया का वाटर टावर माना जाता है। हिमालयी ग्लेशियर में एक महासागर जितने पानी की क्षमता है, इतनी बड़ी मात्रा में पानी होने के बावजूद हिमालयी राज्य उत्तराखंड के कई क्षेत्र पानी के लिए तरसने के कगार पर हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अभी से राज्य के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत साफ-साफ महसूस की जाने लगी है। वैसे हालात देश के दूसरे राज्यों के भी अच्छे नहीं हैं। पानी को लेकर हुए अध्ययनों ने पेयजल की स्थिति पर चिंता बढ़ाई है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर कुप्रभाव नजर आने लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ हर साल आग की भेंट चढ़ते हैं जिससे जीवनोपयोगी जैव विविधता नष्ट हाती है। चौड़ी पत्ती के वन नष्ट हो चुके हैं। रहे सहे चीड़ के वन भी आग की चपेट में आ रहे हैं। इससे भी वातावरण की नमी तेजी से नष्ट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। दुनिया में कहीं भारी से भारी बारिश बर्बादी कर रही तो कहीं भयंकर सूखा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय की बर्फबारी और हिमनदों पर भी पड़ रहा है। बात भारत की करें तो सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या से उत्तर भारत जूझ रहा है। जिसमें सभी महत्वपूर्ण और बड़े राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 90 फीसदी उत्तर भारत के राज्य पेयजल संकट से प्रभावित हैं। देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता आजादी के बाद करीब 8,170 घन मीटर थी, जो अब करीब 1,293 घन मीटर पहुंच गई है। देश में भूजल खपत मामले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्य सबसे ऊपर है। इन चार राज्यों में खपत 100 फीसदी से भी ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत है। वहीं देश के मेट्रो सिटी के अलावा बड़े शहरों में भूजल के प्रदूषण में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश भर में भूजल के कम होने के पीछे इसके ज्यादा उपयोग और वाटर रिचार्ज की मात्रा कम होना माना जा सकता है, लेकिन एक बड़ी वजह पर्यावरण में आ रहा वो बदलाव भी है, जिसके कारण तमाम क्षेत्रों में बारिश का बेहद कम होना है और तापमान में बेहद ज्यादा वृद्धि होना है।

जल स्रोतों को लोग देवता मानते थे

उत्तराखंड राज्य देश की एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन वर्तमान में ये पहाड़ी राज्य भीषण जल संकट से गुजर रहा है। अमूमन ये माना जाता है कि जिस राज्य से गंगा जैसी विशाल नदी बहती हो वहां भला जल की क्या कमी? लेकिन सरकारी आंकड़े जो हकीकत बयां कर रहे हैं, वो बेहद चौंकाने और डराने वाले तो हैं ही साथ ही भयावह भी हैं। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के लिए एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी भी यहां के काम नहीं आई। एक दो अपवादों को छोड़ दें तो यह काफी हद तक सही भी है। क्योंकि अब तो उत्तराखंड के लोगों के ही हलक सूख रहे हैं। पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत छोटी-छोटी नदियां अब गायब हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार और सिस्टम को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे नीति निर्धारक 6-7 महीने में एक बैठक करके इस पर सिर्फ चर्चा ही करते हैं। समाधान की तरफ न तो ध्यान दिया जाता और न ही कोई प्लान बनाया जाता है। हालात यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट यह कह रही है कि उत्तराखंड में लगातार जल स्रोत सूख रहे हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तराखंड में लगातार जल स्रोत सूख रहे हैं, जानकार तो यह भी मानते हैं कि पलायन का एक बड़ा कारण नौले-धारे और जल स्रोतों का सूखना भी है, इन सब के पीछे वजह जो भी हो, पर इन हालात के लिए इंसान भी जिम्मेदार है।

जानकार तो यह भी मानते हैं कि पलायन का एक बड़ा कारण नौले-धारे और जल स्रोतों का सूखना भी है। इन सब के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन इन हालातों की बड़ी वजह इंसान ही है। कुछ समय पहले तक जल स्रोतों को गांव के लोग देवता की तरह पूजते थे। साल में कई बार गांव इकट्ठा होकर इन नौले धारों और जल स्रोतों को संजोकर रखते थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये जल स्रोत आबादी वाले इलाकों में सूखने लगे हैं। राज्य में सबसे अधिक जल संकट, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, और बागेश्वर जिले में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक जल स्रोत कम हो रहे हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की मानें तो राज्य में 725 ऐसे जलाशय हैं, जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसकी वजह मंत्रालय ने प्रदूषण फैक्ट्री और तालाबों के ऊपर बस्तियों को बताया था। उत्तराखंड में 3096 जलाशय हैं, जिसमें 2970 जलाशय ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि 126 जलाशय शहरी क्षेत्र में हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2371 जलाशय में ही पानी पाया गया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में प्राकृतिक जल स्रोत को सूखते देख लोग भी बेहद चिंतित हैं। कभी टिहरी बांध के विरोध में खड़े हुए स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे कहते हैं कि हमने इन जल स्रोतों को भगवान की तरह पूजा है, लेकिन आज पहाड़ों में हो रहा अनियंत्रित विकास और सड़कों का जाल जल स्रोतों के सूखने की प्रमुख वजह हैं। युवा पीढ़ी भी जल स्रोतों और झरनों के फोटो खिंचवाने या खींचने तक सीमित है। जल संरक्षण के लिए आवाज तो उठ रही है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही। हैरानी की बात ये है कि हमारे यहां नदियां हैं और तमाम स्रोत हैं, जो कई राज्यों को पानी देते हैं, लेकिन हम और हमारी सरकार इनको बचा नहीं पा रही हैं। नदियों और जल स्रोतों पर लगातार बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

प्राकृतिक जल स्रोतों की हालत गंभीर

उत्तराखंड में खासतौर पर प्राकृतिक जल स्रोतों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जल संस्थान के स्तर पर गर्मी शुरू होने से पहले किए गए अध्ययन में यह साफ हुआ है कि जल स्रोतों में मौजूद पानी कम हुआ है। यह सीधे पेयजल संकट को जाहिर करता है राज्य में अब तक करीब 2400 प्राकृतिक जल स्रोत अनियोजित विकास के शिकार हो चुके हैं। कंक्रीट के जंगलों ने एक तरफ जल स्रोतों के अस्तित्व पर संकट पैदा किया है तो भूजल के प्राकृतिक रूप से रिचार्ज को भी असंतुलित किया है। साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण प्रभावित वातावरण ने मौसमी चक्र को भी बदल कर रख दिया है। नतीजतन उत्तराखंड के कई ठंडे इलाके पहले के मुकाबले काफी गर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश के असंतुलन ने भी अंडरवाटर की स्थिति को प्रभावित किया है। प्रदेश में जिस तरह इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है, उससे भी पेयजल को लेकर परेशानियां बढ़ने वाली हैं। लंबे समय तक बारिश ना होने और भीषण गर्मी के कारण अंडरवाटर लेवल पहले से ही काफी गिर चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ सही नहीं है। जब ऐसा होता है तो प्रकृति खुद के स्वरूप को पुर्नस्थापित करने के लिए कुछ ऐसे बदलाव करती है जो इंसान पर भारी पड़ते हैं। लिहाजा जो संकेत पेयजल को लेकर मिल रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द गंभीर विचार कर कदम उठाना बेहद जरूरी है, नहीं तो पहाड़ से नीचे नदी तो दिखेगी, लेकिन पहाड़ पर पीने का पानी नहीं होगा।

खुद प्यासे हैं जल स्रोत

देश में 45 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है, लिहाजा पानी को लेकर संकट केवल पेयजल से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका व्यापक असर भी है। देश में 146 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में करीब 55 प्रतिशत वर्षा आधारित है। भारत में वार्षिक औसत 1160 मिलीमीटर वर्षा होती है। जबकि विदेशों में 80 से 85 प्रतिशत पेयजल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। उत्तराखंड में मोटा अनाज जिस भूमि पर होता है, वो क्षेत्र भी वर्षा आधारित खेती से ही जुड़ा है। खास बात ये है कि राज्य में न केवल बारिश को लेकर स्थिति चिंताजनक है, बल्कि कम बर्फबारी के कारण तमाम प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बर्फबारी के कम होने से तमाम जल स्रोत सूख रहे जिसका पेयजल संकट से सीधा संबंध है। यानी उत्तराखंड में सदियों से लोगों की प्यास बुझाने वाले प्राकृतिक जल स्रोत अब खुद प्यासे हो रहे हैं। पहाड़ों से निकलकर मैदान के शहरों तक पहुंचने वाले स्वच्छ और निर्मल जल को मानो किसी की नजर लग गई है। पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास कार्यों का प्रभाव

मानवीय गतिविधियों से प्रभावित वातावरण ने मौसमी चक्र को भी बदल दिया है, नतीजतन उत्तराखंड के कई ठंडे इलाके पहले के मुकाबले काफी गर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं, पहाड़ों पर बारिश के असंतुलन ने अंडरवाटर की स्थिति को प्रभावित किया है।

भूमिगत जल पर पड़ रहा है। पिछले 30 से 40 सालों में उत्तराखंड में करीब एक लाख प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों ने अपने शोध में चिंता जताते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जल स्रोत प्रबंधन केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता बताई है। पिछले दिनों विशेषज्ञों की पंचायत में प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने पर चिंता व्यक्त की गई थी।

लगातार सिकुड़ रहे ग्लेशियर

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड की सदानीर नदियों में 65 फीसदी जल प्राकृतिक स्रोतों से आता है, लेकिन बारिश की अनियमितता व अनियंत्रित विकास, निर्माण कार्य, भूमिगत जल को प्रभावित कर रहे हैं। सड़क व सुरंगों के निर्माण से जलभृत क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जिससे प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं या सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। पिछले 30 से 40 सालों में उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में एक से दो प्राकृतिक जल स्रोत सूखे हैं या सूखने के कगार पर हैं। 2017 की नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब जरुरत इस बात की है कि जल नीति निर्धारित कर प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण व इनको पुनर्जीवित करने की पहल की जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट से भरे पड़े इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल संपदा का परोक्ष लाभ भी यहां के निवासियों को नहीं मिल पाया है। वर्तमान परिदृश्य में तो स्थिति और भी खतरनाक हो रही है। ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं, नदी गाड़, गदेरों में पानी सूखता जा रहा है। राज्य में वन विभाग के नेतृत्व में बनी जल स्रोत प्रबंधन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 गांव जल संकट से गुजर रहे हैं। मोटे तौर पर राज्य में लगभग 510 जलस्रोत सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। अकेले अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक 300 जल स्रोत सूख चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर में साठ फीसदी कमी आई है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नौले-धारे बचे हैं उनमें भी जल की मात्रा आधी रह गई है।

प्राकृतिक स्रोत तेजी से गायब हुए

राज्य में 461 जल स्रोत ऐसे हैं, जिनमें 76 प्रतिशत से अधिक पानी सूख चुका है। दिनों दिन बढ़ती इस गंभीर स्थिति पर नीति आयोग कह चुका है कि हिमालय क्षेत्र के राज्यों में 60 फीसद से अधिक जल स्रोत सूख गए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों में बताया गया है कि देश के 700 जिलों में 256 ऐसे हैं, जहां भूजल का स्तर अतिशोषित हो चुका है। तीन चौथाई ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी की पहुंच नहीं रही है। वे असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है। देश में 70 फीसद जल स्रोत दूषित हैं जिसके कारण लोग तरह-तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। प्रमुख नदियां प्रदूषण के कारण मृतप्राय हो गई हैं। जिस तरह दुनिया का पहला जलविहीन शहर दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन बन गया है, उसी तरह की स्थिति हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बहुत से गांवों और शहरों की है, जिसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जल निकायों की गणना में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इनमें 78 फीसदी जल निकाय मानव निर्मित हैं और 22 फीसद यानी 5,34,077 जल निकाय प्राकृतिक हैं। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक स्रोत तेजी से गायब हो रहे हैं। कुल जल निकायों की क्षमता के संबंध में बताया गया है कि 50 फीसद जल निकायों की भंडारण क्षमता 1000 से 10,000 क्यूबिक मीटर के बीच है। वहीं 12.7 फीसद यानी 3,06,960 की भंडारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। जल निकायों की इस गणना के बाद सुनिश्चित होना चाहिए कि देश के नीति-निर्माता उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भविष्य में जल संसाधनों के सही नियोजन एवं विकास और उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाएं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।

उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाएं

उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टीनेशन युवाओं को खींच रहे हैं, सरकार इसे बढ़ावा देती है तो न केवल सरकार को टैक्स मिलेगा, बल्कि स्थानीय कारोबारियों के व्यापार में भी वृद्धि होगी, वैसे उत्तराखंड में कई वेडिंग डेस्टिनेशन हैं, जहां सात फेरे लेकर युवा अपनी शादी को यादगार बना रहे हैं।

हरीश भट्ट
रामनगर

युवाओं के जीवन में शादी एक ऐसी रस्म है, जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवनसाथी के साथ सुदूर देश या फिर किसी विदेश में अथवा सात समुंद्र पार किसी खूबसूरत डेस्टीनेशन पर शादी की रस्में पूरी करें। ताकि जीवन के ये पल जीवनभर यादगार बने रहे। शायद इसलिए वेडिंग डेस्टिनेशन का क्रेज युवाओं में बढ़ रहा है। कुछ युवा अपने शहर गांव में ही शादियां करते हैं तो कुछ शहर से बाहर जाकर शादियां करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि दूसरे शहर में जाकर शादी करने पर खर्चा बढ़ जाता है। फिर भी डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोग लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक खर्च कर रहे हैं। उत्तराखंड को भी वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की पहल हो चुकी है। निवेशक खूबसूरत वादियों में शादियों को यादगार बनाने पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड को प्रकृति ने ऐसी नेमत से नवाजा है कि जिस तरफ नजर जाती है तो हटाने का मन नहीं करता है। यहां की खूबसूरत वादियां लोगों को खूब लुभाती है। इसलिए देश और विदेश से सैलानी यहां खिंचे चले आते हैं। अब उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टीनेशन भी युवाओं को खींच रहे हैं। सरकार वेडिंग डेस्टीनेशन को बढ़ावा देती है तो इससे न केवल सरकार को टैक्स मिलेगा, बल्कि साथ में स्थानीय कारोबारियों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। हालांकि उत्तराखंड में कई ऐसे वेडिंग डेस्टिनेशन हैं, जहां सात फेरे लेकर युवा अपनी शादी को यादगार बना रहे हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद तो वेडिंग डेस्टिनेशन सुर्खियों में है। अब निवेशक वेडिंग डेस्टिनेशन में निवेश के लिए भी आगे आने लगे हैं।

वेडिंग डेस्टिनेशन से व्यापार बढ़ा

23 बरस पहले जब अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे तब आंदोलनकारियों से एक सवाल अवश्य पूछा जाता था कि आखिर राज्य की आय का स्रोत क्या होगा? राज्य में रोजगार कहां से मिलेगा? तब सभी राज्य आंदोलनकारी एक स्वर में यही कहते थे कि पर्यटन हमारी आय का प्रमुख स्रोत होगा। उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है भी। वेडिंग डेस्टिनेशन के कांसेप्ट की बात करें तो भारत में डेस्टिनेशन के कांसेप्ट की संभावना वाले मुख्य राज्य में राजस्थान, गोवा, केरल और उत्तराखंड का नाम आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन का व्यापार 20 से 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भी वेडिंग डेस्टिनेशन का प्रचलन खूब है, जो मिलियन डालर का वार्षिक व्यापार करता है। वेडिंग डेस्टिनेशन कांसेप्ट में दूल्हा और दुल्हन अपने घर से दूर किसी अन्य स्थान पर दांपत्य सूत्र में बंधते हैं। हालांकि भारत में इस कांसेप्ट के तहत विवाह संस्कार पुरानी परंपरा और रीति-रिवाज से ही होता है। मतलब विवाह संस्कार में केवल स्थान बदलता है बाकी सारी रस्में पारंपरिक ही रहती हैं। राजस्थान और गोवा में स्थानीय झलक भी देखने को मिलती है। वेडिंग डेस्टिनेशन कांसेप्ट से स्थानीय स्तर पर व्यापार करने वालों को काफी फायदा होता है। जैसे अगर राजस्थान में होने वाले विवाह समारोह के अंत में मेहमानों को दिया जाने वाला तोहफा वहीं के किसी स्थानीय उत्पादक द्वारा बनाया जाता है। ऐसे ही यदि केरल में विवाह संस्कार कर रहे हैं तो मेहमानों को मिलने वाली मिठाई केरल के ही उत्पादकों द्वारा तैयार की गई होगी। बाकी मेहमानों के स्वागत की व्यवस्था में भी स्थानीय कारोबारियों की बिक्री बढ़ती है।

रोजगार की अपार संभावना

उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन कांसेप्ट को समझने के लिए गुप्ता बंधु का अच्छा उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कांसेप्ट को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था। जिसमें सीएम के स्वागत की फोटो साझा की गई थी। इस शादी में बजने वाले वाद्य यंत्र स्थानीय नहीं थे। विवाह में जितना भी खाद्यान्न प्रयोग में लाया गया होगा वह स्थानीय व्यापारियों ने आयात ही किया गया होगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो इतना उत्पादन ही नहीं होता जो बड़े विवाह समारोह की मांग पूरी कर सके। इस विवाह में शायद ही ऐसा कोई तोहफा मेहमानों को दिया गया हो जिसे स्थानीय उत्पादकों ने तैयार किया हो। इस पूरी शादी में औली की सुंदरता के अलावा शायद ही कोई स्थानीय झलक देखने को मिली हो। हालांकि वेडिंग डेस्टिनेशन कांसेप्ट स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावना रखता है। विवाह समारोह एक बड़ा इवेंट है इसलिए इससे मिलने वाले रोजगार की कितनी संभावना है? इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में रिसॉर्ट और बैंकेट हॉल में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों पर नजर डाल सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों के रिसार्ट या बैंकेट हॉल में एक मैनेजर के अलावा दो-चार लोग देखभाल करने वाले होते हैं। बाकि अधिकांश काम बाहरी लोगों के जिम्मे रहता है। बहुत अधिक मुनाफे का व्यापार होने के बावजूद इसके लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बाहरी लोगों के पास चला जाता है।

उत्तराखंड में शांतिकुंज हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, मसूरी, देहरादून, औली, चकराता, हर्षिल, काणाताल, नरेंद्र नगर, नैनीताल, रामनगर, ब्रह्मताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, रानीगढ़, नौकुचियाताल, गोल्ज्यू मंदिर, आदि में भी वैवाहिक संस्कार होते हैं।

उत्पादन में फिसड्डी उत्तराखंड

वेडिंग डेस्टीनेशन कांसेप्ट में उत्तराखंड को फिलहाल बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि यह पहाड़ी राज्य उत्पादन के मामले में बहुत फिसड्डी है। शादी में प्रयोग होने वाले दूल्हा-दुल्हन के लिबाज से लेकर शादी में प्रयोग होने वाले खाने के मसालों को यहां के कारोबारी आयात करते हैं। 14 जनवरी से 15 दिसंबर 2023 तक त्रियुगीनारायण मंदिर में करीब 80 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे, जिनमें स्थानीय के साथ बाहरी क्षेत्रों और जनपदों के जोड़े भी शामिल हैं। इसके अलावा टिहरी झील, उत्तरकाशी जिले में तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हाटकोटी माता मंदिर में भी हर साल शादी के लिए बहुत से जोड़े पहुंचते हैं। देहरादून में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी शादी कर चुके हैं। गढ़वाल के अलावा कुमाऊं में जागेश्वर धाम, रामनगर, भीमताल, पिथौरागढ़, कौसानी जैसे स्थानों पर भी वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाएं हैं। चमोली जिले का औली भी प्राकृतिक खूबसूरती का खजाना है, लेकिन इसकी पहचान अब तक बर्फबारी के दीदार और स्कीइंग तक ही सीमित है। हालांकि अक्टूबर में संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे पांड्वाज ग्रुप के कुणाल डोभाल ने यहां शादी समारोह का आयोजन कर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आशा की किरण दिखाई है। 2018 में प्रदेश सरकार ने त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, लेकिन पांच साल बाद भी यहां सुविधाएं न के बराबर हैं। त्रियुगीनारायण में मंदिर के पुजारियों और तीर्थपुरोहितों तक के लिए शौचालय और स्नान घर तक नहीं है। इसके अलावा ऊखीमठ में अनिरुद्ध और ऊषा का विवाह स्थल भी है, लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में यह गुमनाम है।

150 करोड़ के इंवेस्ट एमओयू साइन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन पर जोर दिया था। जिसका असर ये हुआ कि अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशक आगे आने लगे हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में निवेशक अचलेश ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 150 करोड़ रुपये इंवेस्ट करने का एमओयू साइन किया है। जिसके बाद अब वेडिंग डेस्टिनेशन जोर पकड़ने लगा है। हालांकि यहां कई बड़ी हस्तियों की शादियां हो चुकी है। लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन उस वक्त सुर्खियों में आया जब कारोबारी गुप्ता बंधुओं ने औली में विवाह समारोह का आयोजन किया था। इसलिए यहां की खूबसूरत वादियों में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समिट के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि जो करोड़पति और अरबपति परिवार हैं वो अपने घर की एक शादी उत्तराखंड में अवश्य करें। क्योंकि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां विदेशों से कम नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि उत्तराखंड में एक साल में पांच हजार शादियां होती हैं तो एक नया बुनियादी ढांचा तैयार होगा और राज्य को दुनिया के लिए एक विवाह स्थल में बदल देगा।

- **वेडिंग डेस्टिनेशन कांसेप्ट में दूल्हा-दुल्हन घर से दूर किसी अन्य स्थान पर दांपत्य सूत्र में बंधते हैं, लेकिन भारत में इस कांसेप्ट के तहत विवाह संस्कार पुरानी परंपरा और रीति-रिवाज से ही होता है, यानी विवाह में सिर्फ स्थान बदलता है बाकी रस्में पारंपरिक ही रहती हैं।**
- **इस साल त्रियुगीनारायण मंदिर में करीब 80 जोड़ो विवाह किया इनमें स्थानीय व बाहरी क्षेत्र के जोड़े भी शामिल हैं, इसके अलावा टिहरी झील, उत्तरकाशी जिले में तथा हिमाचल की सीमा से सटे हाटकोटी माता मंदिर में भी हर साल शादी के लिए बहुत से जोड़े पहुंचते हैं।**

उत्तराखंड की वादियों में शादियां

वैसे उत्तराखंड के तमाम वेडिंग डेस्टिनेशन हैं, जहां बहुत से लोग शादियां करते हैं, लेकिन इसे और बढ़ाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार भी वेडिंग डेस्टिनेशन पर जोर दे रही है। ताकि निवेशक वेडिंग डेस्टिनेशन पर निवेश करें। जिससे विदेश में जाकर करोड़ों रुपये वेडिंग पर खर्च करने के बजाय सस्ते में उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में शादियां की जा सकें। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बल्कि देश का पैसा देश में रहेगा। कॉर्बेट पार्क में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड सरकार में साथ एमओयू साइन कर चुके अचलेश का कहना है कि वो रामनगर स्थित कॉर्बेट पार्क में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 150 करोड़ रुपये इंवेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर खुली और बड़ी जगह मौजूद है। उनका कहना था कि राज्य सरकार से इस बाबत बातचीत हुई है कि जो भी टैक्स होगा, उसमें सरकार छूट देगी। इसके अलावा सरकार पानी और बिजली में पहले से ही सब्सिडी दे रही है। साथ ही सरकार ने तमाम घोषणाएं भी की है कि अगर तय समय के भीतर निवेश धरातल पर उतरता है तो तमाम सहूलियत सरकार की ओर से दी जाएगी।

शादियां किसी भी दशा में ठीक नहीं

वैसे भी देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक व आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताएं न सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए है बल्कि सात फेरे लेने के लिए भी धीरे-धीरे विख्यात हो रही है। देवभूमि में ही वो स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। उत्तराखंड में त्रियुगीनारायण मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में पहले से ही विद्यमान है। इस धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व के डेस्टीनेशन पर सात फेरे लेने का आकर्षण युवाओं में बढ़ रहा है। इसी तरह धर्मनगरी हरिद्वार में शांतिकुंज में बड़ी संख्या में जोड़े विधि-विधान के साथ जन्म-जन्मांतर के बंधन में बंध रहे हैं तो तीर्थनगरी ऋषिकेश भी देश-विदेश के लोगों के लिए बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इसी तरह मसूरी, नैनीताल, रामनगर समेत सर्व सुविधा संपन्न स्थलों में विवाह समारोह आयोजित करने का चलन बढ़ रहा है। विशुद्ध रूप से प्रकृति की गोद में विवाह के लिए औली जैसे स्थल भी यहां हैं। जिस तरह से पर्यटन व तीर्थाटन के लिए सरकार सुविधाएं विकसित कर रही है, उससे यहां विवाह करने का आकर्षण भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड में त्रियुगीनारायण मंदिर के अलावा शांतिकुंज हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, मसूरी, देहरादून, औली, चकराता, हर्षिल, काणाताल, टिहरी झील, नरेंद्र नगर, नैनीताल, रामनगर, ब्रह्मताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, रानीगढ़, नौकुचियाताल, घोड़ाखाल, गोल्ज्यू मंदिर, चितई गोल्ज्यू मंदिर आदि यहां भी वैवाहिक संस्कार होते हैं, लेकिन स्थानीय लोग ही यहां शादी करते हैं। यदि इन स्थलों को विकसित किया जाए तो यहां दूर दूर से लोग वैवाहिक संस्कार के लिए आकर्षित होंगे। हालांकि चिपको आंदोलन से जुड़े नेता चंडीप्रसाद भट्ट का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में एक साथ बहुत ज्यादा लोगों का जाना और शादी जैसे बड़े समारोह करना किसी भी दशा में ठीक नहीं है। हिमालयी ग्लेशियरों पर कई डॉक्यूमेंट्री बना चुके टीवी पत्रकार का मानना है कि वेडिंग डेस्टिशन के लिए सरकार को हर तरह की सुविधाएं खुद उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोग आएं, शादी करें और चले जाएं। वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर प्राकृतिक ढ़लान पर मनमानी करने की छूट देना, अस्थाई रूप से तम्बू का शहर बनाना, पहाड़ के लिए ठीक नहीं है। इससे पर्यटन का कोई विकास नहीं होने वाला। पर्यटन के नाम पर सिर्फ एक स्ट्रॉयड का इंजेक्शन है, जिसका असर खत्म होने के बाद सामने आएंगा।

देहरादून के दामन पर दाग

देहरादून नगर निगम की 7560 हेक्टेयर भूमि गायब

देहरादून में 75 मलिन बस्ती चिह्नित थीं, 2002 में नगर निगम बनने के बाद ये 102 हो गईं, 2008-09 में हुए सर्वे में यह आंकड़ा 123 तक पहुंच गया, 2009 के बाद चिह्नीकरण नहीं हुआ, अनुमान है कि वर्तमान में देहरादून में 159 अवैध मलिन बस्ती और 40 हजार से अधिक घर हैं।

डा.भारत भूषण
आईएफटीएम यूनि.

उत्तर प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तब यूपी के इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नारे फिजाओं में हमेशा तैरते रहते थे। आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो...,मडुवा, झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे...। 2000 में केंद्र में अटल विहारी बाजपेयी की सरकार थी लिहाजा एक अधिसूचना जारी हुई और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी व तराई के हिस्से को एक अलग उत्तराखंड राज्य का दर्जा मिल गया। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी को लेकर विवाद रहा लेकिन तब देहरादून को अस्थाई राजधानी बना कर राजकाज शुरू हो गया। पहाड़ के लोग चाहते थे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, लेकिन चालाक राजनीतिज्ञों ने अपनी सुविधा देखी और उत्तराखंड को ही राजधानी बना दिया। इसके नतीजे कुछ ही दिनों में नजर आने लगे और कुकुरमुत्तों की तरह मलिन बस्तियां उगती चली गईं। सत्ता और विपक्ष में बैठे सियासतदारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लिहाजा देखते ही देखते बिंदाल-रिस्पना समेत देहरादून के तमाम नदी-नालों के किनारे बाहरी लोग झुग्गी-झोपड़ी व कच्चे मकान बनाकर बसते चले गए। वोटों की राजनीति करने वाले दलों ने अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ी और मकान बनाकर रहने वाले परिवारों के वोटर आई-डी कार्ड बनवा दिए। आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक बनवा दिए। बिजली पानी के कनेक्शन दिला दिए, सड़कों का निर्माण करा दिया। 23 वर्ष के हो चुके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हालत अब ये है कि इस बेहद खूबसूरत शहर के माथे पर 129 से अधिक मलिन बस्तियों का काला दाल लग चुका है। अब इनके कम होने के आसार नहीं है, बल्कि ये लगातार बढ़ ही रही हैं। इन्हीं बस्तियों के बीच मस्जिद बन चुकी है, मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इन मलिन बस्तियों में 40 हजार से अधिक परिवार बस चुके हैं। इन परिवारों में करीब एक लाख से अधिक मतदाता हैं। मतदाताओं की यह संख्या किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए काफी है। यही वजह है कि प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, मलिन बस्तियों को वोट बैंक बनाने का क्रम निरंतर चलता रहता है।

अवैध बस्तियों पर सियासत मेहरबान

वोटों की राजनीति करने वाले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में इन अवैध मलिन बस्तियों को वैध बना दिया गया, जबकि उत्तराखंड में नजूल की भूमि पर बसे लोगों को देश की आजादी के बाद से आज तक भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। वोट बैंक की सियासत करने वालों पर आरोप है कि भले ही वैध कालोनी में नियमानुसार आवास बनाने वालों को बिजली-पानी का कनेक्शन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़े, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को बिजली के कनेक्शन भी आसानी से मिल जाते हैं। पेयजल की सुविधा भी नेता करा देते हैं। इन अतिक्रमणकारियों से कोई प्रमाण-पत्र भी नहीं मांगा जाता है। मसलन जिस स्थान पर वो बिजली का कनेक्शन चाहते हैं उस स्थान पर वो मकान के मालिक कैसे है? जबकि बिजली विभाग कानून के दायरे में रहकर अपनी जमीन पर आवास बनाने वाले से कई तरह के दस्तावेज जमा कराते हैं। किरायेदार यदि अलग बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे मकान मालिक से अनापत्ति सर्टिफिकेट और शपथ लेना पड़ता है। यदि अवैध कब्जेदारों से ये दस्तावेज मांगे जाएं तो उन्हें कभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता। इसके लिए बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किंतु अवैध बस्तियों में बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं नेताओं के दबाव में पहुंच ही जाती हैं। कभी नगर निगम या प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने का प्रयास किया तो जनप्रतिनिधि ही उनकी ढाल बनकर आगे खड़े हो जाते हैं। विडंबना देखिए कि न तो अवैध बस्तियों को कभी हटाया जा सका, न उनका नियमितीकरण ही किया गया। हैरानी की बात ये है कि सभी सरकारों ने अवैध मलिन बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने का आश्वासन दिया और चुनाव में समर्थन मांगा। इस संबंध में तीन बार नियमितीकरण को लेकर अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन अब भी इनके स्थाई समाधान के आसार दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे।

23 वर्ष के हो चुके उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के माथे पर 129 से अधिक मलिन बस्तियों का कलंक लग चुका है, अब इनके कम होने के आसार नहीं है, बल्कि ये लगातार बढ़ ही रही हैं, इन्हीं बस्तियों के बीच मस्जिद, मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे हो चुके हैं।

वोट बैंक का लालच

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवैध मलिन बस्तियां कुकुरमुत्ते की तरह उगी तो धीरे-धीरे देहरादून के नदी-नालों के किनारे हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हो गए। वोट के लालच में सरकारें अवैध निर्माण तोड़ने के बजाय इनके संरक्षण के तरीके खोजती रहीं। नेताओं की सरपरस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे होते रहे और बाहरी लोगों की घुसपैठ बढ़ती रही। अब खूबसूरत शहर देहरादून बदरंग होता जा रहा है। राज्य बनने से पहले देहरादून नगर पालिका थी और देहरादून में 75 मलिन बस्ती चिह्नित थीं, लेकिन 2002 में नगर निगम बनने के बाद इनकी संख्या 102 तक पहुंच गई। 2008-09 में कराए गए सर्वे में यह आंकड़ा 123 तक पहुंच गया। 2009 के बाद से बस्तियों का चिह्नीकरण नहीं हुआ। सरकारी अनुमान है कि वर्तमान में देहरादून में 159 अवैध बस्ती और 40 हजार से अधिक घर बन चुके हैं। देहरादून में बीते 23 वर्षों के दौरान हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुकी। नगर निगम के पास करीब 7,800 हेक्टेयर भूमि थी, इसमें से 7560 हेक्टेयर भूमि गायब हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर निगम की इस भूमि को कौन निगल गया? क्या राजनीतिक संरक्षण में भूमि माफिया नगर निगम का एक बड़ा रकबा निगल गए? क्या नगर निगम की भूमि को खुर्दबुर्द करने में राजनेताओं का भी हाथ रहा है? भू माफिया वन क्षेत्र में भी सरकारी जमीन निगल रहे हैं और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन न सरकार की नींद टूट रही, न नगर निगम के साथ वन और सिंचाई विभाग की। अवैध खरीद-फरोख्त के साथ ही बस्तियों के रूप में अवैध कब्जे और धीरे-धीरे निर्माण कर सरकारी जमीनों को लूटा जा रहा है और वोट की लालची सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं।

देहरादून की डेमोग्राफी बदली

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अवैध बस्तियों की वजह से जनसंख्या असंतुलन से चिंतित धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस समस्या पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू से मिलकर चिंता जाहिर की और प्रभावी कदम उठाने की मांग की थी। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे से पता चला कि यहां पिछले 10 सालों में जनसंख्या असंतुलन की बड़ी वजह बढ़ती मुस्लिम आबादी है। यहां की मतदाता सूची में 170 फीसदी की वृद्धि हुई है। धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली देहरादून नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि पूरे देहरादून निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोग कब्जा करके बसते जा रहे हैं। 2018 में निगम क्षेत्र के विस्तार में शामिल 72 गांवों के भूमि दस्तावेज, निगम में हस्तांतरित नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहां हजारों लोग अवैध कब्जा करके बसते गए। अवैध कब्जेदारों ने ग्राम पंचायतों की जमीन, नदी, नाले, रोखड़ कुछ नहीं छोड़ा है और अब ये अवैध कब्जे नासूर बन गए हैं। विधायक का कहना है कि सरकारी जमीनों को खुर्दबुर्द करने में भू-माफिया खेल कर रहे हैं। इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने है कि उन्होंने देहरादून वन प्रभाग और मसूरी वन प्रभाग की बेशकीमती जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। विधायक विनोद चमोली का कहना है कि मोथरोवाला क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर कब्जे आखिर कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? 2018 से ये खेल चल रहा है, किंतु इस बारे में शासन कुछ नहीं कर रहा है। देहरादून में सहस्त्रधारा, रायपुर क्षेत्र से सटी वन भूमि पर अवैध रूप से गैरहिंदू आबादी ने कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी दर्ज की गई है। 200 बीघा जमीन पर मुस्लिम गुज्जर आकर अवैध रूप से बस गए हैं।

- **राजधानी देहरादून में अवैध मलिन बस्तियां कुकुरमुत्ते की तरह उगी तो धीरे-धीरे देहरादून के नदी-नालों के किनारे हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हो गए, वोट के लालच में सरकारें अवैध निर्माण तोड़ने के बजाय इनके संरक्षण के तरीके खोजती आ रहीं हैं।**
- **भले ही वैध कालोनी में नियमानुसार आवास बनाने वालों को बिजली-पानी का कनेक्शन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़े, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को बिजली के कनेक्शन आसानी से मिल जाते हैं, पेयजल की सुविधा भी नेता करा देते हैं।**

वादे तो झूठे निकले हैं दावे भी खोखले,
फिर भी है कुर्सियों पर सियासत तो देखिये,
तब्दीलियों के नाम पर कुछ भी नया नहीं,
बनने को बन गई है सियासत को देखिये...।

जनकवि बल्ली सिंह 'चीमा' की लिखी गजल की ये लाइनें उत्तराखंड के हालातों पर सटीक बैठती हैं। लंबे जनसंघर्ष और 42 कुर्बानियों के बाद मिले अलग उत्तराखंड राज्य में विकास कार्य तो हुए लेकिन पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल ज्वलंत बने हुए हैं। 2023 के अंत में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट लांच किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 18 शहरों का चयन किया गया है। इस लिस्ट में स्मार्ट सिटी देहरादून शामिल नहीं है। इससे पहले सिटीज 1.0 में देहरादून का नाम शामिल था। लिहाजा अब देहरादून में नए प्रोजेक्ट की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, साथ ही सिटीज 2.0 से कचरा निस्तारण के लिए मिलने वाले 119 करोड़ रुपये भी देहरादून को नहीं मिलेंगे। जहां आम जनता स्मार्ट सिटी के अधूरे काम से परेशान थी, वहीं इस लिस्ट के सामने आने के बाद देहरादून नगर निगम को जोर का झटका लगा है। राजधानी देहरादून के निवासी कहते हैं कि 2019 में राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया। शहर में बहुत सी सड़कों पर गड्ढे आज भी नजर आते हैं। गड्ढों वाली सड़कों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। स्ट्रीट लाइट का काम भी अधूरा रह गया है। न ही उत्तराखंड पावर कारपोरेशन का अंडरग्राउंड वायरिंग का काम पूरा हो पाया है। रेलवे स्टेशन के आसपास और सहारनपुर चौक के पास सीवर और पाइप लाइन डालने का काम अभी तक चल ही रहा है। जिससे जनता बहुत परेशान हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेशक सपनों का एक नया शहर बसाने की ओर कदम बढ़ाए, मगर इस सुनहरे सपने के पीछे दस लाख देहरादून के निवासियों के सारे ख्वाब और उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे पिछले 15 साल से राजधानी का बोझ ढो रहे देहरादून शहर की उम्मीदें तिल-तिल दम तोड़ रही हैं। सवाल यह है कि हरे-भरे बागान और सैकड़ों एकड़ जमीन पर सरकार नई स्मार्ट सिटी तो विकसित कर लेगी, मगर देहरादून के उन बाशिंदों को क्या हासिल होगा, जो डेढ़ दशक से दून की खुशहाल तस्वीर को बदहाली के गुब्बार से बदरंग होते देखते आए हैं। सरकार के दायित्वबोध का यह आलम तब है, जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पुराने देहरादून को स्मार्ट दून में बदलने के सभी विकल्प व संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन सच ये भी है कि स्मार्ट सिटी के माथे से अवैध मलिन बस्तियों का कलंक कैसे मिटेगा, कौन मिटाएगा?

उत्तराखंड बनाकर क्या मिला

एक अनुमान के अनुसार 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी, शहरों में अधिक आबादी का मतलब है कि उनका आधारभूत ढांचा संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ सहने में समर्थ रहें, साथ ही रहने लायक भी बने रहें।

डॉ. हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

शिक्षा मानव को न केवल विद्वान बनाती है बल्कि वास्तविक शिक्षा उन्हें जीवन में चरित्रवान बनने का पाठ भी पढ़ाती है। जीवन यापन के लिए अवसर जुटाना, राष्ट्र के विकास के लिए उपयुक्त मार्ग खोजना, मानव मूल्यों के प्रति संवेदना जगाना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा कही जाती है। भारत ने इस तथ्य को भारतीय संस्कृति के उदय के समय ही आत्मसात कर लिया गया था। इसलिए भारत न केवल अपनी संस्कृति एवं दर्शन के लिए दुनिया में जाना जाता है, बल्कि एक पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है। आजादी के बाद भारत के लिए न केवल बुनियादी शिक्षा का प्रसार महत्वपूर्ण हो गया बल्कि उच्चशिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ाना भी चुनौती बन गया था। यानी युवाओं को कैसे शिक्षित व प्रशिक्षित करें। इसी उद्देश्य से तत्कालीन भारत सरकार ने उच्चकोटि के शिक्षाविदों एवं विचारकों के अधीन शिक्षा आयोग का गठन किया था। आजाद भारत में सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पहला शिक्षा आयोग बना। उच्चशिक्षा सहित हर स्तर की शिक्षा के विकास व संवर्धन के लिए बनाया गया यह पथप्रदर्शक दस्तावेज सरकारों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों व छात्रों के सुझावों, कार्य योजनाओं व देश में शिक्षा के माध्यम से आर्थिक प्रगति करने के उपायों से परिपूर्ण था। इसको भारतीय परंपराओं, तत्कालीन परिस्थितियों एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसके द्वारा अपेक्षा की गई कि हमारी शिक्षा ऐसी होगी जो ऐसे युवाओं को तैयार करेगी जो अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्य कर समाज सुधार एवं जनतांत्रिक प्रणाली को सफल बना सकें। आजादी के बाद उच्चशिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, ताकि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के माध्यम से इसका संचालन किया जा सके। परंतु दुर्भाग्य से शिक्षा के लिए बजट की सीमा इतनी कम रखी गई कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं आधारभूत संसाधनों के अभाव, शिक्षकों की कमी एवं बढ़ती छात्र संख्या के कारण अपेक्षित दक्ष मानव संसाधन नहीं जुटा पाई।

आयोग बने पर गुणवत्ता नहीं सुधरी

समय-समय पर विभिन्न आयोगों के माध्यम से शिक्षा की गुणवता सुधारने के उद्देश्य से नीतियों में परिवर्तन किया जाता रहा। किंतु पहाड़ में शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के दावे खोखले ही रहे। जहां-तहां मनमाने तरीके से राजनीतिक हित के लिए महाविद्यालय खोल दिए गए, लेकिन इनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। प्राचीन समय से ही शिक्षा व संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहे अल्मोड़ा जिले में लोग लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। कहीं शिक्षक हैं तो छात्र नहीं। कई जगह भवन भी नहीं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्थिति भी निराशाजनक है। पहाड़ी प्रदेश में 119 सरकारी महाविद्यालय हैं। इनमें 36 स्नातकोत्तर और करीब 83 स्नातक कालेज हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बड़े पीजी कालेजों को छोड़ दें तो अन्य छोटे महाविद्यालयों में विद्यार्थी कम प्रवेश ले रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार ने डिग्री कालेजों को इसलिए खोला था कि छात्रों का पलायन न हो। कालेज तो खोल दिए मगर इनमें संसाधनों की कमी हमेशा बनी रही है। कई कालेजों के पास अपने भवन तक नहीं हैं, छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। संसाधनों के अभाव में पहाड़ के ये कालेज छात्रों की पसंद नहीं बन पाए। पूर्व में खुले कालेजों में सामान्य कला, विज्ञान और वाणिज्य के कोर्स ही हैं। जबकि वर्तमान में प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिल रही है। ऐसे में छात्र इंटरमीडिएट के बाद प्रोफेशनल कोर्स करने हल्द्वानी और देहरादून का रुख कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में खोले गए कालेजों में सीटें खाली रहने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र को अपनी स्ट्रीम के साथ दूसरे संकाय के पसंदीदा विषयों को चुनने का विकल्प दिया गया है। मगर प्रदेश के कई यूजीसी कालेज ऐसे हैं जहां एकल संकाय ही संचालित है और उसमें भी सभी विषय नहीं हैं। ऐसे में छात्रों को अन्य पसंदीदा विषयों का विकल्प नहीं मिल पा रहा।

प्राचीन समय से ही शिक्षा व संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहे अल्मोड़ा जिले में लोग लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि कहीं शिक्षक हैं तो छात्र नहीं, कई जगह भवन भी नहीं हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्थिति भी निराशाजनक है।

न ही एनईपी की अवधारणा पूरी हो रही है। दो दशक पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा उत्तराखंड बाकी प्रदेशों की तुलना में नया प्रदेश है। यहां की भौगोलिक व जटिल परिस्थितियां इसके विकास में अलग प्रकार की समस्याएं पैदा करती रहती है। फिर भी यह स्कूली शिक्षा का एक बड़ा हब बना और उच्च शिक्षा के विकास में सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते रहे। दुनिया में आबादी के हिसाब से पहले स्थान पर पहुंच चुके भारत का उच्चशिक्षा तंत्र चीन व अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है। वतर्मान में देश में 47 केंद्रीय, 381 राज्य सरकारी, 123 डीम्ड और 291 निजी मिलाकर 900 के लगभग विश्वविद्यालय हैं।

शिक्षण संस्थाओं में समस्याएं ही समस्याएं

राज्य निर्माण के समय उत्तराखंड में मात्र 34 राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे। सहायता प्राप्त एवं निजी महाविद्यालयों की संख्या 60 के करीब थी जिनमें अधिकांश संस्कृत की शिक्षा से संबंधित थे। राज्य में 2000 से पूर्व तीन राजकीय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय और दो राष्ट्रीय महत्व के उच्चशिक्षा संस्थान थे। पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इनमें सामान्य विषयों के अतिरिक्त तकनीकी, चिकित्सा, आयुर्वेद, कृषि, संस्कृत, प्रबंधन से संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शामिल हैं। आज उत्तराखंड में 11 राजकीय व 25 निजी विश्वविद्यालयों के अधीन 114 राजकीय, 17 अनुदानित और 394 स्ववित्तपोशित उच्चशिक्षण संस्थान हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईटीआई रुड़की, एम्स ऋषिकेश, आईआईएम, एनआईटी सहित राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 7 है। इतने नए व छोटे राज्य में इतनी बढ़ी संख्या में शिक्षण संस्थाएं होने पर हम गर्व कर सकते हैं। परंतु इनमें समस्याओं का अम्बार भी उतना ही बड़ा है। जिससे हम शर्मिन्दा हो सकते हैं। क्योंकि वर्षों से कई महाविद्यालय भूमि व भवन की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि हाल में इस स्थिति में कुछ सुधार देखा गया है। 106 राजकीय महाविद्यालयों में से 102 के अपने भवन हैं। कुछ का विस्तार हो रहा है व कुछ निर्माणाधीन हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए सभी स्तर में सुधार करने और देश की युवा पीढ़ी को कौशल विकास एवं रोजगार के अधिक अवसर देने के उद्देश्य से 2020 में नई शिक्षा नीति बनाई। इस नीति के तहत छात्रों के समग्र विकास के लिए संस्थागत पुनर्गठन एवं समेकन के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए अनूकूल वातावरण बनाना एवं छात्रों में सहयोग की भावना पैदा कर सक्रिय संकायों की स्थापना करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 का प्रदेश में अधिग्रहण कर लिया गया है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सक्रियता दिखाने के निर्देश व अपेक्षा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। लिहाजा उत्तराखंड में टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। नई नीति में उच्चशिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्र व राज्यों के स्तर पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में विश्वविद्यालयों के स्तर पर पाठ्यक्रमों को सुधारकर उन्हें शिक्षण एवं शोध के लिए बहुविषयक बनाना है। सभी एकल विषयक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक करना भी नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इस नीति के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही हैं। परंतु किसी भी अच्छी नीति का यदि क्रियान्वयन संपूर्णता से न हो तो नीति ही विफल हो जाती है। लिहाजा सरकारों, नागरिकों, शिक्षकों व छात्रों का योगदान शिक्षा की गुणवता सुधारने में होना चाहिए।

शिक्षकों की जवाबदेही

कक्षा में पढ़ाई संबंधी कार्यों की तुलना में गैर-शैक्षणिक कार्य को प्राथमिकता देने की दिशा में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मुद्दों पर आधारित ईमानदारी की अपेक्षा की जा रही है, वह वोटों की राजनीति में कहीं खो गई है। उत्तराखंड के गठन में आमजन का संघर्ष रहा है, लेकिन जब राज्य के बारे में सोचने व सरकारों के काम के आकलन का मौका आया तो सभी सरकार से अपनी मांगें मनवाने में लग गए। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन ही कम काम बेहतर पगार, अधिक पदोन्नति और ज्यादा सरकारी छुट्टियों, भर्तियों में अनियमितता व विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में समझौता करने के लिए हुआ है। मानो विकास का मतलब कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालों व मेडिकल कालेजों के ज्यादा से ज्यादा भवन बनाना भर है, न कि उनके बेहतर संचालन की व्यवस्था करना। हर साल सड़कें बनाना मकसद है, पर हर साल ये क्यों उखड़ रही हैं, इसकी चिंता न तो सरकारें करती हैं और न ही विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। जाहिर है कि करोड़ों रुपये के निर्माण में पक्ष-विपक्ष दोनों के अपने स्वार्थ हैं। उस

यूपी का विभाजन हुआ तो माना जा रहा था कि अब नवोदित उत्तराखंड राज्य की राजनीति अलग होगी, लेकिन आज भी उत्तराखंड यूपी की ही राजनीतिक विरासत ढो रहा है, सिर्फ बाहुबल की राजनीति से निजात मिली है, बाकी सारी तिकड़म वहां भी है और यहां भी हैं।

वर्षगांठ को मनाने का औचित्य ही क्या है जिसमें उपलब्धियों व विफलताओं की बैलेंस सीट ईमानदारी से न खंगाली जाए। अब लोग भी यह पूछने लगे हैं कि अलग राज्य बनने के बाद ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश में ही रहते तो नहीं हो पाता? सत्ता के सिंहासन पर बारी-बारी से दल तो बदले, लेकिन काम के तौर-तरीके नहीं। नौकरशाही का खामियाजा जनता ने भुगता, लेकिन सत्ताधारी तो इसमें भी मुनाफा कमा गए। हर विफलता के लिए नौकरशाही को कोसने वाले सफेदपोश व्यक्तिगत स्तर पर लाभार्थी ही रहे हैं।

यूपी की विरासत ढो रहा उत्तराखंड

जब यूपी का विभाजन हुआ तो माना जा रहा था कि अब नवोदित उत्तराखंड राज्य की राजनीति अलग होगी, लेकिन यह हुआ नहीं। आज भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की ही राजनीतिक विरासत ढो रहा है। सिर्फ बाहुबल की राजनीति से ही निजात मिली है, बाकी सारी तिकड़म की राजनीति वहां भी है और यहां भी हैं। मतदाताओं के सामने खड़ी समस्याओं के समाधान से अधिक उनकी भावनाओं के दोहन की फिक्र रही है। कर्मचारी-शिक्षक सबसे बड़ा वोट बैंक बन कर उभरा है। हालात ये है कि आर्थिक स्थिति कैसी भी हो कर्मचारी-शिक्षक यूनियनों के सामने सरकारें झुक जाती हैं। शायद इसलिए 23 साल बाद भी प्रदेश में आर्थिक-औद्योगिक प्रगति केंद्र की मदद के बाद भी गति नहीं पकड़ पाई। विकास जो हो रहा है वह पूरी तरह से केंद्र के भरोसे है। पीएम के उत्तराखंड के प्रति सकारात्मक रुख से ही ढांचागत विकास हो रहा है, पर सवाल है कि इतने सालों में प्रदेश इनका लाभ लेने की स्थिति में भी पहुंचा या नहीं? 23 साल, 12 मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक अस्थिरता की कहानी ही बयां करते हैं। अब सरकारी योजनाएं ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी रहेंगी, बल्कि मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक ऐसी योजनाओं पर हरपल नजर रखेंगे। सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए इंफार्मेशन डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) ने पोर्टल तैयार किया है, लेकिन पहाड़ के विकास के लिए कोई भी गंभीर नहीं है और पलायन जारी है। फिर ऐसे अलग राज्य के गठन से क्या फायदा?

आधारभूत ढांचा संवारने की जरूरत

पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्तराखंड में योजनाओं को लागू करने में कई तरह की दिक्कत आती हैं, लेकिन जब सरकार की इच्छाशक्ति जागी, तो योजनाएं भी परवान चढ़ी, लेकिन जब राज्य सरकार वोट बैंक और राजनीतिक लाभ के लिए विकास कार्यों को टालती है तो इसका नुकसान भी जनता को उठाना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी। शहरों में अधिक आबादी रहने का मतलब है कि उनका आधारभूत ढांचा संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ सहने में समर्थ रहें। साथ ही रहने लायक भी बने रहें। आबादी में वृद्धि के कारण शहरों में हर साल लाखों वर्ग मीटर जमीन की व्यवस्था करनी होगी। कोई भी समझ सकता है कि जमीन शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगरीय क्षेत्र घोषित करने से ही हासिल होगी। ग्रामीण क्षेत्र तेजी के साथ शहरों में समा जाएंगे, लेकिन ऐसे क्षेत्रों का विकास बेहद कामचलाऊ ढंग से होगा। क्योंकि जिन सरकारी विभागों पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है वे नियोजित विकास के नाम पर खानापूरी ही करते हैं। जिससे नया ढांचा कुछ ही समय बाद चरमरा जाता है। समस्या ये भी है कि जहां शहरों में नए इलाकों का अनियोजित विकास होता है वहीं पुराने इलाकों के जर्जर होते ढांचे को दुरुस्त करने से बचा जाता है। जिससे शहर गंदगी, जलभराव, प्रदूषण, अराजक यातायात, अतिक्रमण, सघन आबादी वाले मोहल्लों और झुग्गी बस्तियों से घिर जाते हैं। इन समस्याओं के मूल में शहरीकरण से जुड़े विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव है। बेहतर हो कि केंद्र सरकार, राज्यों को इसके लिए तैयार करे कि वे शहरीकरण की चुनौतियों से जूझने में गंभीरता का परिचय दें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को होने वाले पलायन की रफ्तार कम हो सके।

भारतीय संस्कृति की झलक 'वेदक'

वेद प्रकाश गुप्ता (वेद जी) की याद में उनकी मझली बेटी मीनू अग्रवाल बिष्ट ने 2015 में एक ऐसे शब्द की खोज की जो वेदजी के जीवन से किसी न किसी तरह जुड़ा हो, उनकी तलाश 'वेदक' शब्द पर आकर थमी, क्योंकि 'वेदक' का अर्थ ज्ञान बांटने वाले से है।

य

कृष्ण कुमार चौहान

शस्वी पत्रकार, सामाजिक, राजनैतिक चिंतक और खुद की मेहनत और लगन से कारोबार की बुलंदियों तक पहुंचने वाले कर्मयोगी वेदप्रकाश गुप्ता (वेदजी) उत्तराखंड के लिए अपरिचित या अनसुना नाम नहीं है। उत्तरांचल दीप और बीएलएम स्कूल के संस्थापक वेदजी अब हमारे बीच नहीं हैं, छह सितंबर 2014 को वेद जी पंचतत्वों में विलीन हो गए, लेकिन उनके संस्कार, उनके आदर्श, उनकी कार्यशैली हमेशा हमारा मार्ग दर्शन करती है। वेद जी की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को संभालने से लेकर उनकी विचारधारा को जीवित रखने के लिए वेद जी का परिवार पूर्ण आत्मीयता के साथ उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा है। वेद जी की याद में उनकी मझली बेटी मीनू अग्रवाल बिष्ट ने 2015 में एक ऐसे शब्द की खोज की जो वेदजी के जीवन से किसी न किसी तरह जुड़ा हो, उनकी तलाश 'वेदक' शब्द पर आकर थमी, क्योंकि 'वेदक' का अर्थ ज्ञान बांटने वाले से है। मीनू अग्रवाल बिष्ट ने कर्मयोगी अपने पिता के नाम से 2015 में सांस्कृतिक, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के संगम का 'वेदक' से आगाज किया। पापा की लाडली मीनू अग्रवाल बिष्ट ने पहले ही साल नूपूर वैलफेयर सोसायटी के माध्यम से वेद प्रकाश गुप्ता छात्रवृत्ति देने की घोषणा ही नहीं की बल्कि आठ शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देना भी शुरू कर दिया। मीनू अग्रवाल बिष्ट हल्द्वानी (नैनीताल) में 'नूपूर नृत्य कला केंद्र' का संचालन करती है और नूपूर वैलफेयर सोसायटी की संस्थापक हैं। मीनू अग्रवाल बिष्ट कहती हैं कि वेद जी के जन्मदिन पर फरवरी 2015 में वह 'वेदक' का आगाज करना चाहती थीं, लेकिन कलाकारों और नृत्य तथा संगीत की शिक्षा लेने वाले बच्चों की स्कूली परीक्षा की तैयारी को देखते हुए यह कार्यक्रम अप्रैल में करने का फैसला किया। अप्रैल 2015 में उन्होंने अपने ही नूपूर नृत्य कला केंद्र के छात्रों को तैयार कर एक दिवसीय 'वेदक' की नींव रखी। 'वेदक' में अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नूपूर वैलफेयर सोसायटी के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहले ही 'वेदक' कार्यक्रम में निर्णायक बाहर से बुलाए गए। ताकि कोई कार्यक्रम की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा न कर सके। पहला कार्यक्रम था लिहाजा उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी तो आयोजकों का हौसला परवान चढ़ा। दूसरा 'वेदक' अप्रैल 2016 में आयोजित हुआ। इस बार मीनू अग्रवाल बिष्ट ने पति देवेंद्र सिंह बिष्ट, मां आदेश अग्रवाल, बड़े भाई साकेत अग्रवाल, भाभी सौम्या अग्रवाल, बहन रीतू अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल की सलाह से कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी की, फिर ये सिलसिला साल दर साल शुरू हो गया। मीनू अग्रवाल बिष्ट को परिवार का अपेक्षित सहयोग मिला और 'वेदक' 2016 सीजन दो में कुमाऊंनी संस्कृति के साथ राजस्थान, असम और ओडिसी कलाकारों को उत्तराखंड की सरजमी पर आमंत्रित किया गया। जिन्होंने कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य जोहरी, राजस्थानी लोकनृत्य, ओडिसी कथक नृत्य और असम के कलाकारों ने अपने राज्य के लोकप्रिय संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया।

पहली बार कुमाऊं में परदेशी कलाकार

पहली बार कुमाऊं में परदेशी कलाकारों ने जो समा बांधा उसने 'वेदक' की लोकप्रियता के शिखर का रास्ता खोल दिया। 'वेदक' का नाम उत्तराखंड से निकलकर राजस्थान, असम, ओडिसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पहचाना जाने लगा। सीजन दो के बाद तो कलाकारों और संस्कृति व संगीत प्रेमियों को 'वेदक' का बेताबी से इंतजार रहने लगा। 'वेदक' सीजन तीन में हिस्सा लेने वाले बाल कलाकारों के साथ बड़े कलाकारों की कतार लगनी शुरू हो गई। 'वेदक' 2017 सीजन तीन की तैयारी के दौरान ही स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया। मीनू अग्रवाल बिष्ट ने नूपूर नृत्य कला केंद्र में स्थानीय कलाकारों की कला और हुनर को निखारा और फिर सीजन तीन में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का भरपूर मौका मिला। 'वेदक' सीजन तीन, पहले और दूसरे सीजन के मुकाबले और भी भव्य विस्तार के साथ हुआ तो यादगार बन गया। 'वेदक' 2018 सीजन चार ने तो सारे रिकार्ड तोड़ दिए। क्या राजनेता, क्या समाजसेवी, क्या कला प्रेमी और क्या पब्लिक सब का ऐसा सैलाब उमड़ा कि आयोजन स्थल पर दो दिन तक पैर रखने के लिए भी स्थान का अभाव बना रहा। सीजन चार के बाद कोविड-19 ने पैर पसारे तो सालाना होने वाले 'वेदक' कार्यक्रम को स्थिगित करना पड़ा। लेकिन 2024 में एक नए अंदाज में नए कलाकारों, नई थीम के साथ 'वेदक' का पुनः आगाज हुआ है। फिर से स्कूली और गैरस्कूली प्रतिभाओं को मंच दिया गया। गायन, वादन, और नृत्य के साथ इस बार नया था तो महिलाओं का साड़ी में रैंप वॉक। जिसमें हर आयुवर्ग की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस तरह कोविड-19 के बाद एक बार फिर से भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेजने की शुरूआत हुई। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोग डांस, नृत्य नाटिका, लोकनृत्य, कुमाऊंनी नृत्य आदि का संगम 'वेदक' 2024 में देखने को मिला।

संपूर्ण रामायण की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका हर पात्र अपना अभिनय करते समय पूरी तरह एकाग्रचित था, जिससे छोटे से लेकर बड़े सब रामायण के एक-एक दृश्य को आसानी से समझ रहे थे, इसलिए दर्शक दीर्घा की तरफ से तालियों की आवाज रुक नहीं रही थी।

'वेदक' पीछे उद्देश्य

'वेदक' की शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य है? यह भी स्पष्ट करना जरूरी है। दरअसल वेद जी की मझली बेटी मीनू अग्रवाल बिष्ट खुद जानी मानी क्लासिकल संगीत और नृत्य कलाकार हैं। किशोरावस्था में मीनू अग्रवाल बिष्ट ने शास्त्रीय संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की तो वेद जी ने एक बार रोकने की कोशिश की, लेकिन मां आदेश अग्रवाल ने बेटी की इच्छा को पंख लगाने के लिए वेद जी को मना लिया था। मीनू अग्रवाल ने शास्त्रीय संगीत में परिवार और हल्द्वानी का नाम रोशन किया तो वेद जी ने बेटी की हर मुश्किल को आसान करने का रास्ता खोल दिया। कर्मयोगी पिता वेद जी के सपनों को साकार करने, उनके मिशन को आगे बढ़ाने और लोगों के दिलों में वेद जी की यादें 'वेदक' के माध्यम से ताजा करना मीनू अग्रवाल बिष्ट का अब मिशन बन गया। मीनू अग्रवाल बिष्ट कहती है 'वेदक' एक वह जरिया है जब मंच से वेद जी को नेता और समाजसेवी याद करते हैं, समाज के लिए किए गए वेद जी के कार्यों की सराहना करते हैं। उनको कर्मयोगी, महान चिंतक, यशस्वी पत्रकार बताते हैं तो हमारा परिवार गर्व महसूस करता है। वैसे आज वह दौर है जब लोग अपनों को भी याद नहीं रख पाते।

'वेदक' के अंतिम प्रोग्राम रामायण ने दर्शकों को बांधे रखा, रामायण में राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ से लेकर राम जन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, राम वनवास, सीता हरण, रावण वध तक और राम के अयोध्या लौटने तक की लीला का बेहद रोचक तरीके से प्रदर्शित किया गया।

रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति

'वेदक' के आखिरी दिन सबसे ज्यादा जो पसंद किया गया वो कार्यक्रम था संपूर्ण रामायण। 'वेदक' के अंतिम दिन और अंतिम प्रोग्राम ने दर्शकों को बांधे रखा। रामायण में राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ से लेकर राम जन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, राम वनवास, सीता हरण, रावण वध तक और राम के अयोध्या लौटने तक की लीला का बेहद रोचक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि रामायण का हर पात्र अपना अभिनय करते समय पूरी तरह एकाग्रचित था। जिससे छोटे से लेकर बड़े सब रामायण के एक-एक दृश्य को आसानी से समझ रहे थे, इसलिए दर्शक दीर्घा की तरफ से तालियों की आवाज रुक नहीं रही थी। रामायण के इस कार्यक्रम को लेकर नूपूर नृत्य कला केंद्र की संचालक मीनू अग्रवाल बिष्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण रामायण को एक से डेढ़ घंटे में पूरा करने के लिए उनके साथ नूपुर नृत्य कला केंद्र की सहयोगी हिमानी बिष्ट, विजय पांडे, चित्रा ढेला, दीपा, भारती, शैलेंद्र नयाल, आशा और दिल्ली से आए कलाकार श्रुति सिन्हा और अमन पांडे ने लगातार मेहनत की। उन्होंने बताया कि दो दिन के इस कार्यक्रम में ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित डीपीएस, जेसीज पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी के बीएलएम एकेडमी, केवीएम पब्लिक स्कूल, महऋषि विद्या मंदिर, डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों न 'वेदक' के मंच पर अपनी बेहतर से बेहतर प्रस्तुति दी।

मुझे याद है कि 'वेदक' सीजन चार में ही 'यशस्वी पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता (वेद जी) को समर्पित' उत्तरांचल दीप मैगजीन का विमोचन उत्तराखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी, लालकुआं के विधायक नवीन दुम्का, कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने हजारों कला प्रेमियों की उपस्थिति में किया था। उत्तरांचल दीप मैगजीन अब अपने 6 साल पूरे कर चुकी है। इन 6 वर्षों में उत्तरांचल दीप मैगजीन ने उत्तराखंड के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में अपनी पहचान बनाई है। उत्तराचंल दीप मैगजीन को पढने वाले इसे नेशनल मैगजीन का दर्जा देते हैं। हमारे पाठकों का दायरा लगातार बढ़ा है, जो साबित करता है कि उत्तरांचल दीप मैगजीन ने अपनी लेखनी और कंटेंट के दम पर समाज में एक संतोषजनक पहचान अवश्य बना ली है।

सोशल मीडिया के ज्ञानदाता

वैसे तो मुख्यतः पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिह्न, संबोधन कारक चिह्न, उद्धरण चिह्न आदि कुल 16 प्रकार के ही व्याकरण चिह्न बताए गए हैं, पर आज का फेसबुक राइटर पता नहीं इनसे भी अधिक व्याकरण चिह्न कहां से लाकर अपने लेख को ऐसे सजाता है, मानो लेख न होकर चौकला या पिज्जा हो।

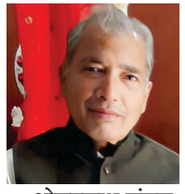

ओमप्रकाश मंजुल
पूरनपुर पीलीभीत

भारत में इंटरनेट की सुविधा बाकी मुल्कों के मुकाबले सस्ती है, लिहाजा देश में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर विशेषकर 'फेसबुक,' 'व्हाट्सएप' प्लेटफार्म पर अच्छे-अच्छे लेखकों और विचारकों के सामयिक और विचारोत्तेजक लेख भी पढ़ने को मिलते रहते हैं। भले ही ये लेखक किसी फेम या टाइप में अभी तक बंधे हुए न हों या पत्र-पत्रिकाओं में न छपने या कम छपने के कारण उतने लोकप्रिय और चर्चित न हो सके हों, किंतु व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे लेखकों व ज्ञानियों की भरमार होना अकारण नहीं है। इस पर एक प्रकार से ऐसे स्वयंभू लेखकों के आधिक्य का कारण है, 'सर्वतोभावेन स्वतंत्रता'। लेखक जैसा चाहे, जितना चाहे जो, जो चाहे वैसा लिखने के लिए स्वतंत्र है। वो जितना बड़ा चाहे, उतना बड़ा, कैसे भी तर्क और कुतर्कों वाला चाहे, वैसे कुतर्की लेख लिख सकता है। एक तरह से वह यहां एजी गार्डिनर के निबंध, 'सहयात्री' की तरह अपने सहयात्री (मच्छर) के साथ कैसा भी व्यवहार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, क्योंकि कोई भी यहां उसे नहीं देख रहा है। कोई उसकी कापी चैक नहीं कर रहा है, उसने जो लिख दिया वही सच है, वही साहित्य है, वही इतिहास है वही सब कुछ है, यानी उससे बड़ा कोई दूसरा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में शायदत नहीं है। ऐसा इन लेखकों के लेख पढ़ने से अहसास होता है?

सोशल मीडिया एक फूहड़ नायिका

पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में लेखन कई प्रकार की सीमाओं और वर्जनाओं में बंधे होने के कारण न केवल कलेवर में सीमित हो जाते है, वरन संयत और शालीन भी हो जाते हैं। प्रिंट मीडिया जैसा चाहो और जो चाहो वैसा और वो लिखने की इजाजत नहीं देता। सोशल मीडिया का लेखन एक अस्त-व्यस्त-निर्वस्त्र और स्वेच्छाचारी यानी अनियंत्रित तथा फूहड़ नायिका जैसा है, तो प्रिंट मीडिया एक सौंदर्य के भार से सजी-संवरी-सिमटी गृहणी के समान है। सोशल मीडिया का लेखन, एक माडर्निका का हवा में उड़ने वाला लाल दुपट्टा है, तो प्रिंट मीडिया का लेखन एक पतिव्रता के सिर पर सुशोभित लाज के पूल्लू जैसा है। न्यूज पेपर और पत्र-पत्रिकाओं में लेखन उस शयन के समान है, जिसमें स्वास्थ्य और मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए आप पेट के बल, पीठ के बल, जिस करवट चाहें, उस करवट से अधनंगे, नंगधड़ंगे, सीने पर हाथ रखकर, मुंह को कैक्टस के फूल की तरह खोलकर जैसा चाहें, वैसे नहीं लेट या सो सकते। वहां तो लेटने-सोने के भी नियम और कायदे हैं साथ में आचार संहिता भी लागू होती है। पर सोशल मिडिया या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में लेखन रूपी शयन में आप चारपाई का प्रयोग, उपयोग, दुरूपयोग कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। चाहें जिस अंग के बल पर, चाहें जिस करवट लेटिए-सोइए। चाहें दोनों पैर पूरे फैलाइए, चाहें डेढ़ फैलाइए, चाहें तो केवल एक ही फैलाइए और चाहें तो उसे भी न फैलाइए। चाहें सिर को नीचे और पैरों को ऊंचाई पर रखिए, चाहें सिर और पैर दोनों को चारपाई के सेंटर में पाटियों के समानांतर रखिए, चाहें सिर को पश्चिमोत्तर कोण में और पैरों को दक्षिण-पूर्व कोने में फेंक दीजिए। चाहें तो चारपाई पर केवल एक टांग को ही कष्ट दे सकते हैं और दूसरी टांग को नीचे लटका कर हवा को परेशान कर सकते हैं। हाथ यह न समझें मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं। वो भी यह कर सकते हैं। यानी आप सोशल मीडिया की चारपाई के साथ अपने अंग-उपांगों से कोई भी कोण बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

फेसबुक-लेखन का उदाहरण-वन

आपको एक अनुच्छेद के माध्यम से फेसबुक-लेखन का एक उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूं... दुनिया में इस समय दो ही बड़े लोकतंत्र हैं, भारत और अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबको पछाड़ चुका है यानी जनसंख्या के मामले में अमेरिका-भारत से बहुत फिसड्डी है। आबादी के लिहाज से अमेरिका को भारत की बराबरी करने में अभी सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे।

व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे लेखकों व ज्ञानियों की भरमार होना अकारण नहीं है, इस पर एक प्रकार से ऐसे स्वयंभू लेखकों के आधिक्य का कारण है, 'सर्वतोभावेन स्वतंत्रता', लेखक जैसा चाहे, जितना चाहे जो, जो चाहे वैसा लिखने के लिए स्वतंत्र है।

भारत की राजधानी, दिल्ली से संबद्ध भारत के दिल्ली प्रदेश को ही ले लें। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं पर दुर्भाग्य से इसके मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्री ही घोटालों के मामले में जेल में हैं। एक तरह से सरकार के मंत्री विधायक, सांसद या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। उनके एक नेता (राज्यसभा सांसद) राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने विदेश प्रवास पर हैं। जहां डॉक्टर उन्हें दिन में दो बार देखता है, जबकि एक आम भारतीय नागरिक आंखों का इलाज अपने कस्बे में ही कठिनाई से करवा पाता है और डॉक्टर उसे एक बार ही देख कर ठीक कर देता है। यह भारत के लोकतंत्र की देन है। आज से लाखों वर्ष पूर्व भारत में राजतंत्र का जमाना था। तब भी एक राघव हुआ करते थे। वो राघव वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए पैदल निकल गए थे। यह भारत के राजतंत्र की देन थी।

फेसबुक-लेखन का उदाहरण-टू

देश में एक परिवार है जिसकी शिनाख्त नेहरू-गांधी परिवार के रूप में होती है। नेहरू सरनेम ब्रह्मांड में सिर्फ भारत के इकलौते परिवार में पाया जाता है क्योंकि ये परिवार अपने कर्मों की वजह से नहर के किनारे बसा था, इसलिए नेहरू सननेम हो गया। गांधी नाम उधार का है, जो देश के एक महात्मा से लिया गया है। खैर मुझे कभी-कभी लगता है गांधी परिवार की कांग्रेस में श्रीमान राहुल गांधी की हालत टाटा नैनो जैसी है, यानी रतन टाटा जिस तरह टाटा नैनो को बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह कांग्रेस राहुल गांधी को प्यार करती है। मार्केट में टाटा नैनो नहीं चलती और राजनीति में राहुल गांधी नहीं चलते। फिर भी रतन टाटा उसे बार-बार री-लॉन्च करते रहते हैं उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी को लेकर हिम्मत नहीं हारती। 21वीं बार उन्हें एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। चुनावों में हार दर हार राहुल गांधी को री-लॉचिंग होती ही रहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच जो रिश्ता है वो शादी में सात फेरे लेते वक्त सात वचन देने जैसा है...पंडित जी पति से वचन दिलाते हैं कि तुम जो कमाओगे उसमें आधा हिस्सा पत्नी का होगा। तुम जो पुण्य करोगे उसमें से आधे बीवी के होंगे। पत्नी जो पाप करेगी उसका आधा हिस्सा पति के खाते में होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल जीते, तेलंगाना और कर्नाटक जीतें तो राहुल गांधी की वजह से जीत गए, दिल्ली और यूपी से कांग्रेस लुप्त हो जाएं तो कार्यकर्ता जिम्मेदार। लेकिन मेरी चिंता राहुल गांधी के लिए नहीं, कांग्रेसी प्रवक्तागणों के लिए है। मैं महसूस करता हूं

एक राघव दिल्ली के हैं और दूसरे लाखों वर्ष पुराने हैं। आज से लाखों वर्ष पूर्व भारत में राजतंत्र का जमाना था, तब भी एक राघव हुआ करते थे, वो राघव वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए पैदल निकल गए थे, यह भारत के राजतंत्र की देन थी, दिल्ली के राघव लोकतंत्र की देन हैं।

कि कांग्रेस की हार के बाद प्रवक्तागण राहुल गांधी को बचाने के लिए जितनी उर्जा खर्च करते हैं उतनी उर्जा खर्च करके तो न जाने कितने घरों का निर्माण हो गया होता? वैसे भी हर हार में भी राहुल गांधी की तारीफ लायक कुतर्क खोजने के लिए जितने शोध किए जाते हैं उतने शोध करके तो किसी भी ग्रह और उप ग्रह में जीवन की खोज हो गई होती।

मेरी अपनी राय

उपर्युक्त पैराग्राफ की सामग्री के भाव पर नहीं जाना है, उसमें यत्किंचित व्यंग्य-विनोद भर दिया गया है। यहां भाव की अभिव्यक्ति पर जाना है। यूं तो मुख्यतः पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिह्न, संबोधन कारक चिह्न, उद्धरण चिह्न आदि कुल 16 प्रकार के ही व्याकरण चिह्न बताए गए हैं, पर आज का फेसबुक राइटर पता नहीं इनसे भी अधिक व्याकरण चिह्न कहां से लाकर अपने लेख को ऐसे सजाता है, मानो लेख न होकर चौकला या पिज्जा हो, भले ही चिह्नों का प्रयोग इतना बेसुरा हो कि उनसे अर्थ की जगह अनर्थ ही अधिक हो रहा हो। शब्दों से भी अधिक चिह्नों और एक ही चिह्न की बारंबारता का प्रभाव यह होता है, कि लेखन का स्वयमेव विस्तारीकरण, जिसे लेखन का दूषण माना जाता है, हो जाता है। जबकि सारगर्भिता जिससे लेखन में संक्षिप्तता आती है, अथवा संक्षिप्तता, जिससे लेखन में सारगर्भितता आती है, को लेखन का भूषण माना जाता है। सार-संक्षेपीकरण को अंग्रेजी में सटीक कहते हैं। किसी भी भाषा में संक्षिप्तता लेख की सुंदरता और लेखक की विद्वता का पैमाना माना जाता है। इस संदर्भ में इंग्लिश विद्वान, कॉबेट ने कितना अच्छा कहा है, लिखने और बोलने में सबसे बड़े दोषों में से एक कम कहने के लिए कई शब्दों का उपयोग करना है। इस दोष से खुद को बचाने के लिए, पूछें कि आपने जो कहा है उसका सार या मात्रा क्या है। ●

उत्तरांचल दीप
पत्रिका

उत्तराखंड की तेजी से बढ़ती मैगजीन
चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने, नैनीताल रोड हल्द्वानी
देहरादून कार्यालयः-11 लिटन रोड देहरादून (उत्तराखंड)

सदस्यता फार्म

प्रबंधक
उत्तरांचल दीप
हल्द्वानी (नैनीताल)

माव्यवर,
मैं उत्तरांचल दीप पत्रिका की एक वर्ष की सदस्यता लेना चाहता हूं। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रुपये 450 नकद, बैंक ड्राफ्ट,चेक संख्या.....भेज रहा हूं। मुझे पत्रिका भिजवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मेरा पता इस प्रकार है। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट **उत्तरांचल दीप** के नाम से स्वीकार होगा।

सदस्य का नामः-

पिता अथवा पति का नामः-

डाक का पताः-

तहसीलः-

जिलाः-

मोबाइल नंबरः-

ई-मेलः-

यदि आपको लेखन में रूचि है तो आप लेख अथवा स्टोरी लिखकर उत्तरांचल दीप पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं। संपदकीय टीम द्वारा आपकी स्टोरी का चयन करने पर आपके लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। याद रखें कि स्टोरी अथवा लेख आपका मूल होना चाहिए। अच्छी स्टोरी व लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

संपादक

चिंता

तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी

मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ने का सीधा मतलब है कि मुस्लिम समाज अपने वोट की कीमत जानता है, जबकि हिंदू समाज ने कभी अपने वोट की ताकत को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए लोकसभा चुनाव के तीन चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक ताजा रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा है। यह रिपोर्ट दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के मध्य आए डेमोग्राफिक चेंज का विश्लेषण करने वाली है। पर हैरानी की बात ये है कि इस रिपोर्ट पर सिर्फ भारत में बवाल मचा है। क्योंकि भारत में हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी का स्पष्ट उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घट चुकी है यानी 8 प्रतिशत के करीब। जबकि इसी दरम्यान मुसलमानों की आबाद में 43.15 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जैन, पारसी, बौद्ध की आबादी में भी गिरावट दर्ज की गई है। जबकि मुस्लिम, ईसाई और सिखों की आबादी में वृद्धि हुई है। इसमें भी सबसे तेजी से मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि दुनिया में सिर्फ भारत में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और फल-फूल रहे हैं। जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के वंश के वंश मिट चुके हैं। पाकिस्तान में तो हिंदू बेटियों को अगवा कर बूढ़े व्यक्ति के साथ निकाह कराने की तमाम तस्वीरें आती रहती है। पाकिस्तान में न हिंदु सुरक्षित हैं और न ही हिंदुओं के देवालय सुरक्षित हैं। फिर भी कोई ये सवाल नहीं करता कि पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या हुआ? भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली देशी और विदेशी ताकतें क्या अभी भी यही राग अलापेंगी कि भारत में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) डरा हुआ है? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं? अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। खैर लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। भाजपा डेमोग्राफी में आए इस बदलाव के लिए सीधे-सीधे कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रही है। 'गजवा-ए-हिंद' की तैयारी बता रही है। भाजपा कह रही है कि यही हाल रहा तो भविष्य में हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा जहां वो सुरक्षित रह सके। इसके विपरीत विपक्षी नेता इस रिपोर्ट को भटकाने और भ्रम फैलाने वाली बता रहे हैं। कोई इस रिपोर्ट को 'व्हॉट्सएप यूनिवर्सिटी' की रिपोर्ट बताकर खारिज कर रहा है तो कोई इसे नफरत फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। किंतु याद होना चाहिए कि पिछले साल जब पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापे मारी हुई थी तब भारत को 2047 तक 'गजवा-ए-हिंद' बनाए जाने की तैयारी के दस्तावेज मिले थे। मुस्मिल आबादी बढ़ाने के पीछे कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है और वो है 'गजवा-ए-हिंद'। 'गजवा-ए-हिंद' की पैरोकारी करने वाले भी किसी से छिपे नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा था। लेकिन पिछले दस वर्षों में हिंदू जागा है और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहा है।

क्या है रिपोर्ट है?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की हालिया रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच डेमोग्राफी में आए बदलाव का विश्लेषण किया गया है। डेमोग्राफी में यह बदलाव पिछले दस सालों में नहीं आया है, बल्कि आजादी के बाद कांग्रेस ने इसे एक साजिश के तहत इसे परवान चढ़ाया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जिससे साबित होता है कि देश में अनेकता में एकता के लिए कितना अनुकूल वातावरण है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के एक राष्ट्रव्यापी विश्लेषण (1950-2015) शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी में जैन समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी 1950 में 0.45 प्रतिशत थी जो 2015 में घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई। एसी-पीएम की सदस्य शमिका रवि के नेतृत्व वाली टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82 प्रतिशत की कमी के साथ हिंदू 84.68 प्रतिशत से घटकर 78.06 प्रतिशत रह गए हैं। जबकि 1950 में देश में मुसलमानों की आबादी 9.84 प्रतिशत थी जो 2015 तक बढ़कर 14.09 प्रतिशत पहुंच गई है। यानी 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि 1950 और 2015 के बीच ईसाइयों की आबादी 2.24 प्रतिशत से बढ़कर 2.36 प्रतिशत पहुंच गई। 1950 में सिखों की आबादी 1.24 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2015 तक 1.85 प्रतिशत हो गई यानी 6.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में पारसी आबादी में 85 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है। इस समुदाय की आबादी

विरोधी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया था, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोट बैंक के लिए भारत में बसाया, अब घुसपैठियों को आरक्षण देना चाहती है।

1950 में कुल जनसंख्या का 0.03 प्रतिशत थी, लेकिन 2015 में यह सिर्फ 0.004 प्रतिशत रह गई है। ईएसी-पीएम की रिपोर्ट बताती है कि इन 65 वर्षों में गैर-मुस्लिम देशों में बहुसंख्यकों की जनसंख्या घटी है। लेकिन ये आंकड़ा मुस्लिम-बहुल देशों पर लागू नहीं होता। मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक संप्रदाय की आबादी निरंतर बढ़ी है। केवल मालदीव एक अपवाद है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों के व्यापक संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पासरी आबादी में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि पड़ोसी मुस्लिम देशों से अल्पसंख्यक आबादी दबाव या उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने आती है।

राष्ट्रव्यापी विश्लेषण

ईएसी-पीएम की रिपोर्ट बताती है कि सभी मुस्लिम बहुल देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी में वृद्धि हुई है। सिर्फ मालदीव ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जहां बहुसंख्यक शाफी-सुन्नियों की आबादी में 1.47 प्रतिशत की कमी आई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय (मुस्लिम) की हिस्सेदारी में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक वृद्धि है। 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक हनफी मुस्लिम की भागीदारी में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि और टोटल मुस्लिम आबादी की भागीदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय (हिंदुओं) की हिस्सेदारी में कमी आई है। ये अध्ययन रिपोर्ट दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति का राष्ट्रव्यापी विश्लेषण है जिसमें 1950 और 2015 के बीच 65 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती डेमोग्राफी को मापा गया है। विश्लेषण में शामिल 167 देशों के लिए, 1950 के आधारभूत वर्ष में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी का औसत आंकड़ा 75 प्रतिशत है, जबकि 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी में परिवर्तन का औसत 21.9 फीसदी है।

क्यों गिरा मत प्रतिशत?

लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को लेकर हर कोई चिंतित है, लेकिन जहां मुस्मिल बहुल सीट हैं वहां मत प्रतिशत बढ़ा ही है। उदहारण के तौर पर पश्चिमी बंगाल के धुबरी में 91.1 प्रतिशत मतदान हुआ यहां 79.07 फीसदी मुस्लिम आबादी है और 19.09 प्रतिशत

भारत में हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध की आबादी में कमी आई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और सिखों की आबादी बढ़ी है, इसमें भी सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सिर्फ भारत में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं।

हिंदू आबादी है। मुर्शिदाबाद में 81.5 प्रतिशत मतदान हुआ यहां मुस्लिम आबादी 68.5 प्रतिशत है जबकि हिंदू आबादी 30 फीसदी है। पश्चिम बंगाल की ही मालदा दक्षिण लोकसभा सीट पर 76.7 प्रतिशत मतदान हुआ यहां मुस्लिम आबादी 58.8 फीसदी है जबकि हिंदू आबादी 40.2 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल की ही जंगीपुर लोकसभा सीट पर 75.7 प्रतिशत मतदान हुआ जहां 63.2 प्रतिशत मुस्लिम और 36 फीसदी हिंदू आबादी है। असम की बात करें तो यहां भी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बेहतर रहा है। असम की लक्षदीप लोकसभा सीट पर 84.1 प्रतिशत मतदान हुआ यहां मुस्लिम 96.6 फीसदी और हिंदू 2.8 प्रतिशत हैं। बरपेटा में मुस्लिम आबादी 70 प्रतिशत है और हिंदू आबादी 29 फीसदी है यहां मतदान का प्रतिशत 85.2 रहा है। इसके विपरीत गुजरात के अमरेली लोकसभा सीट पर 49.5 फीसदी मतदान हुआ यहां हिंदू आबादी 93.1 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 6.5 फीसदी है। यूपी के संभल में 62.9 फीसदी मतदान हुआ यहां मुस्लिम 50.2 प्रतिशत और हिंदू 49 फीसदी हैं। इसी तरह आगरा में 54.1 प्रतिशत मतदान हुआ यहां हिंदू आबादी 88.8 प्रतिशत और मुस्लिम 9.2 फीसदी हैं। बिहार के अररिया लोकसभा सीट पर 61.9 फीसदी मतदान हुआ यहां हिंदू 58.5 प्रतिशत है जबकि मुस्लिम 41.1 फीसदी हैं। इसी तरह बिहार के झंझारपुर में 54.5 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि यहां हिंदू आबादी 84.7 प्रतिशत है और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 15.2 है। मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम समाज अपने वोट की कीमत जानता है, जबकि हिंदू समाज ने कभी अपने वोट की ताकत को समझने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के तीन चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। इसलिए भी ईएसी-पीएम की रिपोर्ट पर घमासान सा मचा है।

सियासत का पारा हाई

भाजपा ने देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार पर चिंता जताते हुए हैरानी जताई कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर तुली कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तो इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को टारगेट करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये सभी मिलकर भारत में गजवा-ए-हिंद की पैरवी करने में लगे हैं। विरोधी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया था। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को वोट बैंक के लिए भारत में बसाया गया। अब इससे आगे बढ़ कर घुसपैठियों को आरक्षण देना चाहते हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने तो तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर दी है। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8 प्रतिशत सिकुड़ गई। मुस्लिम आबादी 43 फीसदी फैल गई। कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया है। अगर विरोधियों पर छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए पनाह लेने के लिए कोई देश ही नहीं बचेगा। देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्या-क्या नहीं किया यह किसी से अब छिपा नहीं है। अल्पसंख्य आयोग है पर बहुसंख्यक आयोग नहीं है। मुस्लिम पर्सनला बोर्ड है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं। मुस्लमानों के लिए वक्फ बोर्ड है किंतु हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं है। भाजपा की इस क्रिया की प्रतिक्रिया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आई। प्रियंका ने कहा कि ईएसी-पीएम की रिपोर्ट असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश भर है। बात तो उन मुद्दों पर होनी चाहिए जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। किसान और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। किंतु भाजपा चाहती ही है कि मुद्दों पर बात ही न हो। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जब मीडिया ने इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे व्हॉट्सऐप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताकर खारिज कर दिया। ओवैसी ने कहा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए तब मैं बोलूंगा। किसकी रिपोर्ट है ये? किसने ये रिपोर्ट बनाई है? बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट को लोगों में भ्रम और नफरत फैलाने की कोशिश करार दे दिया। उनका आरोप है कि भाजपा का यही एजेंडा है। 10 साल तक लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं।

एलन मस्क और शेयरों की चाल

शेयर बाजार कहीं सत्ता परिवर्तन की हवा तो नहीं सूंघ रहा है? इतना तो तय है कि प्रचंड बहुमत यानी 400 पार के आंकड़े की सच्चाई से वह वाकिफ है, लेकिन, गिरकर संभलना एक दूसरा संकेत भी दे रहा है, फिर भी एलन मस्क का चुनावी दौर में न आना और फिर इसी साल आने का भरोसा दिलाना क्या समझा जाए?

आलोक भदौरिया
वरिष्ठ पत्रकार

मई का महीना शेयर बाजार के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति और कॉरपोरेट के नतीजे बाजार पर असर डालते ही हैं। इस बार चुनाव के कारण बाजार सहमा हुआ है। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के बॉस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने आखिरी वक्त में भारत दौरे को टाल दिया। क्या मस्क भी सावधानी का रास्ता पकड़ चुके हैं? उनके न आने का भी क्या मतलब निकाला जाए? आखिर वह नई सरकार के दौर में ही क्यों आना चाहते हैं? बैटरी से चलने वाली 'टेस्ला' के स्वामी एलन मस्क आमतौर पर आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि कारोबारी फैसले वह काफी तेजी से लेते हैं। इस मामले में उनका कोई सानी नहीं है। टेस्ला कार दुनिया में झंडे गाड़ चुकी है। अनेक देश टेस्ला को अपने देशों में आने का न्यौता देते रहते हैं। भारत भी इस मामले में अपवाद नहीं है। पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस दौरान ही मस्क को आने का न्यौता दिया गया। उन्होंने 2024 में आने का भरोसा दिया था। तब से उनकी मांग थी कि कई टैक्स और ड्यूटी से टेस्ला को मुक्ति दी जाए। वार्ता का यह दौर काफी समय से चल रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने उन्हें कई सहूलियतें दीं। एफडीआई में छूट दी गई। ड्यूटी में भी कटौती की गई। मसलन, 35 हजार डॉलर वाली या इससे महंगी टेस्ला कार की ड्यूटी 15 फीसद कर दी गई। पहले यह सौ फीसद होती थी। यह छूट पांच सालों के लिए दी गई। इसके अलावा भारत ने छोटी कार देश में ही बनाने की बात कही। एफडीआई नियमों में बदलाव भी किए गए। 50 करोड़ डॉलर निवेश करने पर सहूलियतें दी गईं। पर, यह छूट सिर्फ नए निवेश पर ही मिल सकेगी। टैक्स में छूट और कटौती की मांग कर रही कंपनी को अंततः सब मिल गया था। अर्से से इच्छुक टेस्ला कंपनी फिर भी क्यों नहीं आई? वैसे भारत का बाजार काफी बड़ा है। हाल के वर्षों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों का रुझान बदला है। अब सस्ती कारों के मुकाबले महंगी कारों के खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट कारों का दौर चल निकला है। एसयूवी की बिक्री भी बढ़ी है। यानी मस्क के लिए बाजार में संभावनाओं की कोई कमी नहीं थी।

एलन मस्क केवल टेस्ला कार ही नहीं बनाते हैं, उनका कारोबार अंतरिक्ष तक में फैला हुआ है, उनकी कंपनी का मिशन मंगल गृह पर इंसानी बस्ती बसाने का भी है, इस सेक्टर में काम कर रही 'स्पेसएक्स' अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगा रही है।

भारत क्यों नहीं आए एलन मस्क

ऐसा नहीं है कि एलन मस्क केवल टेस्ला कार ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उनका कारोबार अंतरिक्ष तक में भी फैला हुआ है। उनकी कंपनी का मिशन मंगल गृह पर इंसानी बस्ती बसाने का भी है। इस सेक्टर में काम कर रही 'स्पेसएक्स' अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगा रही है। स्टार लिंक के जरिये वह घर बैठे संचार की दुनिया बदल रहे हैं। दूसरे शब्दों में अब आपको टीवी देखने या मोबाइल चलाने के लिए केबल बिछाने या टॉवर लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब छोटे से एंटीने के जरिये बेहतर कनेक्टीविटी मिला करेगी। संचार मंत्रालय के पास पिछले तीन साल से यह प्रस्ताव पड़ा था। आनन-फानन में मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। सैद्धांतिक मंजूरी का अर्थ है कि गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी खतरे का अध्ययन कर अपनी मंजूरी दे सकता है। भारत पहले से इस बात का कायल रहा है कि सर्वर देश में ही लगाया जाए। यह बात समझ से परे है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने की तैयारियां करने वाले मस्क को अब और क्या चाहिए था? इस सेक्टर में तो सौ फीसद एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से मंजूर की जा चुकी है। इसकी घोषणा तो बजट में ही कर दी गई थी। इन सबके बावजूद एलन मस्क ने 21-22 अप्रैल का दौरा रद्द कर दिया। चिंता की बात यह है कि एलन मस्क चीन चले गए। वैसे भी उन्हें चीन की ईवी कारों से काफी चुनौतियां मिल रही थीं। वहां चीन की कंपनियों ने अपनी कारों के दाम कोई दो हजार डॉलर तक घटा दिए थे। भारत दौरे को लेकर और दो अरब डॉलर के निवेश की खबरें चलने पर चीन की कंपनियों ने फौरन कदम उठा लिए। अब मस्क कह रहे हैं कि इसी साल के उत्तरार्ध में भारत आएंगे। यानी नई सरकार के बनने के बाद। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वह भी सतर्कता बरतने के मूड में है? क्या इस फैसले में कोई संदेश छिपा हुआ है?

- **टेस्ला कार दुनिया में झंडे गाड़ चुकी है, अनेक देश टेस्ला को अपने देश में आने का न्यौता देते हैं, भारत भी इस मामले में अपवाद नहीं है, पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब ही मस्क को भारत आने का न्यौता दिया था और मस्क ने 2024 में आने का भरोसा भी दिया था।**
- **मई में अमेरिकी फेडरल बैंक ब्याज दरों के बारे में फैसला लेता है, जिसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर पड़ता है, इस बार उसने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में काफी समय से बदलाव नहीं किया है, फिर शेयर बाजार में इतनी उठापटक क्यों मची हुई है?**

शेयर बाजार

अब हम लोग बात करते हैं शेयर बाजार की चाल पर। मई का महीना हमेशा से ही उथल-पुथल का रहता है। मई में ही अमेरिकी फेडरल बैंक ब्याज दरों के बारे में फैसला लेता है। फेड दरों में बदलाव का दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर पड़ता है। हालांकि इस बार भी उसने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में काफी समय से कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में इतनी उठापटक क्यों मची हुई है? यदि एफआईआई की बात करें तो इस मई में खबर लिखे जाने तक 24975 करोड़ रुपये उन्होंने निकाल लिया। फ्यूचर और ऑप्शन से भी 11279 करोड़ रुपये निकाल लिए। फ्यूचर और ऑप्शन ऐसे सौदे होते हैं जो पहले से ही बाजार के बारे में अनुमान लगाकर तय कर लिए जाते हैं कि आगे अमुक तारीख को अमुक भाव पर खरीदारी करेंगे या बेचेंगे। बाजार की चाल ऊपर-नीचे होने पर लाभ और हानि होती है। तो क्या एफआईआई के पैसे निकालने पर ही बाजार की ऐसी नौबत आई? दरअसल, भारत का वोलैटिलिटी इंडेक्स (वीआईएक्स) बहुत ऊंचाई पर है। 13 मई को यह 21.41 पर जा पहुंचा था। जो साल का उच्चतम स्कोर है। शेयर बाजार में यह उथल-पुथल की संभावना जताती है, यह दर्शाती है कि भारत का शेयर बाजार कृत्रिम तेजी पर है। यानी जरूरत से ज्यादा शेयरों के दाम पहुंच गए हैं। अब और आगे बढ़ने की गुंजाइश कम है। इसके विपरीत सनराइज इंडस्ट्रीज के लिए भी निवेशक ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि भविष्य में यह ज्यादा मुनाफा देने में सक्षम होगी। नया क्षेत्र होने के कारण जल्द फायदा की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। वीआईएक्स जितना ज्यादा होगा बाजार में अनिश्चितता की स्थिति उतनी ही ज्यादा होगी। यानी निवेशकों को इस मौके पर सावधान रहने की जरूरत है। बाजार के गिरने पर तेजी से बिकवाली से बचना चाहिए। इसके साथ ही बाजार में उछाल आने पर सब कुछ गुलाबी तस्वीर नहीं मान लेनी चाहिए। तब तेजी से अपना सारा पैसा बाजार में झोंक देने पर उतारू भी नहीं हो जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि निवेशकों को समझ बूझ कर ही धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए।

बाजार में शेयरों के दाम चढ़े होने का अंदाजा प्रति शेयर कीमत और उससे लाभ से भी लगती है। यानी पीई वैल्यू जितनी कम होगी उस कंपनी का शेयर वास्तविक मूल्य पर डटा होगा। दूसरे शब्दों में उसमें जोखिम की संभावना भी उतनी ही कम रहती है। इस हिसाब से देखें तो शेयर बाजार का पीई 25 पर जा पहुंचा है। यह भी साबित करता है कि शेयरों का बाजार मूल्य ज्यादा बढ़ा हुआ है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर एक पहलू पर और ध्यान देने की जरूरत है। विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने की वजह में सबसे प्रमुख ब्याज दरों में कटौती न होना भी रहता है। अर्से से ब्याज दरों में बदलाव न होने पर उद्योग जगत के लिए यह फायदेमंद स्थिति नहीं होती है। पूंजी महंगी दरों पर मिलना यानी मुनाफे में उतनी बढोतरी न होना भी है। लिहाजा एफआईआई डॉलर सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाते हैं। एशियाई टाइगर्स माने जाने वाले पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था ढहने का यही कारण था। पिछले दशक में पूंजी वहां से निकलकर अमेरिका की तरफ चली गई थी। विदेशी निवेशकों की एक बड़ी चिंता कॉरपोरेट को उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न होना भी है। पहले बताए गए दोनों संकेतकों के भी उनमें निराशा का भाव पैदा करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सबके बावजूद बड़ी चिंता देश में चुनाव को लेकर भी है। दूसरे चरण के बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। एक दिन में हजार प्वाइंट से ज्यादा गिरावट से साढ़े सात लाख करोड़ तक का नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा। ऐसा इसी माह अब तक दो दफा हो चुका है। हजार प्वाइंट का गिरना असामान्य है।

बाजार के जानकार कहते हैं कि वीआईएक्स का 21 पार करना बाजार को मंदी की ओर ले जा सकता है। यह भले ही थोड़े समय के लिए हो। लेकिन, पिछले कुछ सालों से आम लोगों का बाजार की ओर रुझान बढ़ना अपनी पूंजी को बढ़ाने भी जुड़ा हुआ है। बैंकों में ब्याज दरों के कम होने के चलते मध्य वर्ग ने म्यूचुअल फंड्रों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। घरेलु निवेशकों की एक बड़ी तादाद ने इस ओर रुख किया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2023-24 में कोई 1.99 लाख करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिये लगाए गए हैं। कोई 15 करोड़ डीमैट एकांउट हैं। बाजार के गिरने की स्थिति में लाखों छोटे निवेशकों का हाथ जल जाना तय है। काबिलेगौर है कि हर्षद मेहता कांड के बाद बाजार को संभलने में लंबा वक्त लगा था। ऐसा ही केतन पारिख मामले के बाद भी हो चुका है। छोटे निवेशक बाजार से मुंह मोड़ लेते हैं। हालांकि बाजार बाद के दिनों में संभला है। लेकिन, कुछ जानकार यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि शेयर बाजार कहीं सत्ता परिवर्तन की हवा तो नहीं सूंघ रहा है? इतना तो तय है कि प्रचंड बहुमत यानी 400 पार के आंकड़े की सच्चाई से वह वाकिफ हो चला है। लेकिन, गिरकर संभलना एक दूसरा संकेत भी दे रहा है। फिर भी एलन मस्क का चुनावी दौर में न आना और फिर इसी साल आने का भरोसा दिलाना क्या समझा जाए? क्या यह कॉरपोरेट का अपनी बात कहने का अंदाज है?

व्यंग्य

जीजा V/S साला

राजनीति में न आऊं तो क्या करूं, तुम्हारी मूर्खता और अल्पबुद्धि ने पूरे परिवार, देश और दल की नाक में दम कर रखा है। तुम तो घर छोड़ कर उत्तर से दक्षिण निकल लेते हो, ताने हमे सुनने पड़ते हैं, इसलिए हमने भी अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। 'उत्तर भारत करे पुकार जीजा जी अबकी बार।'

हास्य व्यंग्य का नाम आते ही जीजा-साली, देवर-भाभी के बीच का हास्य-व्यंग्य सबसे पहले दिमाग में घुसता है। बात जीजा-साले की हो तो हास्य-व्यंग्य कई बार तीखी नोंक झोंक और तकरार में तबदील हो जाता है। ऐसे ही हमारे देश के एक नेशनल जीजा-साले जब मिलते हैं तो हास्य तो नहीं होता लेकिन कहीं न कहीं से व्यंग्य जरूर निकल आता है। चुनाव का दौर चल रहा है एक चर्चित जीजा जी पूरा दमखम लगा रहे हैं कि कैसे भी हो राजनीति में इंट्री हो, वो पोस्टर भी लगवा चुके हैं, लेकिन साले साब हैं कि जीजा जी की भावनाओं को भाव ही नहीं दे रहे। साले साब ने जीजा जी की सारी हसरतों पर पानी फेर दिया। न तो खुद खानदानी सीट संभाल पाए और न ही जीजा जी को संभालने दी, बल्कि 40 साल पुराने वफादार को दे दी। अब जीजा जी झुनझुना लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं यूपी कर रही पुकार, जीजा जी यूपी से बाहर। लेकिन जीजा जी तो चाहते थे कि अमेठी में खानदान की इज्जत बची रहे। इज्जत बचाने के लिए साले साब चाहते तो फोन पर भी बात कर सकते थे, किंतु मुद्दा संवेदनशील ही नहीं बल्कि अति संवेदनशील था, इसलिए वो सुबह-सुबह जीजा जी के घर जा धमके और नौकर को हुकुम दिया कि जीजा जी को बुलाओ। नौकर हुक्म की तामील करने चला गया। साले साब ड्राइंग रूम में पड़े अति सुविधाजनक इंपोर्टेड सोफे पर पसर गए। थोड़ी देर बाद जीजा जी बाहर आए। बीती रात एक बड़ी डील फाइनल होने के बाद सभी प्रकार के इंपोर्टेड मादक द्रव्यों की मैराथन पार्टी हुई थी, लिहाजा जीजा जी अभी भी तरंगित अवस्था में थे। यानी हैंगओवर सिर पर सवार था। इसलिए सुबह-सुबह और बेवक्त जगाने के कारण चिढ़े हुए भी थे। बगल में बैठ कर साले की तरफ सवालिया नजरों से निहारा और बोले? क्या मुसीबत है, क्यों सुबह-सुबह आ धमके...?

साले साब अकड़ और कड़क अंदाज में आंखे लाल-पीली करते हुए बोले...आप राजनीति में आने की क्यों सोच रहे हैं? मेरे रहते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैं आपके हितों का आपकी डील का ख्याल नहीं रखता? क्या आपको ईडी और सीबीआई जेल भेज पाई? नहीं न, यह सब मेरे ही तेज और प्रताप का असर है, क्योंकि देश का चौकीदार सिर्फ मुझसे डरता है...। इसलिए तुमने जिस सीट पर रुमाल रखा है न उसे जाकर तुरंत उठा लो...। जीजा जी बेचारे सिर पर पैर रखकर दौड़े और अपना रुमाल उठाकर गायब हो गए। पर जाते जाते जीजा जी की तरफ से साले के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पेश हुआ। इधर गाल लाल हुआ, सिर चकराया, और साले साब की सारी हेकड़ी पल भर में तिरोहित हो गई...आग बबूला हो रहे साले साब उछल कर दूर जा खड़े हुए। अब बारी जीजा जी की थी...।

जीजा जी- राजनीति में न आऊं तो क्या करूं, तुम्हारी मूर्खता, अल्पबुद्धि और अहंकार ने पूरे परिवार, देश और दल सबकी नाक में दम कर रखा है। तुम तो घर छोड़ कर उत्तर से दक्षिण निकल लेते हो, ताने हमे सुनने पड़ते हैं, इसलिए हमने भी उत्तर में अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। 'यूपी करे पुकार जीजा जी अबकी बार।' तुम तो 52 के हो गए, ऊपर से नीचे तक...सफेद हो गए, फिर भी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। जब देखो जहां देखो रायता फैला आते हो और समेटना दरबारियों को पड़ता है।

ये चुनाव है इसमें ठका ठक...पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, हमने पहाड़ी स्टेट में एक लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी, रोजगार दिए क्या? हमने महंगाई कम करने की गारंटी दी थी, करी क्या? हमने राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी दी थी, करे क्या?

कहते हो डरे नहीं लड़ो है, लेकिन तुम खुद डर कर भागे-भागे फिर रहे हो, कंफ्यूज करते हो मेरा घर यहां भी है वहां भी है, इधर भी है उधर भी है, पर घर तो घरवाली से होता है। इसलिए अब हमने फैसला कर लिया है कि राजनीति में आगे आकर हम देश और दल को संभालेंगे। वैसे भी दस साल हो गए पर तुम्हारी बुद्धि और विवेक में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। अब और सहन करने की हिम्मत नहीं रही।

साले साब दूर से ही जीजा से नजर चुराकर-ओए इस बार तो अच्छा चल रहा है। मैंने सामने वाले की हालत खराब कर रखी है। इस बार तो मेरा बनना पक्का है। बस एक बार बन जाने दे, तेरी क्या सब की...?

साले की बकवास सुनते ही जीजा जी का पारा हाई फाई हो गया...जीजा दांत पीसते हुए तुमने तो पहले से ही मेरी हालत खराब कर रखी है...कल मुझे जबाब देते नहीं बन रहा था।

साले साब अब और थोड़ा पीछे खिसक कर...क्यों क्या हुआ...क्या आफत आ गई जो लाल पीले हो रहे हो?

जीजा- कल देश भर के खबरची आए थे, साथ मेरे लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति का लेखा-जोखा लाए थे, पूछ रहे थे कि 'गुजारे लायक छोड़कर बाकी की संपत्ति मैं कब बांटने वाला हूं। आपके साले साब की स्कीम है तो घर से ही उद्घाटन हो जाना चाहिए...।'

साले साब-जीजा जी को समझाने की मुद्रा बनाते हैं शून्य में देखते हैं और फिर कहते हैं अरे जीजा जी वो तो मैं जनता को वोट लेने के लिए बेवकूफ बना रहा हूं। क्या जीजा तुम भी मेरे झूठ और मक्कारी के जाल में फंस गए? ये तो ठका ठक...ठका ठक...पब्लिक को उल्लू बनाने का फार्मूला है। अब तुम ही बताओ ऐसा करना क्या मुमकिन है...?

हमने एक पहाड़ी स्टेट में एक लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी, रोजगार दिए क्या? हमने महंगाई कम करने की गारंटी दी थी, करी क्या? हमने तो डीजल पेट्रोल के रेट और बढ़ा दिए। राजस्थान में कर्ज माफ करने की गारंटी दी थी, करे क्या? फिर जीजा ये तो चुनाव है इसमें मैं गरीब महिलाओं को एक लाख रुपये देने की गारंटी दे रहा हूं, किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी फिर दे रहा हूं, शरिया कानून बहाल करने की गारंटी भी दे रहा हूं, रोजगार देने की गारंटी दे रहा हूं, महंगाई कम करने की गारंटी दे रहा हूं, एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दे रहा हूं, जो मुंह पर आता है उसकी गारंटी दे देता हूं, यूसीसी, सीएए को वापस लेने की ठका ठक...ठका ठक गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूं, भले ही देश बेचने की गारंटी ही क्यों न देनी पड़े...। जीजा जी की पीठ थपथपाते हुए... साले साब दिल और दिमाग की बात निकालते हैं...मैं कुछ बन जाऊंगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जीजा जी को न...। पब्लिक को भला हमने या हमारे खानदान ने 55 साल में कुछ दिया है क्या...? अगर दिया है तो वो है फरेब, झूठ, मक्कारी, गरीबी, लाचारी, तभी तो शान से जीते हैं हम और तुम...।

साले साब सफाई दे ही रहे थे कि तब तक नौकर एक ट्रे में इंपोर्टेड व्हिस्की और दो खूबसूरत विदेशी गिलास और अन्य सामग्री के साथ चखना लेकर आ गया।

जीजा जी फिर थोड़े और तमतमाए और कहने लगे...अरे जो करना नहीं रहता है वह बकते क्यों हो? जहां देखों जब देखों बकवास तुम करते हो और सफाई हम देते फिरते है...।

बात खत्म होते ही जीजा ने लपक कर ट्रे से एक गिलास उठाया और पूरी ताकत से साले के सिर को निशाना बनाकर फेंका। वो तो साले साब समय पर झुक गए वरना तो निश्चित रूप से बचा खुचा दिमाग भी डैमेज हो गया होता...।

जीजा ने निशाना चूकता देख पुनः गिलास उठाया किंतु तब तक साला अलादीन के चिराग के जिन की तरह गायब हो चुका था। लेकिन बड़बड़ा रहा था देख लेना एक दिन पूरे दल की विनाश कर दूंगा। राम नवमी वालों की सारी संपत्ति छीन कर डकार भी नहीं लूंगा। अंकल ने अमेरिका के विरासत टैक्स के सारे टिप्स मुझे समझा दिए हैं। देखते रहना...।

मेरा पप्पू, शहजादा बन गया

हमारे देश का 52 साल का पप्पू इस बार शाही परिवार का शहजादा बन गया है...। शहजादे हैं तो उड़ाने भी भरते हैं। एक बार उड़ान भरने के लिए शहजादे ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक की...। बंगले पर ड्राइवर टैक्सी लेकर पहुंच गया, शहजादे नजाकत के साथ टैक्सी में सवार हुए और एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए निकल गए। रास्ते भर ड्राइवर को ज्ञान देते रहे और विचारों का आदान प्रदान करते रहे... पर चेस्ट स्टैबिंग फ्रॉम बैक, आलू से सोना ठका-ठक जैसे विषयों के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकर शहजादे मेरा मतलब पप्पू हैरान रह गए...। ड्राइवर को क्या गजब का ज्ञान है उसे ये भी पता है कि ठाका ठक.... खाते में पैसा जाएगा, आलू से सोना बनेगा...खैर ज्ञान के आदान-प्रदान में न जाने कब एयरपोर्ट आ गया और ड्राइवर ने ख्वाबों की दुनिया में उड़ रहे शहजादे को बताया सर एयरपोर्ट आ गया है। कहां उतारना है?

हड़बड़ाहट से नार्मल होने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हुए शहजादे जब एयरपोर्ट के गेट पर उतरे तो ड्राइवर से उसका विजिटिंग कार्ड मांग लिया, ताकि भविष्य में ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए उसकी कैब फिर बुक कराई जा सकें...। ड्राइवर ने अपना कार्ड दिया तो शहजादा कार्ड पढ़कर सरप्राइज हो गया...। विजिटिंग कार्ड पर अंग्रेजी में छपा हुआ था। शहजादे को शायद यह अंदाज नहीं था कि ड्राइवर भी इतना हाई क्वालिफाई होगा? अब तो शहजादे की आंखे फटी की फटी रह गई...हैरानी और परेशानी के बीच शहजादे ने पूछ ही लिया...। 'आप इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होकर टैक्सी क्यों चलाते हो...? आप को तो देश चलाना चाहिए...!'

ड्राइवर साहब ने बड़े ही शालीनता से कहा 'जो डीआर. यानी डा. लिखा हुआ है उसका फुल फार्म है ड्राइवर'

शहजादे ने आश्चर्य से पूछा 'फिर आपकी पीएचडी वाली डिग्री का क्या है...?'

ड्राइवर साहब ने माचिस की तीली से कान खोदते हुए इत्मीनान से जवाब दिया...। पीएचडी का फुल फार्म है...'प्राइवेट हायर्ड ड्राइवर'...व्हाय ओनली फेसबुकियाज हैविंग ऑल द फन...वहां भी सब इलेक्ट्रिशियन लोग भी इं. वगैरह लगाते हैं न। ऐसे ही फेसबुकियाज भले ही कपड़ों पर प्रेस करते हों, लेकिन अबाउट में प्रोफेशन के खाने में प्रेस लिख देते हैं। अब शहजादा परेशान है क्योंकि उससे भी काबिल लोग इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। खैर मम्मी, दीदी और जीजा जी इसलिए खुश हैं क्योंकि अब उनके पप्पू का प्रमोशन हो गया है, अब वो शहजादा बन गया है। शहजादा नाम अच्छी फीलिंग दे रहा है। पप्पू सुन कर ऐसा लगता था कि कोई 52 साल के युवराज को पागल कह रहा है।

हुल्लड़ उत्तराखंडी

- **जीजा जी मैं राजनीति में न आऊं तो क्या करूं, तुम्हारी मूर्खता ने पूरे देश और दल की नाक में दम कर रखा है। तुम तो घर छोड़ कर उत्तर से दक्षिण निकल गए, ताने हमे सुनने पड़ते हैं, इसलिए हमने अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। 'उत्तर भारत करे पुकार जीजा जी अबकी बार।'**
- **साले साब कड़क अंदाज में आंखे लाल करते हुए जीजा से...आप राजनीति में आने की क्यों सोच रहे हैं? मेरे रहते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे हितों का आपकी डील का ख्याल नहीं रखता? क्या आपको ईडी और सीबीआई जेल भेज पाई? नहीं न।**

फर्स्ट इंप्रैशन इज द लास्ट इंप्रैशन

जिस प्रकार रोजाना अच्छा भोजन करने और सेहत के नियमों का पालन करने से हम सदा स्वस्थ रहते हैं उसी प्रकार हर बार शिष्टाचार का पालन करना हमारे संबंधों को सुदृढ़ करता है। जब हम किसी से पहली बार मिलने पर अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं, तो हमेशा क्यों नहीं?

जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बहुत सतर्कता से काम लेते हैं और मिलने वाले पर अपना अच्छे से अच्छा प्रभाव छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कहते हैं कि प्रथम प्रभाव या पहली छवि चिरस्थाई होती है। 'फर्स्ट इंप्रैशन इज द लास्ट इम्प्रैशन'। इसलिए किसी से भी पहली बार मिलते समय सलीके से साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं। प्रयास करते हैं कि मुख अथवा वस्त्रों में से किसी भी प्रकार की अप्रिय गंध न आए। अवसर के अनुकूल उपहार आदि भी ले जाते हैं। शिष्टाचार ही नहीं तमाम औपचारिकताओं का भी पूरी तरह से निर्वाह करते हैं। पहली बार मिलने वाले से ही नहीं उस समय वहां उपस्थित अन्य सभी से भी अत्यंत विनम्रता से पेश आते हैं। क्रोध जैसी चीज आसपास नहीं फटकने पाती। ऊंची आवाज में बात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सहयोग की भावना का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकते, आदर्शों की बात करते हैं। यथा संभव नैतिकता का दामन थामे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं को एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक आदर्श और सुसभ्य व्यक्ति के रूप में, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि यदि हमारा व्यवहार बदलता है तो मात्र फर्स्ट इंप्रैशन अथवा प्रथम प्रभाव के आधार पर हम कितने दिन तक लोगों को प्रभावित कर पाएंगे? जैसे ही हमारा व्यवहार बदलेगा न केवल लोगों का व्यवहार और प्रतिक्रिया बदल जाएंगी अपितु उसका नकारात्मक प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। यदि हम अपनी उन सभी आदतों अथवा व्यवहार को, जो किसी से पहली बार मिलने पर हम व्यवहार में लाते हैं, स्थाई रूप से अपने आचरण में सम्मिलित कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत उत्कृष्ट हो सकता है। इस प्रकार की अच्छी आदतों और व्यवहार से संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपके व्यवहार की तुलना भी करते हैं।

सीताराम गुप्ता,
पीतमपुरा, दिल्ली

नई चेतना का उदय

कई लोग मानते हैं कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव डालना संभव है, लेकिन रोज-रोज शिष्टाचार का पालन करना संभव नहीं है। अत्यधिक शिष्टाचार से जीवन में सहजता नहीं रहती। व्यवहार में एक कृत्रिमता-सी आ जाती है। ये बात किसी भी तरह से ठीक नहीं है। रोज-रोज संतुलित व पौष्टिक भोजन करने से क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? जिस प्रकार से प्रतिदिन अच्छा भोजन करने और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से हम सदैव स्वस्थ बने रहते हैं उसी प्रकार से हर बार शिष्टाचार का पालन करना हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने में ही सहायक होता है। जब हम किसी से पहली बार मिलने पर अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं तो बाद में अथवा हमेशा क्यों नहीं? यदि पहली बार मिलने पर अच्छा प्रभाव छोड़ना मात्र नाटक है तो इस नाटक को बार-बार क्यों नहीं दोहराया जा सकता? अच्छाई अथवा अच्छा प्रभाव डालने के इस नाटक को इतनी बार दोहराइए कि वो जीवन की वास्तविकता बन जाए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो नुकसान नहीं लाभ ही होगा। हम अच्छी आदतों व व्यवहार के अभ्यस्त हो जाएंगे। यही मनुष्य का वास्तविक विकास व रूपांतरण है।

कई लोग मानते हैं कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव डालना संभव है, लेकिन रोज-रोज शिष्टाचार का पालन करना संभव नहीं है, अत्यधिक शिष्टाचार से जीवन में सहजता नहीं रहती, व्यवहार में एक कृत्रिमता-सी आ जाती है।

हमें हर हाल में हमेशा ही अपने अच्छे व्यवहार से लोगों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहिए और इसके लिए स्वयं को महत्व न देकर जो व्यक्ति हमें ये अवसर उपलब्ध करवाते हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस तरह के आचरण से घर-परिवार और समाज में एक नई चेतना का उदय संभव है।

व्यवहार के प्रति सतर्क रहे

जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसका अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। उस समय हम पूर्ण शिष्टाचार का पालन करते हुए चेहरे पर मुस्कान भी बनाए रखते हैं। साथ ही भावों के अनुरूप हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अत्यंत अनुकूल व सकारात्मक बनी रहती है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा मिलना-जुलना आम हो जाता है हम न केवल इन सब बातों की परवाह करना छोड़ देते हैं अपितु कई बार उपेक्षात्मक तरीके से भी पेश आने लगते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के स्वभाव, वास्तविकता अथवा कमियों को जान लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। हमें इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। हमें दूसरों के दोष अथवा कमियां देखने के बजाय अपने व्यवहार के बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिए। हमारा स्वयं का अच्छा व्यवहार हमारे विकास में सहायक होता है न कि दूसरों का अच्छा व्यवहार। हम अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं दूसरों के व्यवहार के लिए नहीं। लेकिन अपना व्यवहार बदल कर निश्चित रूप से दूसरों को बदलने का अवसर ही प्रदान करते हैं। दूसरों के व्यवहार के कारण हमारा व्यवहार बदल न जाए इसके लिए भी अनिवार्य है कि हम हर व्यक्ति से हर बार ये सोचकर ही व्यवहार करें जैसे आज पहली बार उससे मिल रहे हैं। इससे न केवल संबंधों में आत्मीयता बनी रहेगी अपितु लगातार सकारात्मक रहने के कारण मिलने वाले लाभ भी हमें अनायास ही मिल जाएंगे। जब हम किसी को दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं तो इससे हमें स्वाभाविक रूप से व्यायाम का लाभ मिलता है। मुस्कराकर किसी का स्वागत करते हैं तो ध्यान लगाने का लाभ मिलता है। बार-बार हमारी मनोदशा सकारात्मक होने के साथ हम स्वस्थ व तनावमुक्त भी रहते हैं। यानी नकारात्मकता और तनाव को दूर करने का यह आसान और बिना खर्च का एक सरल तरीका भी है।

स्वागत-सत्कार में प्रसन्नता

यदि हम किसी का स्वागत-सत्कार करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और यदि हम हर मिलने वाले का हर बार हर, रोज मन से स्वागत-सत्कार करेंगे तो हमारी प्रसन्नता में वृद्धि ही होगी। यही प्रसन्नता हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना अच्छा प्रभाव डालने के लिए उस समय न केवल अच्छे से अच्छे कपड़े-जूते पहनते हैं, अपितु सही तरीके से भी पहनते हैं। शेविंग वगैरा भी ठीक से करते हैं। हाथों व पैरों के नाखूनों का ध्यान रखते हैं। इन सब बातों का सामने वाले पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा प्रभाव हमेशा के लिए बना रहे तो हमें इन आदतों को स्थाई रूप से अपना लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारा बाह्य व्यक्तित्व निखरता है। जहां तक किसी से पहली बार मिलने का प्रश्न है जब भी हम किसी से मिलते हैं हर बार वो एक नया क्षण ही होता है। हर क्षण ही नया नहीं होता अपितु हर क्षण हर व्यक्ति भी पूर्ण रूप से नया व्यक्ति ही होता है। क्योंकि हम हर क्षण परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हर बार इस परिवर्तित नए व्यक्ति से मिलते समय हम उस पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ने का प्रयास करें तो सचमुच हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति पर हमारा फर्स्ट इंप्रैशन अथवा पहला प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा तो हमें तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति पर हमारी सही छवि अंकित न हो जाए। जब हर हाल में लोगों पर अपेक्षित अच्छा प्रभाव छोड़ना महत्वपूर्ण है तो फर्स्ट इंप्रैशन अथवा पहले प्रभाव को चिरस्थाई बनाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी होगा इसमें संदेह नहीं।

यह भी सच है

अमूमन देखा और सुना जाता है कि अरे उस लड़के को देखों क्या जोकर वाले कपड़े पहने हैं, लगता है उसे फैशन की समझ नहीं है। अरे मैंने कल उसके भाई से बात की थी, लगता है उसे कम बोलना पसंद है या वो बात करते हुए लड़कियों की तरह शर्माता है...। इस तरह के जुमले सभी अपने आसपास सुनते ही होंगे, लेकिन एक ही नजर में

- **यदि पहली बार मिलने पर अच्छा प्रभाव छोड़ना मात्र नाटक है तो इस नाटक को बार-बार क्यों नहीं दोहराया जा सकता? अच्छाई अथवा अच्छा प्रभाव डालने के इस नाटक को इतनी बार दोहराइए कि वो जीवन की वास्तविकता बन जाए।**
- **जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो अच्छी तरह से उसका अभिवादन करते हैं, उस समय हम पूर्ण शिष्टाचार का पालन करते हुए चेहरे पर मुस्कान भी बनाए रखते हैं, साथ ही भावों के अनुरूप हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अत्यंत अनुकूल व सकारात्मक बनी रहती है।**

किसी को जज कर लेना भी सही आदत नहीं है? इसलिए किसी को समझने के लिए मुद्दे की बात से पहले कुछ देर इधर-उधर की बातें करना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान को अच्छे से समझने के लिए सिर्फ 4 मिनट की इधर-उधर की बातें भी काफी हो सकती हैं। सिर्फ चार मिनट में ही आप सामने वाले के व्यक्तित्व, मिजाज और यहां तक कि उसके आईक्यू लेवल (बौद्धिक स्तर) को भांप सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रैशन इज द लास्ट इंप्रैशन। लेकिन सामने वाले को समझने के लिए खुद को वक्त देना भी जरूरी है। क्योंकि पहली बार में आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, आदर सत्कार करें, कितना भी झुककर नमस्कार करें इन सब को देखकर किसी के बारे में कोई राय बना लेना कितना सही है और कितना गलत। यह आप के आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है।

समीक्षा

अस्पताल की दर्दभरी कहानी में नवजीवन

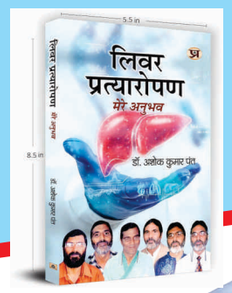

15 वर्षों में मैं अपने जीवन को पिछले 50 वर्षों के जीवन की तुलना में कहीं आगे देखता हूं, सच तो यह है कि प्रत्यारोपण के बाद जितनी शीघ्रता से मैंने स्वास्थ्य-लाभ पाया, उसने सचमुच मुझे एक आलौकिक ऊर्जा दी, अब मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे समाज के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करने यानी रक्तदान व अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने का माध्यम बनाया है।

डॉ.अरुण कुकसाल
ग्राम चामी, पौड़ी गढ़वाल

लिवर प्रत्यारोपण-मेरे अनुभव' मेरे 23 वर्षों के संघर्षपूर्ण, किंतु सफल जीवनकाल का छोटा सा आख्यान है। इसे आमजन के सम्मुख प्रस्तुत करने का मेरा मंतव्य केवल इतना है कि इसे पढ़कर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क तो रहे हीं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को यथासंभव अंगदान कर नवजीवन भी दे सकें। इस भ्रांति का निराकरण भी हो सके कि अंगदान से दानकर्त्ता को कोई शारीरिक क्षति या असहजता होती है, ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान या अंगदान करने के लिए आगे आएं। मैं स्वयं और मुझे अपने लिवर का अंशदान देने वाला मेरा पुत्र, दोनों ही एक स्वस्थ और संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इन 15 वर्षों में मैं अपने जीवन को पिछले 50 वर्षों के जीवन की तुलना में कहीं आगे देखता हूं। सच तो यह है कि प्रत्यारोपण के बाद जितनी शीघ्रता से मैंने स्वास्थ्य-लाभ पाया, उसने सचमुच मुझे एक आलौकिक ऊर्जा से अनुप्राणित कर दिया है। अब मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे समाज के अन्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करने तथा आमजन को रक्तदान व अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा देने का माध्यम बनाया है। यह किताब लेखक डॉ. अशोक कुमार पंत के उक्त विचारों के पीछे उनके जीवनकाल के संघर्षों की गाथा है। साथ ही यह किताब उनके इस जीवनकाल की विकटता की सुखद परिणिति की सफल कहानी है। इस किताब के बहाने, हमारे समाज और उसकी व्यवस्थाओं की गहनता से बहुआयामी पड़ताल भी उजागर हुई है। जिन्हें, जानना और समझना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उत्तराखंड राज्य में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं लेखन के माध्यम से विज्ञान लोकप्रियकरण, विज्ञान संचार, लोक साहित्य, लोक संस्कृति के अध्येयता के रूप में डॉ.अशोक कुमार पंत (जन्मतिथि- 18 अप्रैल, 1958) एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। सामाजिक योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय व प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। 'एसेसमेंट एंड स्टेटस ऑफ टेरिडोफाइट डायवर्सिटी इन मिलम (नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व) में पीएच.डी, डॉ. अशोक कुमार पंत वर्तमान में 'मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पिथौरागढ़ के चेयरमैन, 'पहल' संस्था और 'विज्ञान परिचर्चा' पत्रिका के वैज्ञानिक सलाहकार के बतौर सामाजिक दायित्वशीलता में सक्रिय हैं।

पुस्तक के 7 अध्याय

'लिवर प्रत्यारोपण-मेरे अनुभव' पुस्तक में डॉ. पंत ने अपने अनुभवों और विचारों को 7 अध्यायों में व्यापकता और गहनता से अभिव्यक्त किया है। ये 7 अध्याय हैं- 'प्रारंभिक लक्षण और उपचारात्मक त्रुटियां', 'सिरोसिस का आक्रमण', 'चिंता और चिंतन' 'ऑपरेशन और एमओटीयू', 'चांद से जमीन पर', 'कुछ उपलब्धियां', 'पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट-मेरी जीवनचर्या'। पुस्तक के 7 अध्यायों में डॉ. पंत ने अपने जीवन के विगत 23 वर्षों के विविध पड़ावों की विश्लेषणात्मक जानकारी पाठकों को दी है। इसमें उद्देश्य यह है कि उनके निजी जीवन से उपजी ये जानकारियां वैज्ञानिक संचेतना के माध्यम से सामाजिक शिक्षण और जागरूकता का माध्यम बने। निश्चित रूप में वे इसमें सफल भी रहे हैं। वास्तव में, इस किताब की कहानी केवल अशोक जी की ही नहीं है। वरन, देश-दुनिया में उन असंख्य लोगों की है, जो अभावग्रस्त व्यवस्थाओं और अज्ञानी चिकित्सकों के कारण अपने जीवन में अकारण ही आजीवन कष्ट भोगने को अभिशप्त हो जाते हैं। यह पुस्तक बताती है कि, फरवरी, 2001 से डॉ. पंत को उनके नए जीवनीय संघर्षों की आहटों ने सचेत करना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप में उसके बाद से उनकी दिनचर्या ने उपलब्ध एवं समुचित चिकित्सकीय सुविधाओं और सलाहों के अनुसार नया आकार लिया। परंतु, खेदजनक यह है कि आने वाले 8 वर्षों तक उन्होंने चिकित्सकीय और उपचारात्मक त्रुटियों के दुष्परिणामों को अपने जीवन में वे-बजह सहन किया। लेकिन देर से ही सही चिकित्सकीय लापरवाही का यह क्रम 4 जनवरी, 2009 को थमा जब उन्होंने 'लिवर प्रत्यारोपण' ऑपरेशन का सफल मुकाम हासिल किया।

डाक्टरों का अल्प-ज्ञान

वर्षों से चली आ रही तकलीफ का राज खुल गया कि मुझे अल्सर है ही नहीं। मैं लिवर की गंभीर बीमारी से गुजर रहा था। मुझे लिवर सिरोसिस एवं पोर्टल हाइपरटेंशन था, जो अत्यंत गंभीर तथा लाइलाज जैसा था। पूर्व में सही बीमारी का पता न चलने तथा गलत इलाज होने के कारण अब मौत मेरे दरवाजे खटखटा रही थी। मैंने जूस पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पूर्व डायग्नोसिस के आधार पर मुझे डायबिटिक घोषित किया गया था।

मैं लिवर की गंभीर बीमारी से गुजर रहा था, मुझे लिवर सिरोसिस एवं पोर्टल हाइपरटेंशन था, जो अत्यंत गंभीर तथा लाइलाज जैसा था, पूर्व में सही बीमारी का पता न चलने तथा गलत इलाज होने के कारण अब मौत मेरे दरवाजे खटखटा रही थी।

इन वर्षों में मेरी स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। संपर्क में आए डाक्टरों ने अपने अल्प-ज्ञान से मुझे यहां तक पहुंचा दिया था। मेडिकल सुविधाओं का अभाव, क्षेत्र का पिछड़ापन, अज्ञानता और लापरवाही पहाड़ों में कितनों की जान की दुश्मन बनी हुई है। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक नहीं हूं। आज मैंने लगभग 4 साल बाद पुनः मीठा लेना आरम्भ कर दिया था। वास्तव में यह किताब आज की दंभभरी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक सामान्य व्यक्ति की वास्तविक स्थिति और उसके असाधारण संयम, सकारात्मकता एवं साहस से हासिल स्फूर्तिदायक नवजीवन से पाठकों का साक्षात्कार कराती है। मौत' शब्द मस्तिष्क में दूर-दूर तक भी नहीं आया, केवल कर्तव्य व समन्वय ही मुझे खींचता गया और मुझे लगा कि अभी मेरे मन-मस्तिष्क में उलझनों से ग्रसित विचारों का पानी हिल रहा है, धीरे-धीरे पानी शांत होगा तथा अपने-अपने घनत्व के अनुसार सभी चीजें क्रम से रुकेंगी और तब यह मिश्रण शायद सुंदर दिखाई पड़े! इस किताब के प्राक्कथन में डा. राकेश बलूनी ने लिखा है कि 'अस्पताल एक दर्दभरी कहानियों की किताब है।' इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा जा सकता है कि 'अस्पताल' दर्दभरी कहानियों की किताब के साथ नवजीवन का मातृ स्थल भी है।' और, इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है जीवन जीने के प्रति दृढ़-इच्छशक्ति जो हमारे लेखक और नायक डॉ. अशोक कुमार पंत के व्यक्तित्व में नैसर्गिक तौर पर जीवंत रही है।

ऑपरेशन थिएटर का अनुभव

'वह बोले-'वेरी गुड पेशेंट', मुझे हंसी आ रही थी कि पेशेंट भी क्या वेरी गुड! दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया था। मैंने कहा कि आप लोग फिर कभी इस ऑपरेशन थिएटर में तो घुसने नहीं देंगे। मैं आया हूं तो एक बार सब चीजें देखना व समझना चाहता हूं, फिर कहां मौका मिलेगा? डाक्टर व अन्य लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिसकी जिंदगी अंतिम चरण में हो, सब कुछ अनिश्चित हो, उसे यह सूझ रहा है! लेकिन डाक्टर साहब ने मेरी बात मानी और मेरे अनुरोध पर सारे उपकरणों और मशीनों के बारे में संक्षेप से समझाया। सामने गोल शीशे की खिड़की से दिल्ली का मनोहारी दृश्य दिखाई पड़ रहा था। मैं स्वयं को एक वीवीआईपी महसूस कर रहा था।' यह किताब जीवन की जटिलताओं को 'परे हट' कहकर जीवन को सार्थक रूप में जीने की ओर प्रेरित करती है। जीवनीय विसंगतियों से उभरकर जीवनीय व्यवहारिता को अपनाने के कई प्रसंग इस पुस्तक में हैं। यानी क्या मेरे लिए इतनी महंगी जिंदगी की कोई सार्थकता है? क्या मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सार्थक हूं? ऐसी कुछ बातें घूम रही थीं मन में। यदि मैं ऑपरेशन न कराऊं तो भविष्य में बच्चे व समाज कहेगा कि पैसे खर्च न करने के कारण जवान व्यक्ति को नहीं बचाया गया। यह आक्षेप सीधे मेरी पत्नी पर लगेगा और उसे कोसा जाएगा। मन ने कहा कि नहीं, उसे आक्षेपों का शिकार न बनाया जाए। मन बोल उठा कि तेरी अभी जरूरत है।

बेटे का आत्मविश्वास

यह किताब बड़ी खूबसूरती से बताती है कि हमारा इस जीवन में होना हमारे पिता के होने से है। इस रचनाशीलता में पिता-पुत्र संबंधों पर यह एक बेहतरीन किताब है। हमारे मध्यमवर्गीय समाज में 18 वर्ष की आयु के उपरांत भी संतानों को बच्चा समझने की परिपाटी है। हमें लगता है समझदारी और जिम्मेदारी का भाव उनमें आने वाले वक्त में ही आएगा। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। लेखक अशोक के सुपुत्र शिवाशीष ने यह कर-दिखाया है। 4 जनवरी, 2009 को 18 वर्ष 6 माह का अभी जवान हुए शिवाशीष का डाक्टर से यह संवाद यही तो रेखांकित करता है...डाक्टर ने उसे कुछ डराने का प्रयास किया था तथा डांटकर पूछा था, जानते हो, तुम लिवर दान कर रहे हो? पता है तुम्हें क्या होगा? क्योंकि शिवाशीष मेडिकल साइंस का विद्यार्थी था तथा मैंने उसे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार कर दिया था, अतः उसने पूरे आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया-मैं मेडिकल का छात्र हूं और मैंने एनाटॉमी पढ़ी है। हां, मैं जानता हूं कि मेरे लिवर का एक हिस्सा काटकर पापा के लिवर के स्थान पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि लिवर में पुनर्जनन की क्षमता होती है, अतः कुछ ही दिन में मेरा लिवर पूरा बन जाएगा। डोनर के आत्मविश्वास भरे स्वर के कारण साइकेट्रिस्ट ने तुरंत ओके कर दिया। इस किताब का एक मजबूत पक्ष यह भी है कि इसने एक तरफ जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं समाज के तथाकथित शुभचिंतकों की पोल खोली है। अधिकांश, विपदा में आए व्यक्ति के साथ होने वाले सामाजिक व्यवहार बहुत ही कष्टकारी और अमानवीय भी होते हैं। सामान्य अनुभव बताते हैं कि ज्यादातर परिचित लोग औपचारिकता या उत्सुकतावश जानकारी लेने और अपनी सलाह देने के लिए रोगी

यह किताब आज की दंभभरी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक सामान्य व्यक्ति की वास्तविक स्थिति और उसके असाधारण संयम, सकारात्मकता एवं साहस से हासिल स्फूर्तिदायक नवजीवन से पाठकों का साक्षात्कार कराती है।

से मिलने आते हैं। उनका मरीज को सहयोग करने से ज्यादा अपनी उपस्थिति को दिखाना भर होता है। मुश्किल यह है कि ये लोग मरीज से ही उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। उनके लिए ये सब केवल एक सूचना है, जिसे अपने हिसाब से अन्य परिचितों में आगे प्रसारित करना वे अपना परम कर्तव्य मान लेते हैं।

सामाजिक ढकोसला

निश्चित रूप में यह सामाजिक तरीका बदलना चाहिए। व्यक्ति और परिवार की खुशी में तो आकर्षक भेंट देने का तो रिवाज है, परंतु उनके दुःख में आर्थिक मदद करने की निःसंकोच सामाजिक परिपाटी नहीं है। लगता है कि हम सभी सुख के साथी हैं, दुःख में मात्र कोरी सलाह देने के आदी हैं। अतः एक बीमार व्यक्ति और असहाय परिवार से कैसे वर्ताव किया जाना चाहिए? इसके लिए सामाजिक शिक्षण की जरूरत है। इस दिशा में लेखक अशोक पंत के अनुभवों से सीखा जा सकता है...। मुझे भीतर-ही-भीतर यह अनुभव हो रहा था कि विपत्ति में समाज की ओर देखना खुद को कमजोर करना है। खुद को देखा जाए तो व्यक्ति मजबूत होता है। मुझे इस बीच रवींद्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' में आई कविता 'विपदा मोरे रक्खा करो' की ये पंक्तियां याद आ रही थीं, 'हे ईश्वर! विपत्तियों से मेरी रक्षा कर, यह भाव लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूं। विपत्ति भरी अंधेरी रातों में जब पूरी दुनिया मेरा उपहास कर रही हो तो मैं तनिक भी विचलित न होऊं, इतनी शक्ति देना मुझे...।' वास्तव में मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था। शायद मेरी प्रार्थना सुनी जा रही थी और मैं रुग्णता की पराकाष्ठा, संसाधनों की विषमता, समाज का उपहास और भविष्य की प्रतिपल अनिष्चितता के दौर में स्वयं को खड़ा रख सका। यह किताब इसलिए भी रोचक है कि इसमें कई उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी सरलता और सहजता से पाठकों तक पहुंचती हैं। बीमार व्यक्ति एवं उसके परिवार के साथ डाक्टर एवं अस्पताल प्रशासन के अनुकूल तारतम्य के कई पाठ इस किताब में मौजूद हैं। मेरे लिए मजेदार बात यह भी है कि इसी किताब से पता चला कि जिगर-कलेजा का मतलब 'हृदय' नहीं वरन 'यकृत' याने लिवर होता है। यह शरीर के 400 से अधिक कार्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संचालित करता है। यह भी कि ट्रांसप्लांट के रोगी की अधिकतम आयु 10 वर्ष मानी जाती है। जिस मिथक को डॉ. अशोक पंत ने प्री एवं पोस्ट ट्रांसप्लांट के कड़े मानकों को आत्मसात करके निर्मूल सिद्ध किया है। डॉ. पंत ने जीवन के इस जटिल दौर में भी अपने पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन निर्बाध रूप में जारी रखा। आज भी इनमें वे निरंतरता बनाए हुए हैं। इस रूप में यह किताब मानव जीवन में 'अनुशासित जीवन-शैली' की मजबूती से पैरवी करती है।

यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून में 4 जनवरी, 2024 को पुस्तक 'लिवर प्रत्यारोपण:मेरे अनुभव (सफल लिवर प्रत्यारोपण के 15 वर्ष)' के लोकार्पण के अवसर पर प्रो. हेमचंद पांडे, कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने पिता डॉ. अशोक कुमार पंत को अपना लिवर का अंशदान करने वाले डा. शिवाशीष पंत को विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड राज्य में अंगदान-महादान अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया है। सामाजिक जागरूकता के दृष्टिगत यह एक सराहनीय पहल है। जिसके दूरगामी परिणाम हमारे समाज में प्रचलन में जरूर आएंगे। सार रूप में कहा जा सकता है कि डॉ. अशोक पंत के जीवन के अनुभवों पर लिखी पुस्तक 'लिवर प्रत्यारोपण: मेरे अनुभव' चिकित्सा विज्ञान और सामाजिक जागरूकता के संदर्भ और मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में सार्वजनिक हुई है। इस किताब को श्रीमती कंचन लता पंत, देवाशीष पंत, डा. शिवाशीष पंत, कमला पंत, डा. सुभाष गुप्ता, डा. दिनेश कुमार सिंघल, डा. मानव वधावन, डॉ. डीके पांडे, डा. राकेश बलूनी आदि ने अपने-अपने किरदारों में भावनात्मक एवं अपनी विषय विशेषज्ञता के उच्चतम समर्पण से समाजोपयोगी बना दिया है। हर एक का रोल काबिलेतारीफ है। वास्तविकता यही है कि समर्पित एकजुटता ही हमारे समाज को जीवंत बनाए रखती है। लेखक मित्र डॉ. अशोक कुमार पंत को नवजीवन एवं शानदार समाजोपयोगी पुस्तक लेखन की आत्मीय बधाई।

खतरे में प्राचीन वाद्ययंत्र

उत्तराखंड गठन के बाद पर्वतीय राज्य से लगातार पलायान हुआ, युवाओं के आधुनिकता की तरफ बढ़ते कदमों ने परंपरागत वाद्ययंत्रों के प्रति रुचि ही खत्म कर दी, जिससे इन वाद्ययंत्रों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है, लिहाजा उत्तराखंड के वाद्ययंत्रों का लुप्त होना लगभग निश्चित सा लगता है।

अफजल फौजी
नैनीताल

वाद्ययंत्रों का प्राचीन और वर्तमान संस्कृति से बहुत गहरा नाता रहा है। वाद्ययंत्रों के बिना संस्कृति की कल्पना करना ही बैमानी होगी। ये वाद्ययंत्र ही हैं जो अपने आधार से संगीत की आत्मा को दर्शाते और जगाते हैं। हिमालय का पर्वतीय अंचल उत्तराखंड पारंपरिक वाद्ययंत्रों का खजाना कहा जाता था, जिसकी बदौलत इस पर्वतीय अंचल का लोकगीत-संगीत और लोकनृत्य पारंपरिक तौर पर समृद्ध व विविधता से ओत-प्रोत रहा है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपरा में कई तरह के पौराणिक व प्राचीन वाद्ययंत्रों की फेहरिस्त रही है। प्राचीनकाल से ही उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के मांगलिक, मनोरंजन, रीति-रिवाजों, आंदोलनों, युद्ध, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व संचार कार्यों में तमाम प्रकार के वाद्ययंत्र बजाए जाते थे। धातुओं से निर्मित वाद्ययंत्रों में चिमटा, थाली, झाल, घुंघरू, मंजीरा, बिणाई, करताल, मोठंग, खजडी, घंटा, झांज, घन या घाना, तुरही, रणसिंहा, नागफणी, भंकोरा, झंकोर। लकड़ी व चमड़े से बने वाद्ययंत्रों में हुड़का, डौर, साइयां, ढोलकी, मशकबीन और तबला। धातु व चमड़े से बने दमाउ, डफली नगाडा और ढोल। बांस व रिंगाल से निर्मित अल्गोजा तथा बांसुरी। तार या तांत वाद्ययंत्रों में एकतारा, दो तारा, वीणा, और सारंगी। शेष नागफणी, वाद्ययंत्रों में गिटार, हार्मोनियम, आरगन तथा शंख शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के इन वाद्ययंत्रों से निकलने वाले अनोखे व निराले संगीत में कौतुहल से भरे प्रकृति के तमाम स्वरूपों का वास रहा है। पर्वतीय राज्य के इन वाद्ययंत्रों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है। देवभूमि की लोक संस्कृति में कई तरह के वाद्ययंत्रों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता पाई जाती है। लोकगीत में सुर, लय और ताल को वाद्ययंत्र ही नियंत्रित करते हैं, लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद जिस तरह से पर्वतीय राज्य से लगातार पलायान हुआ, युवाओं के आधुनिकता की तरफ बढ़ते कदमों ने परंपरागत वाद्ययंत्रों के प्रति रूचि ही खत्म कर दी। जिससे इन वाद्ययंत्रों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। एक तरह से समय के साथ उत्तराखंड के वाद्ययंत्रों का लुप्त होना लगभग निश्चित सा लगता है। हालांकि बहुत से वाद्ययंत्र तो कब के लुप्त भी हो चुके हैं।

प्राचीन वाद्ययंत्र चलन से बाहर

दुनिया भर में मशहूर प्राचीन ढोल वाद्ययंत्र उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़ा होने के साथ राज्य वाद्ययंत्र के तौर पर भी विख्यात रहा है। ढोल व दमाउ पर्वतीय अंचल के सबसे लोकप्रिय और मांगलिक वाद्ययंत्रों की श्रेणी में रहे हैं, जो विवाह, शादी, जागर, लोकनृत्य, रीति-रिवाजों के साथ आंदालनकारियों में जोश पैदा करते रहे हैं। इसलिए भी ये सबसे अधिक प्रचलित वाद्ययंत्र में हैं। जो पहाड़ी राज्य में हर शुभ कार्यों में उत्साह व उमंग बिखेरते नजर आते हैं। ढोल पर सबसे पहले बजाई जाने वाली मंगल बधाई ताल शुभ का प्रतीक मानी जाती है। ढोल वादन की अन्य तालौ में जागर की प्रमुख ताल को धुयाल ताल कहा जाता है। घुडया रासो व मंडाड ताल भी ढोल की मुख्य तालौ में गिनी जाती हैं। प्राचीन काल से निरंतर प्रचलित ढोल व दमाउ को ही उत्तराखंड के सुरक्षित वाद्ययंत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन आधुनिकता, भू-मंडलीकरण और डिजिटलकरण के इस दौर में अधिकतर पौराणिक व पारंपरिक वाद्ययंत्रों की जगह हल्के और आधुनिक वाद्ययंत्रों कम्प्यूटर, की-बोर्ड और सिंथेसाईजर ने ले ली है। एक ही यंत्र से सितार, संतूर, तबला तथा दर्जनों अन्य वाद्ययंत्रों की धुन बजाई जा सकती है। गीत और संगीत में रुचि रखने वालों को पाश्चात्य संगीत के वाद्ययंत्र गिटार, की-बोर्ड और ड्रम्स ज्यादा आकर्षित करने लगे हैं। तेजी से डिजीटल होते समाज में संगीत भी डिजीटल होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्राचीन वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल कम होने के कारण इन पहाड़ी वाद्ययंत्रों की मांग और उपलब्धता प्रभावित हुई है। प्राचीन वाद्ययंत्रों का संरक्षण न होने से भी ये वाद्ययंत्र चलन से बाहर होते जा रहे हैं, यानी इनका अस्तित्व ही दाव पर लगा हुआ है।

- **मध्यकाल में नागफणी का इस्तेमाल युद्ध के समय सेना के जवानों में जोश भरने के लिए किया जाता था, बाद में नागफणी का इस्तेमाल मेहमानों के स्वागत में किया जाने लगा, विवाह के दौरान भी इस वाद्ययंत्र का खूब प्रयोग किया जाता रहा है।**
- **डिजीटल होते समाज में संगीत भी डिजीटल हो रहा है, ऐसे में प्राचीन वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल कम होने से पहाड़ी वाद्ययंत्रों की मांग और उपलब्धता प्रभावित हुई है, प्राचीन वाद्ययंत्रों का संरक्षण न होने से भी ये वाद्ययंत्र चलन से बाहर होते जा रहे हैं।**

ढोल व दमाउ पर्वतीय अंचल के सबसे लोकप्रिय और मांगलिक वाद्ययंत्रों की श्रेणी में रहे हैं, जो विवाह, शादी, जागर, लोकनृत्य, रीति-रिवाजों के साथ आंदालनकारियों में जोश पैदा करते रहे हैं, इसलिए भी ये सबसे अधिक प्रचलित वाद्ययंत्र रहे हैं।

गायब हुई बांसुरी की धुन

वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड के वाद्ययंत्र वैंटीलेटर पर अंतिम सांस लेते नजर आ रहे हैं। इन वाद्ययंत्रों को बनाने वाले कुशल कारीगरों व बजाने वाले सिद्धहस्त वादकों की संख्या भी सिमट गई है। इस समय उत्तराखंड के हर शुभ कार्य में गीत-संगीत तो है, लेकिन सब आधुनिक। मनोरंजन के आयोजनों में हर वो आधुनिक वाद्ययंत्र प्रयोग हो रहे हैं जो देश भर में उपयोग किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के लुप्तप्राय प्राचीन वाद्ययंत्रों में बांस या मोटा रिंगाल से निर्मित मुरली या बांसुरी जो भी कहें, वो लोकगीतों खुदेड़ अथवा झुमैला गीतों तथा पशुचारकों द्वारा बजाई जाती थी जो लगभग लुप्त हो चुकी है। बांसुरी की धुन अब कहीं सुनाई नहीं देती, जबकि पहले पशु चराने वाले जब बांसुरी बजाते थे तब आसपास के बाकी पशु चराने वाले भी मस्ती में झूमने लगते थे। धातु से बना छोटा सा वाद्ययंत्र बिणाई पहाड़ की अधिकतर महिलाएं बजाती थी। बिणाई विभिन्न सुर-ताल के लिए अलग-अलग तरह से बनाई जाती थी। यह वाद्ययंत्र अब लुप्त हो चुका है। आज की पीढ़ी तो इस वाद्ययंत्र का नाम भी नहीं जानती है, इसके सुर और ताल सुनना उनके नसीब नहीं रहा है। हुड़का उत्तराखंड के लोकगीत व जागर में उपयोग किया जाने वाला वात यंत्र है। इसका उपयोग खेती कार्यों तथा युद्ध प्रेरक प्रसंगों में किया जाता रहा है। इस वाद्ययंत्र को बनाने वाले कुशल कारीगरों तथा बजाने वाले वादकों के अभाव में इस वाद्ययंत्र से निकलने वाली कर्णप्रिय गूंज के लुप्त होने से पहाड़ का यह लोकप्रिय वाद्ययंत्र अपना अस्तित्व लगभर खो चुका है।

संग्रहालयों में सिमटा नागफणी वाद्ययंत्र

उत्तराखंड के लोक वाद्ययंत्रों में एक नागफणी भी कभी प्रसिद्ध था। उत्तराखंड का यह एक ऐसा लोक वाद्ययंत्र था जो अब लुप्त हो चुका है। पहाड़ की नई पीढ़ी ने तो शायद कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। शिव को समर्पित कुमाऊं का यह महत्वपूर्ण लोक वाद्ययंत्र पहले धार्मिक समारोह के अलावा सामाजिक समारोह में खूब सुनाई देता था। लगभग डेढ़ मीटर लम्बे इस लोक वाद्ययंत्र में चार मोड़ होते हैं, कुछ नागफणी में यह चारों मोड़ पतली तार से बंधे होते थे। नागफणी का आगे का हिस्सा सांप के मुंह की तरह का बना होता है, इसी कारण इसे नागफणी कहा जाता है। नागफणी बजाने के लिए बेहद कुशल वादक की आवश्यकता होती है। तांत्रिक साधना करने वाले लोग आज भी इस नागफणी वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड के अलावा नागफणी गुजरात और राजस्थान में भी बजाया जाता है। दोनों ही राज्यों में इस वाद्ययंत्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अब इस वाद्ययंत्र को बजाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है, इसलिए अब कोई इसे बनाता भी नहीं है। हां पुराने संग्रहालयों में नागफणी वाद्ययंत्र आज भी देखने को जरूर मिल जाता है।

डौर थाली

डौर थाली उत्तराखंड के गढ़वाल का दूसरा प्रमुख वाद्ययंत्र है। डौर (डमरू) शिव का वाद्ययंत्र है। वादक ढोल की तरह डमरू को लाकड़ और हाथ से बजाता है। घुटनों के बीच डमरू को रखकर डौरिया डमरू बजाने वाला दाहिने हाथ से डौर पर शब्द करता है और बायें हाथ से शब्दोत्पत्ति में उंगलियों का संचार कर आवश्यक देवताओं की तालों की उत्पत्ति करता है। कांसे की थाली बजाने वाला बायें हाथ को उठाकर बायें अंगूठे पर थाली को टिकाता है और दायें हाथ से लाकुड़ थाली पर मारता है, जिससे डौर के शब्दों के अनुसार शब्द निकलते हैं। इसमें देवताओं का नर्तन होता है। डौर-थाली वादन केवल ब्राह्मण पुरोहित ही करते रहे हैं। इसको घड़ियाला या घड़ियालो भी कहते हैं। घड़ियाला देव शक्ति के आह्वान, नर्तन एवं पूजन के लिए ब्राह्मण या पुरोहितों के द्वारा जागर गाकर डौर थाली बजा-बजा कर सम्पन्न करता है। जागरी या घड़याल्या विशेष कर देव नृत्यों में देवताओं को नचाने और देवशक्ति के आह्वान के लिए ही डौर थाली बजाकर नृत्य करते हैं। कभी धर्याभूत, आंछरी, रणभूत और भूत नचाने के लिए भी घड़याल्या इनके जागर गाकर नृत्य कराता है। वाद्ययंत्रों की श्रृंखला से इस जमे-जमाए प्रचीन वाद्य का उपयोग बंद होने से इसके अस्तित्व पर पूर्णरूप से विराम लगता नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लोक आस्था के प्रतीक जागर में स्थानीय देवताओं को नचाने में इस वाद्ययंत्र का प्रयोग बड़े स्तर पर होता था।

सितार का सितारा अस्त

संगीत की दुनिया में अब धुनों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र सितार की जगह छोटे से कंप्यूटर साफ्टवेयर वीएसटी ने ले ली है। भारी भरकम तानपुरे की जगह रेडियोनुमा दिखने वाले इलैक्ट्रानिक तानपुरा ने कब्जा ली है। की-बोर्ड ने हार्मोनियम सहित कई दूसरे वाद्ययंत्रों की जगह ले ली है। यहां तक कि अमीरों व बड़े-बड़े संगीतकारों के सिंबल का प्रतीक रहे पियानो जैसे सबसे बड़े वाद्ययंत्र की जगह एक छोटे से रेडियोनुमा इलैक्ट्रानिक वाद्ययंत्र ने ले ली है। अस्तित्व खो चुके अनेकों वाद्ययंत्रों की धुनों को एक वादक की-बोर्ड की की-कंबिनेशन की सहायता से प्रभावशाली रूप से हू-बहू प्रस्तुत कर सकता है। बाजार भाव, सरलता व वादन की दृष्टि से अगर आधुनिक व प्रचीन वाद्ययंत्रों का तुलनात्मक रूप से अवलोकन करे तो एक इलैक्ट्रोनिक वाद्ययंत्र जो प्रचीन वाद्ययंत्रों से भार की तुलना में हल्का, लाने ले जाने व वादन में सरल तथा कीमत की तुलना में बीस-इक्कीस का ही आंकड़ा रखता है। इलैक्ट्रोनिक वाद्ययंत्र का सबसे बड़ा फायदा नजर आता है, एक वादक एक ही यंत्र से कई वाद्यों की धुन निकाल सकता है। आधुनिक वाद्ययंत्रों की सुगमता व बहुलता ही वो कारण माना जा सकता है जिसने प्राचीन वाद्ययंत्रों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के जनमानस का प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी यकीन रहा है, अंचल में प्रचलित प्रचीन वाद्ययंत्र दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत रहे हैं। वाद्य व वादक साधारण नहीं असाधारण रहे हैं। जहां भी इन वाद्ययंत्रों का वादन सिद्धहस्त वादकों द्वारा किया गया, वाद्यों की ध्वनि से उस स्थान व वहां के जन में सकारात्मकता का वास हुआ है। नकारात्मक जन नाचते देखे गए हैं। सिद्धहस्त वादकों द्वारा वाद्ययंत्रों का वादन कर समय-समय पर जनजागरण कर सकारात्मकता की राह दिखाई गई है। देवभूमि में देवताओं का आह्वान पारंपरिक तौर पर प्रचीन वाद्ययंत्रों के द्वारा ही किया जाता रहा है, जो आज विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। इस समय उत्तराखंड की जो दशा व दिशा चलायमान है। अनेकों प्रकार की भयावह विपदाओं से जो हा-हा कार मचा हुआ है। दिव्य प्रचीन वाद्ययंत्रों के संरक्षण की पहल को नजर अंदाज करने से उन वाद्यों पर जो विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, इसे देवभूमि के परिपेक्ष मे सकुन कहा जाए या अपसकुन? समझा जा सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति के वाहक रहे प्रचीन वाद्ययंत्रों को लुप्त होने से बचाने के लिए उत्तराखंड के निवासियां को चाहिए कि वो दिव्य वाद्ययंत्रों के संरक्षण के लिए आगे आए। सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि देवभूमि उत्तराखंड की सामाजिक व सांस्कृतिक को बचाया जा सके।

खतरा

थोड़ी-थोड़ी पिया करो...

हिमालय बचाओ की चेतना यदि विकसित होगी तो उसका नुकसान राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, माफियाओं, कंपनियों व तकनीशियनों को होगा है, क्योंकि इन लोगों का तो मकसद सिर्फ प्राकृतिक संपदा को लूटकर हिमालय को बर्बाद करना है।

उदयभान सिंह
लेखक

उत्तराखंड में कुछ आंदोलन चर्चित रहे हैं। मसलन उत्तराखंड राज्य, चिपको, भू कानून और नशा नहीं रोजगार दो, जैसे आंदोलनों में जाने और उसमें नए-नए छंद जोड़कर सड़कों पर गाए जाने से यह संपूर्ण हिमालयी समाज का आत्मनिवेदन बन गया। 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान यह नारा बहुत सुनने को मिलता था...मंडुवा-झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में देवी के रूप में हिमालय में नंदा देवी के अनेक नाम हैं जैसे देवी, काली, कालिंक्या, नंदा, शाकम्बरी और चंद्रवदनी आदि। तदनुसार विभिन्न नामों से शक्तिपीठ बने हैं। इन्हीं नामों की परंपरा में पार्वती नंदा कहलाती है और हर वर्ष भाद्रपद में नंदाष्टमी-राधाष्टमी को नंदाजात, नंदापाती, नंदा देवी, आठूं इत्यादि नामों से यात्रा, मेले, खेल, बलि, पूजा इत्यादि अनुष्ठान होते हैं। हिमालय बचाओ से ऐसा लगता है कि हिमालय बचाओ कह दिया, तो हिमालय बच जाएगा। हिमालय बचाओ का नारा देने वाली उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को यह बताने की कोई कोशिश नहीं की कि आप अपने स्कूल, कालेज, शहर, गांव, गांव के जंगल, जल स्रोत, खनिज संपदा तथा प्राकृतिक संपदा को बचा लेते हैं तो हिमालय खुद बच जाएगा। अगर यह समझाने से हिमालय बचाओ की चेतना यदि विकसित होगी तो उसका कुठाराघात राजनीतिज्ञों, नेताओं, नौकरशाहों, माफियाओं, कंपनियों व तकनीशियनों पर होना है, क्योंकि इन लोगों का तो अस्तित्व ही प्राकृतिक संपदा को लूट कर हिमालय को बर्बाद करना है। इसलिए ऐसे लोग इस बात से बचते रहते हैं कि उत्तराखंड का वास्तविक अर्थ लोगों की समझ में आए। यही लोग उत्तराखंड बचाओ की शपथ का ढकोसला कर उत्तराखंड के रहनुमा बन जाते हैं। उत्तराखंड में शराब की खपत का आंकड़ा शराब के जाम में डूबा हुआ है। आंकड़ों की दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शराब पीना प्रतिबंधित नहीं है। यहां सिर्फ त्यौहारों पर ही नहीं, बल्कि आम दिनों में भी खूब शराब पी जाती है। भारत में जहां प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 4.3 लीटर शराब पीता है, वहीं शीर्ष दस देशों में एक व्यक्ति साल में औसतन 15 लीटर शराब पीता है। इनमें से ज्यादातर देश यूरोपीय हैं, जहां ठंड सालभर रहती है और उससे बचने के लिए लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। सबसे कम खपत कुवैत में है, जहां शुद्ध अल्कोहल की खपत सबसे कम 0.005 लीटर है। अल्कोहल प्रेम में भारत का दर्जा दुनिया के अन्य कई देशों से बहुत ऊपर है। विश्व में हमारी खुशहाली का सूचकांक भले ही गिर रहा है लेकिन शराब की खपत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2005 से 2016 के बीच यह खपत दोगुनी हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि व्यसन से व्यक्ति को मानसिक तनाव, असंतोष और हताशा होती है। इसके कारणों की पड़ताल खुशहाली के विश्व सूचकांक से करनी चाहिए। दुनिया के 155 देशों में हम नीचे खिसककर 133वें पायदान पर आ गए हैं, जबकि एक साल पहले हमारी जगह 122वीं थी। यदि आम आदमी बेचैन और परेशान है तो जाहिर है कि वह राहत की तलाश में शराब जैसे नशे का आसान सहारा तलाशता है। उसके लिए पैसा भी चाहिए। भारत जैसे देश में राज्य सरकारें अपने शाही खर्च पूरे करने के लिए शराब पर भारी-भरकम टैक्स लगाती है। ऐसे में सस्ती शराब गरीब के लिए वरदान बन जाती है। इसी कमजोरी का फायदा पैसे के लिए जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले उठाते हैं।

हरिद्वार भी शराब की चपेट में

केंद्र सरकार मानती है कि हर साल 2 से 3 हजार के बीच नशेड़ी जहरीली शराब के कारण जीवन से हाथ धो बैठते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर वही दारुण त्रासदी दोहराई गई है। दोनों राज्यों में जहरीली व सस्ती शराब ने 110 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया और कमोवेश इतने ही बीमार हुए हैं। यह जहरीली शराब उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार के क्षेत्र में बनी थी और एक पारिवारिक उत्सव के मौके पर मेहमानों को परोसी गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि हर थोड़े अंतराल पर लगातार होने वाली ऐसी घटनाएं निकम्मे प्रशासन, भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों की याद दिलाती है। लेकिन हमदर्दी और दिखावटी कानूनी कार्रवाई से आगे हम कभी जा ही नहीं पाते हैं। मौत का यह दुष्चक्र बदस्तूर यूं ही जारी रहता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसा ही हादसा 2015 में मुंबई के मालवणी में हुआ था, जिसमें 106 मजदूर सस्ती शराब पीने से जान गंवा बैठे थे। यदि उस इलाके में जाकर देखा जाए तो वहां आज भी वहां सस्ती व नकली शराब बनते मिल जाएगी। निकम्मे प्रशासन और लचर कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाले ऐसे हादसों के तत्काल बाद सरकारी मशीनरी छापे और तलाशी अभियान चलाती है। ज्यादा कोशिश किए बिना ही वह नकली जहरीली शराब बनाने वाले ठिकानों तक पहुंच जाती है और सैकड़ों हजारों लीटर जानलेवा शराब नष्ट करने की तस्वीरें लेकर वाहवाही के लिए जनता के सामने आ खड़ी होती हैं। अंधाधुंध गिरफ्तारियों के साथ ही कुछ दिन के लिए जहर के ये सौदागर ओझल हो जाते हैं और जैसे ही जनता का रोष कम होने लगता है, वे फिर धंधा शुरू कर देते हैं। हमारे शासकों की कर्तव्यहीनता और गैरजिम्मेदाराना रवैये पर इससे ज्यादा शोचनीय टिप्पणी और क्या हो सकती है! इस प्रकरण में सबसे जरूरी सवाल यह है कि सरकारें विभागीय जवाबदेही क्यों तय नहीं करती? अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी के लिए सभी प्रदेशों में अलग विभाग कार्यरत हैं। ऐसे हादसों के सामने आने पर इन विभागों से न केवल जवाब-तलब किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था शायद इन आंकड़ों से खुश हो सकती है कि दुनिया में शराब का सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा आयातकर्ता भारत है। हालांकि देश में बहुत बड़े पैमाने पर कारखानों में शराब का उत्पादन होता है। ऐसे बड़े कारखानों की संख्या 10 है। इनमें तैयार की जाने वाली शराब का 70 प्रतिशत देश में ही सुरा प्रेमियों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर भी ज्यादा सस्ता और आसान नशा मुहैया कराने के लिए शराब के नाम पर जहरीले पदार्थ से तैयार शराब बेचा जाना आम है, जो कभी न कभी जानलेवा बन जाती है। देश के नौ राज्य ऐसे हैं, जहां का 70 प्रतिशत हादसों से दो-चार होना पड़ता है। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक गुजरात और तेलंगाना शामिल हैं। ऐसी घटनाएं शराब बंदी वाले गुजरात और बिहार में भी सामने आ चुकी हैं, हालांकि व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई।

विश्व में हमारी खुशहाली का सूचकांक भले ही गिरा है लेकिन शराब की खपत में तेजी से आगे बढ़ा है, 2005 से 2016 के बीच यह खपत दोगुनी हो चुकी है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि व्यसन से व्यक्ति को मानसिक तनाव, असंतोष और हताशा होती है।

पहाड़ी जिले पीने में अव्वल

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी एम्स की ऋषिकेश शाखा में शराब के दुष्प्रभाव तथा प्रमाण पर आधारित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता विषय पर चर्चा हुई। पहले दिन देश के बड़े डॉक्टरों ने उत्तराखंड में शराब की खपत के बारे में बताया। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने शराब से स्वास्थ्य, समाज और देश पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर व्याख्यान दिए। बताया गया कि कांफ्रेंस में चिकित्सा विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर शराब के बढ़ते प्रचलन को कम करने के लिए राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे एनएएमएस केंद्र सरकार को सौंपेगी। तीन दिवसीय कंटीन्यू मेडिकल एजूकेशन (सीएमई) अकादमी के अध्यक्ष सीएस भास्करानंद ने बताया कि शराब पीने से लीवर, आंत, मांसपेशियों, ब्रेन आदि को नुकसान के साथ व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। यहां प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में उत्तराखंड से आगे केवल दिल्ली है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति शराब की खपत वाल राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शराब के विरोध के बीच आबकारी विभाग की सारी उम्मीदें पहाड़ से ही टिकीं हैं। आंकड़े बताते है कि प्रदेश के पांच पहाड़ी जिलों में की खपत उम्मीद से ज्यादा है, जबकि मैदानी जिलों में विदेशी शराब के दिवाने थोड़े कम हैं। मार्च में पूरे हुए वित्त वर्ष से पहले राज्य का आबकारी विभाग अपने रेवेन्यू टारगेट का 2650 करोड़ रुपये का करीब 70 प्रतिशत ही पूरा कर पाया है। उत्तराखंड सरकार के लिए शराब, कमाई का बड़ा जरिया है। लिहाजा तमाम विरोध के बीच भी सारा फोकस शराब पर रहता है। आंकड़े बताते हैं कि पांच जिलों टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शराब पीने के मामले में अव्वल हैं। अल्मोड़ा में पिछले साल नवंबर तक 58 फीसदी ज्यादा शराब गटकी गई। वहीं अन्य चार जिलों में अंग्रेजी शराब के शौकीनों की तादाद 28 से 38 फीसदी के बीच बढ़ी है। मैदानी जिलों में ऊधमसिंह नगर जिले में पिछले साल के मुकाबले 2 फीसदी अंग्रेजी शराब की खपत बढ़ी है, जबकि देहरादून में ये 17 फीसदी के आसपास है।

सस्ती शराब के नाम पर जहरीले पदार्थ से तैयार दारु बेचना आम है, जो कभी न कभी जानलेवा बन जाती है, देश के नौ राज्य ऐसे हैं, जहां का 70 प्रतिशत हादसे होते हैं, इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना शामिल हैं।

गांव में देशी शराब को प्रमुखता

उत्तराखंड में शराब का विरोध हमेशा स्पॉटलाइट में रहा है। अप्रैल में जब सरकार नई आबकारी पॉलिसी लेकर आई तो विरोध इस कदर बढ़ गया कि कई जगह दुकानें नहीं खुल पाईं, लेकिन धन कमाने को बेताब विभाग ने कुछ गाड़ियों को चलती फिरती दुकान में तब्दील कर लिया जो पहाड़ में अभी भी दिख जाती हैं। देश में सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। जहां एक साल में औसतन प्रति व्यक्ति 34.5 लीटर शराब इस्तेमाल की खपत है। कीमती या सस्ती शराब का ताल्लुक पीने वाले की कमाई और उसके रहन-सहन पर निर्भर करता है। शहर में कुछ बेहतर किस्म की और गांव में देशी शराब को प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाताहै। जाने-माने गजल गायक स्व.पंकज उधास ने कोई दो दशक पहले गाया था 'कि हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी-थोड़ी पिया करो...' लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। शराब की वजह से भारत में हर साल करीब 2.60 लाख लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि 2005 से 2016 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2005 में देश में जहां प्रति व्यक्ति अल्कोहल की खपत 2.4 लीटर थी, वहीं 2016 में यह बढ़ कर 5.7 लीटर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्कोहल के कुप्रभाव की वजह से जहां हिंसा, मानसिक बीमारियों और चोट लगने जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, वहीं कैंसर व ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वस्थ समाज की राह में सबसे गंभीर खतरा बनती शराब पर अंकुश लगाने की सिफारिश की है। शराब के ज्यादा सेवन से दो सौ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा शराब पीने वालों में टीबी, एचआईवी और निमोनिया जैसी बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेडरोस आधानोम गेब्रेयेसुस का कहना है, शराब के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और वर्ष 2010 से 2025 के बीच इसकी वैश्विक खपत में 10 फीसदी की कटौती का लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सदस्य देशों को लोगों का जीवन बचाने के लिए अल्कोहल पर टैक्स बढ़ाने और इसके विज्ञापन पर पाबंदी लगाने जैसे रचनात्मक तरीकों पर विचार करना चाहिए।

शराब का तीसरा बड़ा बाजार भारत

भारत दुनिया में शराब का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहां अल्कोहल यानी शराब उद्योग सबसे तेजी से फलने-फूलने वाले उद्योगों में शामिल है। शराब उद्योग के जानकार मानते हैं कि युवावर्ग में शराब पीने की बढ़ती लत इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सूचना तकनीक समेत कई क्षेत्रों में युवाओं को शुरुआती नौकरियों में मिलने वाली भारी भरकम सैलरी और तेजी से विकसित होती पब संस्कृति ने इसे बढ़ावा दिया है। यह उद्योग काफी लचीला है। शराब के विभिन्न ब्रांडों की कीमतें बढ़ने के बावजूद न तो उनकी मांग कम होती है और न ही लोग पीना कम करते हैं। उल्टे लोग कम कीमत वाले दूसरे ब्रांडों का सेवन करने लगते हैं। एक गैर-सरकारी संगठन के प्रमुख दिलीप मोहंती कहते हैं। बंगलुरू, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में आईटी उद्योग में आने वाली क्रांति और बेहतर वेतन-भत्तों की वजह से अब युवाओं के एक बड़े तबके के पास काफी पैसा है। सप्ताह में पांच दिनों की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद सप्ताहांत के दो दिन वे अपने मित्रों के साथ इन पैसों को पबों या बार में उड़ाते हैं। देश में हाल के वर्षों में अल्कोहल निर्माता कंपनियों की भी बाढ़ सी आ गई है। हर महीने बाजार में कोई न कोई नया ब्रांड आ जाता है। मोहंती कहते हैं देश में शराब की खपत बढ़ने की मुख्यतः दो वजहें हैं, जागरूकता की कमी और उपलब्धता।

आलेख

मेडिकल टूरिज्म और उत्तराखंड

पियौरागढ़ मेडिकल कालेज को मेडिकल टूरिज्म के लक्ष्य को लेकर निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को विकसित किया जाना चाहिए। विदेश की तुलना में भारत में इलाज सस्ता है। कारपोरेट के चिकित्सालय इसी का लाभ उठा रहे हैं।

कमल कांत शर्मा

उत्तराखंड को पिछड़ा और संसाधनविहीन राज्य कहना सरासर गलत और अमूल्य प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न देवभूमि का अपमान है। उत्तराखंड को प्रकृति ने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मुक्तहस्त से दिया है। भीड़भाड़ और शोरगुल से निजात पाने के लिए पर्वतीय चोटियों, घाटियों और शांत वन क्षेत्र के प्रदूषणमुक्त वातावरण से आकर्षित होकर सैलानी आते हैं। इसी लिए पर्यटन को सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित कर देने से उत्तराखंड को पिछड़ा कहा जाता है। अलग राज्य का गठन होने के बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, लेकिन चारधाम के अलावा देवभूमि के अन्य धर्मस्थलों को विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया। राज्य में मेडिकल टूरिज्म की अच्छी संभावनाएं हैं। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक भी यह स्वीकार करते हैं कि प्रदूषण रहित वातावरण में उन्हें शुद्ध प्राणवायु से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अनेक लोग देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेश से भी उत्तराखंड आते हैं।

योगगुरु बाबा रामदेव द्वारा हरिद्वार में स्थापित पतंजलि पीठ में योगाभ्यास और आयुर्वेदिक चिकित्सा से असाध्य रोगियों को स्वस्थ किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज और धनाढ्य परिवार स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्वतीय और वन क्षेत्र के अनुकूल मौसम में रहने के लिए आते थे। विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं। वन क्षेत्र में जड़ी-बूटियों व विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के सम्पर्क से गुजरने वाली वायु से अनेक रोग स्वतः खत्म हो जाते थे। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद मेडिकल कालेज और कारपोरेट समूह के बड़े अस्पताल स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज को मेडिकल टूरिज्म के लक्ष्य को लेकर निर्मित करने का निर्णय किया है। इसी तरह राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को विकसित किया जाना चाहिए। विदेश की तुलना में भारत में इलाज सस्ता है। इसी लिए मेदांता, अपोलो, फोर्टिस आदि कारपोरेट अस्पतालों में विदेश से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन कारपोरेट के अस्पताल महानगरों के प्रदूषित वातावरण में हैं। यदि उत्तराखंड में चिकित्सा की आधुनिक व्यवस्था वाले अस्पताल स्थापित होंगे तो स्वच्छ वातावरण में लोग इलाज को प्राथमिकता देंगे। मेडिकल टूरिज्म से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी विकसित होगा। अस्पताल में इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए हरेभरे वातावरण में लोग रहना चाहेंगे तो होटल एवं होम स्टे का व्यवसाय भी विकसित होगा। अलग-अलग तरह का कारोबार बढ़ने से पर्वतीय क्षेत्र से पलायन की समस्या का समाधान होगा। उत्तराखंड की छवि बदलेगी और पिछड़ा पर्वतीय राज्य की जगह मेडिकल हब तथा प्राकृतिक वातावरण से संपन्न राज्य का गौरव प्राप्त होगा।

लचर चिकित्सा व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण

मेडिकल हब बनने की अपार संभावना के बाद भी उत्तराखंड में चिकित्सा की लचर व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने पर कहा जाता था कि बड़ा राज्य होने से पर्वतीय क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे पाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा व नारायण दत्त तिवारी केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का प्रावधान किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ा होने का तर्क देकर पर्वतीय क्षेत्र की दो कमिश्नरियों कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य घोषित किया गया। राज्य बनने के करीब ढाई दशक बाद स्थिति जस की तस है। सरकार विकास के दावे और घोषणाएं करती रही है। पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों से लेकर बड़े शहरों में मेडिकल कालेजों तक अव्यवस्था का बोलबाला है। राज्य बनने के बाद नये अस्पताल और मेडिकल कालेज खोले गये, लेकिन डाक्टर पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहते हैं। मेडिकल कालेजों में भी डाक्टरों का टोटा है। कुमाऊं के सबसे बड़े महानगर हल्द्वानी के मेडिकल कालेज में फैकल्टी कभी पूरी नहीं रहती है।

कारपोरेट के अस्पताल महानगरों के प्रदूषित वातावरण में हैं। उत्तराखंड के स्वच्छ वातावरण में स्थापित अस्पतालों में लोग इलाज को प्राथमिकता देंगे। मेडिकल टूरिज्म से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यवसायियों का कारोबार विकसित होगा।

पर्वतीय क्षेत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के नहीं होने से मरीज भटकते रहते हैं। भावी डाक्टर बनने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाने वालों के पद रिक्त हैं। रुद्रपुर में मेडिकल कालेज सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रहा है। इसके बाद भी नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की जा रही है। नये मेडिकल कालेज खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु पहले से खुले मेडिकल कालेजों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। मेडिकल कालेज में फैकल्टी पूरी नहीं होने पर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। सिर्फ डिग्री देने से कोई अच्छा डाक्टर नहीं बन सकता है। हल्द्वानी मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ चिकित्सक अल्मोड़ा मेडिकल कालेज तबादला होने पर इस्तीफा देकर निजी प्रेक्टिस करने लगते हैं। डाक्टरों में सेवा भावना का अभाव है, जबकि डाक्टर को धरती पर भगवान की तरह सम्मान मिला है।

सीबीआई और ईडी क्यों नहीं करते जांच?

चिकित्सा को सेवा नहीं, मरीज को लूटने का धंधा समझने वालों का एक और मामला उजागर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सरकार द्वारा देशभर के अस्पतालों में आंखों के इलाज के लिए एक समान दरें तय करने के खिलाफ ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसायटी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि सभी निजी अस्पताल सरकार से सस्ती दरों पर जमीन लेते समय कहते हैं कि वे कम से कम 25 फीसदी बेड समाज के कम आय वर्ग के मरीजों को निशुल्क इलाज के लिए आरक्षित करेंगे, लेकिन जमीन लेकर अस्पताल बनाने के बाद, वे कभी ऐसा नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि क्या आप इस तरह की नीति को चुनौती दे सकते हैं? इस मामले से एक बार और यह साबित हो गया कि निजी अस्पताल सरकार से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेकर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाने और मरीजों से खिलवाड़ करते हैं। निजी अस्पताल भी उद्योग बन गये हैं। जिस तरह एक उद्योग समूह जगह-जगह सरकार से सस्ती जमीन लेकर फैक्ट्री स्थापित करके धनवान बनता जाता है, ठीक उसी तरह कई कारपोरेट अस्पतालों की शाखाएं बहुत कम समय में विभिन्न राज्यों में खुल जाती हैं। इतना धन अचानक कहां से आता है, यह आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी की आंखों को दिखाई नहीं देता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार तथा अन्य जगह सरकार से सस्ती जमीन लेकर निजी अस्पताल स्थापित किये हैं।

सरकारी महकमे व दवा कंपनियां बाधक

उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 औषधियों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बाबा रामदेव और आचार्य बाल कृष्ण द्वारा औषधियों के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। शीर्ष अदालत में पेश हलफनामे में प्राधिकरण ने कहा कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फटकार लगाने के बाद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को अपनी शक्तियों का अहसास हुआ। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि उत्तराखंड में एलोपैथी दवाओं के सैंपल अक्सर जांच में फेल होते हैं। नकली दवाओं का धंधा सरकारी महकमे की छत्रछाया में होता है। एलोपैथी की नकली दवाएं जानलेवा साबित होती हैं। साइड इफेक्ट होता है, जबकि आयुर्वेदिक दवा जानलेवा साबित नहीं होती है। उत्तराखंड को मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल हब बनने में संबंधित सरकारी महकमे बाधक साबित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों को किसी की जान जाने से कोई मतलब नहीं है तो देवभूमि की बदनामी से क्या लेना-देना। राज्य सरकार को मेडिकल कालेजों, सरकारी व निजी अस्पतालों को सुधारने के साथ ही उच्च मानक के अनुरूप दवाओं के उत्पादन तथा उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

भवाली का टीबी सेनेटोरियम

भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था, तब ट्यूबरक्यूलोसिस यानि टीबी एक लाइलाज बीमारी थी, जिसका ठीक हो पाना बेहद मुश्किल था, उस दौरान नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर दूर भवाली में एक ऐसा अस्पताल बनवाया गया था, जहां टीबी का इलाज किया जाता था। इस अस्पताल का नाम था टीबी सेनेटोरियम भवाली। घने चीड़ के जंगल के बीच स्थित अस्पताल में टीबी मरीजों का इलाज किया जाता था। चीड़ के पेड़ों से छनकर आने वाली हवा को मरीजों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जाता है। यही वजह थी कि भारत के कोने-कोने से आने वाले मरीजों के साथ ही कई नामी हस्तियों का भी इलाज किया गया था। वर्ष 1912 में टीबी सेनेटोरियम की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। यह उत्तर भारत का पहला टीबी का अस्पताल था। कैंसर की तरह टीबी का भी कोई इलाज नहीं था। टीबी के मरीजों को अलग से रखा जाता था। साथ ही इन मरीजों को छूने और उनके पास जाने से भी लोग बचते थे। भवाली सेनेटोरियम में बेहतर इलाज होता था। टीबी से दुनिया के कई देशों में हजारों लोग मारे जा रहे थे। टीबी सेनेटोरियम में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू भी 1935 में भर्ती रही थीं। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद थे, ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा की जेल में शिफ्ट किया गया, जहां से वह कमला नेहरू को देखने के लिए भवाली सेनेटोरियम में आते थे। सुभाष चंद्र बोस को जब ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था तो उन्हें भी यहां भेजा गया। प्रख्यात क्रांतिकारी और साहित्यकार यशपाल, गायक कुंदन लाल सहगल, खिलाफत आंदोलन के मोहम्मद अली और शौकत अली भी यहां इलाज के लिए भर्ती हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की पत्नी का भी यहीं इलाज हुआ था। वर्ष 1912 में मरीजों के लिए 378 बेड की व्यवस्था थी। अब 112 साल बाद कई भवन टूट चुके हैं। बहुत कम बेड उपलब्ध हैं, जिनमें इलाज हो रहा है। समुद्र तल से 1731 मीटर की ऊंचाई पर 18 हेक्टेयर क्षेत्र में टीबी सेनेटोरियम को बनाया गया है। अंग्रेजों की हुकूमत के समय ट्यूबरक्यूलोसिस का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता था ऐसे में सबसे बड़ी चिंता फौज और पुलिस के सिपाहियों के बीमार होने के दौरान होती थी क्योंकि हजारों की संख्या में पूरी फौज एक साथ बीमार हो सकती थी। सेनेटोरियम में अलग से एक पुलिस वार्ड की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार ने जिस लाइलाज बीमारी से लड़ने के लिए इस सेनेटोरियम की स्थापना की थी, इसका जीर्णोद्धार करना तो दूर, प्रशासन यहां पहुंचाने वाली सड़क तक को बेहतर नहीं कर पाया है। टीबी अब लाइलाज नहीं है, लेकिन स्वच्छ आबोहवा और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में यहां पर बड़ा मेडिकल संस्थान स्थापित कर विदेशी और देश के अन्य राज्यों के मरीजों के लिए अनेक असाध्य रोगों के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। सेनेटोरियम का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और कोई भी बड़ा मेडिकल संस्थान यहां बनाया जा सकता है।

1. प्रकृति ने दिया स्वास्थ्यवर्धक वातावरण
2. ढांचागत चिकित्सा व्यवस्था का अभाव
3. लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, अन्य कारोबार का विकास
4. संसाधनविहीन राज्य कहना देवभूमि का अपमान

ओम प्रकाश की लव स्टोरी

ओमप्रकाश एक दिन पान की दुकान पर खड़े थे, तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओमप्रकाश से मिन्नतें करने लगी, ओमप्रकाश की आत्मकथा के मुताबिक महिला ने कहा कि वो विधवा हैं, उसकी चार बेटियां हैं सबसे बड़ी 16 साल की है वो मुझे दामाद बनाना चाहती थीं।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर और पांच दशक तक बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने वाले ओम प्रकाश ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से अच्छे-अच्छे कॉमेडियनों को भी पीछे छोड़ दिया था। उनका जन्म 19 दिसंबर 1919 को गुलाम भारत के लाहौर में हुआ था। ओमप्रकाश ने 12 साल की उम्र में क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उन्हें सगीत के अलावा थियेटर व फिल्मों में दिलचस्पी थी। ओमप्रकाश को 'दासी' फिल्म के जरिये फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मिला था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओमप्रकाश ने अपने करियर में आजाद, मिस मैरी, हावड़ा ब्रिज, दस लाख, प्यार किए जा, खानदान, साधु और शैतान, गोपी, दिल दौलत दुनिया, शराबी जैसी सुपर हिट फिल्म समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उनका किरदार पहले से जुदा होता था। वे डायरेक्टर भी रहे। राजकपूर और नूतन जैसे स्टार्स को लेकर भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्म का नाम था कन्हैया अपनी फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर पॉजिटिव रोल ही निभाए थे। एक्टर, डायरेक्टर के साथ ओम प्रकाश ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। ओमप्रकाश ने ही फिल्मों में गेस्ट रोल की शुरुआत की थी। उन्होंने 60 के दशक में फिल्म संजोग, जहांआरा और गेटवे आफ इंडिया जैसी फिल्में बनाईं। वो एक अच्छ सिंगर भी थे। कुछ समय तक ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। एक दिन वह अपने दोस्त की शादी में गए थे। वहां वह हंसी मजाक कर रहे थे, उसी दौरान एक प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली की नजर उन पर पड़ी और इसी दावत के बाद ओमप्रकाश को फिल्म 'दासी' से एक्टिंग की दुनिया में पहला चांस मिला। अपने करियर में ओमप्रकाश ने कई हिट फिल्मों में काम किया।

ओम प्रकाश की लव स्टोरी

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर की लव स्टोरी भी काफी दिलस्प है। रेडियो में काम करते हुए उनकी मुलाकात एक फैन से हुई थी, जो रेडियो स्टेशन में उनसे मिलने आया करती थी। लेकिन लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। मेरी मां उनके घर बात भी करने गई लेकिन उसके घरवाले नहीं मानें। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम प्रकाश की मां बीमार रहती थीं और वो चाहती थीं कि ओम प्रकाश जल्दी शादी कर लें। ओमप्रकाश एक दिन पान की दुकान पर खड़े थे, तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओमप्रकाश से मिन्नतें करने लगी। ओमप्रकाश की आत्मकथा के मुताबिक महिला ने कहा कि वो विधवा हैं और उसकी चार बेटियां हैं जिनमें सबसे बड़ी 16 साल की है। वो मुझे दामाद बनाना चाहती थीं। इस बारे में मेरी मां से भी उनकी बात हो चुकी थी। उन्होंने मेरे आगे अपना पल्लू फैलाया और विनती की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। फिर क्या था मैंने अपने प्यार को भुला दिया और उस विधवा महिला की बेटी से शादी कर ली। ओम प्रकाश 21 फरवरी, 1998 को दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है।

ओम प्रकाश रिश्ते में ऋतिक के नाना थे, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, लिहाजा जब ऋतिक छह साल के थे, तब उन्होंने अपने नाना की फिल्म आशा से फिल्मों में कदम रखा, इसके अलावा ऋतिक उनकी फिल्म आसपास और भगवान दादा में भी नजर आए थे।

सिर्फ 80 रुपये मिले थे पहली फिल्म के

लाहौर में पैदा होने वाले ओम प्रकाश अपने किरदारों की वजह से हिंदी सिनेमा में खूब लोकप्रिय थे। मात्र 12 साल की उम्र में ओमप्रकाश ने म्यूजिक की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। संगीत की पढ़ाई करते-करते 5 दशक बीत गए, फिर लंबे संघर्ष के बाद ओमप्रकाश ने बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरा। ओम प्रकाश ने दासी फिल्म से बड़े पर्दे पर शुरुआत की। बताया जाता है कि पहली फिल्म के लिए उन्हें महज 80 रुपये मिले थे। हालांकि एक फिल्म मिलने के बाद उन्हें कई सालों तक फिल्में नहीं मिली। इसलिए वो कठिन दौर से गुजरे, लेकिन निराश नहीं हुए और संघर्ष करते रहे। ओम प्रकाश की एक सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर फिल्म में अलग तरह से किरदार निभाते थे। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। ओम प्रकाश उस दौर के थे जब दुनिया बदल रही थी। लोगों में बहुत से अंधविश्वास, और सामाजिक विपन्नता व्याप्त थी।

ऋतिक के नाना थे ओम प्रकाश

ओम प्रकाश मानते थे कि काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। वैसे तो यह डायलॉग फिल्म थ्री इडियट्स का है और इसका ऋतिक रोशन से कोई कनेक्शन भी नहीं है। इसके बावजूद यह डायलॉग ऋतिक की जिंदगी से जुड़े एक शख्स पर बखूबी लागू होता है। यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि ऋतिक रोशन के नाना ओम प्रकाश थे, जो बेहतरीन कलाकार थे। साथ ही फिल्मकार के रूप में भी उनका कद काफी ऊंचा था। यूं कह लीजिए कि एक जमाने में ओमप्रकाश को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी का दूसरा नाम कहा जाता था। एक्टर ओम प्रकाश किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके पिता लाहौर के एक स्कूल में शिक्षक थे, लिहाजा ओम प्रकाश और पढ़ाई-लिखाई का नाता बचपन से ही काफी मजबूत रहा। जब देश आजाद हुआ तो वह मुंबई आ गए और कुछ कर गुजरने के लिए कमर कस ली। काफी कम लोग ही जानते होंगे कि ऋतिक रोशन और ओम प्रकाश का आपस में रिश्ता है। दरअसल ओम प्रकाश रिश्ते में ऋतिक के नाना थे। दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी। यही वजह थी कि जब ऋतिक छह साल के थे, तब उन्होंने अपने नाना की फिल्म आशा से फिल्मों में कदम रख दिया था। इसके अलावा ऋतिक उनकी फिल्म आसपास और भगवान दादा में भी नजर आए थे। ओमप्रकाश ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार ऋतिक ही करेंगे। आज की तारीख में भले ही ओम प्रकाश का नाम काफी नजाकत के साथ लिया जाता है, लेकिन किसी जमाने में ऐसा कतई नहीं था। वह न सिर्फ पहचान के मोहताज थे, बल्कि नाम कमाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। ओम प्रकाश जब मुंबई आए, तो उन्हें बतौर स्पॉट ब्वॉय काम करना पड़ा। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने स्पॉट ब्वॉय के रूप में भी काम किया है। फिल्मों में कई छोटे-मोटे काम किए, लेकिन हमेशा यह देखता रहा कि निर्देशक किसी दृश्य को कैसे फिल्मांकित करते हैं। इससे मैंने काफी कुछ सीखा। ओम प्रकाश ने बतौर डायरेक्टर आपकी कसम फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आखिर क्यों? (1985), अपनापन (1977), आशा (1980), अपना बना लो (1982), अर्पण (1983) और आदमी खिलौना है (1983) आदि फिल्में भी बनाईं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ओम प्रकाश की सभी फिल्मों के नाम अ अक्षर से ही शुरू होते थे और वह भगवान भोलेनाथ को मानते थे।

असल जिंदगी में भी एक्टिंग

बड़े पर्दे पर तो ओम प्रकाश अपनी एक्टिंग से धमाल मचाते थे ही, लेकिन असल जिंदगी में भी वह परिस्थितियों को देख कर अभिनय करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा सालों बाद भी काफी मशहूर है। जिसमें उन्होंने अंग्रेजी फौज को अपनी एक्टिंग से चकमा दे डाला था। दरअसल, यह बात उन दिनों की है जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था और भारत से फौजियों को भेजा जा रहा था। इसी दौरान अभिनेता ओमप्रकाश को भी किसी काम से रावलपिंडी जाना था। लाहौर से जब वह रेलगाड़ी में बैठने के लिए निकले तो उन्होंने देखा की ट्रेन तो फौजियों से भरी हुई है, लेकिन उनका काम इतना जरूरी था कि उन्होंने थर्ड क्लास में जाने के लिए टिकट ले ली। ट्रेन की टिकट मिली और ओम प्रकाश उस भरी ट्रेन में खुद के लिए जगह ढूंढने लगे। कड़ी मेहनत के बाद ओम प्रकाश पहली क्लास में पहुंच गए। जहां पहले से ही कुछ अंग्रेज फौजी अफसर सीटों को घेरे बैठे थे। इस दौरान गाड़ी भी पटरी से निकलने लगी। ओम प्रकाश को फर्स्ट क्लास में देख अंग्रेजी फौजी आपस में इंग्लिश में बातचीत करने लगे। वह इस कदर बात कर रहे थे जैसे कि वह ओम प्रकाश को उनकी हरकत के लिए ताना कस रहे हों। वहीं ओम प्रकाश को अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने उन अंग्रेजी फौजियों के सामने गूंगा होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। जिससे इज्जत बच गई और उस फर्स्ट क्लास में सफर करने को भी मिल गया। अभिनेता की गूंगे होने की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि कोई उनकी चलाकी को पकड़ नहीं पाया। यात्रा के दौरान उन्हें पीने और खाने का सामान भी मिलता रहा। जैसे ही ट्रेन रावलपिंडी के पास पहुंचने वाली थी तो तभी उनसे पूछा गया कि क्या वह जन्म से ही गूंगे हैं? अभिनेता ने उस सवाल का सिर हिलाकर ऐसा जवाब दिया कि लोग सोच में पड़ गए कि वह गूंगे हैं भी या नहीं? ओमप्रकाश का सफर तो अंग्रेजी फौजियों के साथ बड़ा ही शानदार तरीके से गुजरा, लेकिन उनकी एक्टिंग ने अंग्रेजों को दंग करके रख दिया था। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वह असल जिंदगी में भी खुद को एक्टिंग से ही मुश्किल समय से बचाते थे और यही वजह रही कि उन्होंने सालों तक बड़े पर्दे पर राज किया।

- **ओमप्रकाश ने अपने करियर में आजाद, मिस मैरी, हावड़ा ब्रिज, दस लाख, प्यार किए जा, खानदान, साधु और शैतान, गोपी, दिल दौलत दुनिया, शराबी जैसी सुपर हिट फिल्म समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।**
- **एक्टर, डायरेक्टर के साथ ओम प्रकाश ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया, ओमप्रकाश ने ही फिल्मों में गेस्ट रोल की शुरुआत की थी, उन्होंने 60 के दशक में फिल्म संजोग, जहांआरा और गेटवे आफ इंडिया जैसी फिल्में बनाई।**

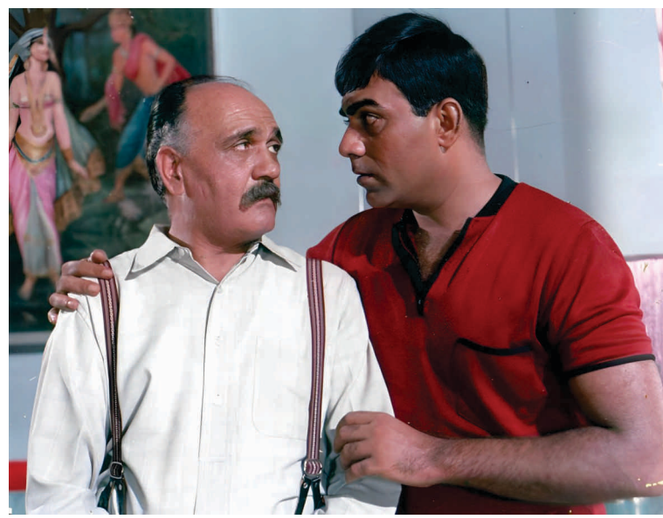

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह अतिआक्रामकता से बचिए, वाणी पर संयम अति आवश्यक है। साहस और पराक्रम निरंतर बनाए रखिए, यात्राओं से लाभ मिलेगा मित्रों से समागम के अवसर उपलब्ध होंगे। शत्रु निराश हैं और निराश ही रहेंगे, भागीदारी के कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण के योग हैं। पुरानी बीमारी में आराम मिलेगा।

वृषभः-

इस माह क्रोध करने से काम बिगड़ सकते हैं, पैरों में किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। मध्य माह में परिणाम अनुकूल होंगे। ऋण लेने का मार्ग सुगम होने जा रहा है। बुद्धि कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होगी पुराने रोग के उभरने की संभावना है। धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनिर्णय की स्थिति निर्मित होगी।

मिथुनः-

इस माह रक्तदान का अवसर मिल सकता है, पुण्य के इस मौके का लाभ अवश्य लीजिए। जीवनसाथी से तालमेल बनाने का प्रयास कीजिए। मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। घर में कोई सदस्य बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता कम होगी। ननिहाल के किसी व्यक्ति से मुलाकात संभव है। विरोधियों की खुराफातें बढ़ सकती हैं। जलीय रोगों के होने की संभावना प्रबल है।

कर्कः-

इस माह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन होने की प्रबल संभावना है। आर्थिक लाभ का प्रचुर अवसर उपलब्ध होगा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा धैर्य से काम लीजिए। संचार माध्यम से कोई आनंददायक सूचना मिलेगी। अनावश्यक क्रोध आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। असत्य भाषण से बचने का प्रयास कीजिए। गुमराह होने से बचें।

सिंहः-

इस माह अचानक कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। भाग्य प्रबल रहेगा, सम्मान बढ़ेगा। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। सहयोगियों की संख्या में वृद्धि होगी। मन पसंद भोजन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से मेल मिलाप के अवसर प्राप्त होंगे। अकारण क्रोध को टालें वरना आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। वाणी संयमित रखने से आपके रुके काम बनने का योग प्रबल है।

कन्याः-

इस माह लम्बी दूरी की यात्रा होगी, खर्च में अचानक वृद्धि होगी। सीने का पुराना रोग की उभरने की संभावना बन रही है। पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा। मान सम्मान में वृद्धि के अवसर हैं। आलस्य से काम बिगड़ सकते हैं किसी कारण से अस्पताल जाने की संभावना है। लाभ के प्रचुर अवसर मिलेंगे मनपसंद नौकरी मिलेगी। जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखना आवश्यक है।

तुलाः-

इस माह ललित कलाओं में अचानक रुझान बढ़ेगा, जीवनसाथी से तालमेल बैठाए रखना कठिन होगा। मनपसंद उपहार की प्राप्ति संभव है। मेडिटेशन कर सकते हैं। मनमुताबिक परिणाम मिलने में संदेह रहेगा। घर से दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ज्यादा ठंडा पेय पदार्थ का उपयोग न करें तकलीफ बढ़ सकती है, आप मेहनती हैं और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पा सकेंगे।

वृश्चिकः-

इस माह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ज्यादा व्यसन आपकी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पीठ की तकलीफ बढ़ सकती है। खरीददारी के लिए बाहर जा सकते हैं। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। आपकी मनोकामना की पूर्ति संभव है, किसी कारण से अस्पताल जाने की संभावना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करें।

धनुः-

इस माह आप जिस मानसिक बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं उससे निकलने में अभी कुछ समय और लगेगा। स्वाभाविक परिवर्तन आपके लिए आगे चलकर सुखद होगा। बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। पिता व भाई से किसी प्रकार की मदद मिल सकती है। व्यापार और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आलस्य बढ़ने की संभावना है जो हानि के योग बनाएगा।

मकरः-

इस माह अनिर्णय की स्थिति रहेगी, संभल कर चलिए, मुंह के बल गिर सकते हैं। खर्चों से पार पाना मुश्किल होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। किसी धर्म गुरु से मुलाकात होने की संभावना है। ससुराल के लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी गलत विधि से धन आपके हाथ में आएगा। न्यायालय में विचाराधीन किसी प्रकरण में विजय मिलने के योग प्रबल हो रहे हैं। सावधानी बरतें।

कुंभः-

इस माह धन लाभ के अत्याधिक अवसर प्राप्त होंगे। बड़े भाई के सहयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे जिससे हिम्मत बढेगी, संचार माध्यम से धन अर्जित करेंगे। धार्मिक यात्रा होगी। ससुराल के लोगों से मुलाकात हो सकती है। अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मास के अंत से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीनः-

इस माह रुका हुआ धन प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वाणी पर संयम रखें। यात्रा की प्रबल संभावना है। यात्रा में अपने सामान का ध्यान जरूर रखें। रोमांटिक मूड में रहेंगे एवं घूमने फिरने जा सकते हैं। भाग्य की वजह से कई रुके काम बन सकते हैं। कोई शत्रु अनायास ही सामने आ सकता है। वाहन आदि का प्रयोग सावधानी से करें। दुर्घटना में चोट आदि का भय रहेगा।